epaper.dehatsandesh.com

3 डोगरी संस्था जम्मू ने किया डॉ. निर्मल विनोद की चार पुस्तकों का विमोचन

5 डायमंड लीग के अंतिम चरण में भाग नहीं लेंगे नीरज चोपड़ा

8 वृक्षों और वनों का संरक्षण

मौसम जम्मू — न्यूनतम 22 — अधिकतम 28

E-mail: dehatsandesh@gmail.com

देहात संदेश

जम्मू-कश्मीर का एकमात्र ग्रामीण दैनिक

वर्ष-22, जम्मू तवी, अंक-207 | जम्मू तवी, शुक्रवार 22 अगस्त, 2025 | मूल्य-3 रूपये- (लेह)4 रूपये | पृष्ठ -8

लोकसभा और राज्यसभा अनिश्चितकाल के लिए स्थगित, हंगामे की भेंट चढ़ा मानसून सत्र

नई दिल्ली, 21 अगस्त। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही गुरुवार को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी गई, जिसके साथ ही संसद का 21 दिवसीय मानसून सत्र समाप्त हो गया। अंतिम दिन भी कई बार कार्यवाही स्थगित हुई और विपक्षी दलों ने बिहार एसआईआर और कथित वोट चोरी के खिलाफ अपना विरोध प्रदर्शन जारी रखा। शुरूआच से ही यह संत्र हंगामेदार रहा। पहले दिन से ही इस एसआईआर को लेकर विपक्ष ने जबरदस्त हंगामा शुरू किया जो आखिरी दिन तक भी जारी रहा। दोनों सदनों की कार्यवाही लगातार बाधित होती रही। हालांकि, ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के दौरान दोनों सदनों में हंगामा कम देखने को मिला। लोकसभा की कार्यवाही लोकसभा की बैठक बृहस्पतिवार को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई जिसमें 12 विधेयकों को बिना चर्चा के या संक्षिप्त चर्चा के साथ पारित किया गया। लोकसभा अध्यक्ष ने मानसून सत्र में कार्यवाही में गतिरोध बनाए रखने पर विपक्षी दलों के प्रति निराशा प्रकट करते हुए कहा कि नियोजित तरीके से सदन के कामकाज में

लोकसभा की बैठक बृहस्पतिवार को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई जिसमें 12 विधेयकों को बिना चर्चा के या संक्षिप्त चर्चा के साथ पारित किया गया।

सत्र के दौरान जहां बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन परीक्षण (एसआईआर) के मुद्दे पर चर्चा को लेकर विपक्ष के भारी हंगामे के कारण लगातार गतिरोध बना रहा

व्यवधान पैदा किया गया जो लोकतंत्र और सदन की मर्यादा के अनुरूप नहीं है। अठारहवीं लोकसभा के पांचवें सत्र की शुरुआत 21 जुलाई को हुई थी जिसमें 14 सरकारी विधेयक पेश किए गए और 12 विधेयक पारित किए गए। इनमें अनुसूचित जनजातियों के विधानसभा क्षेत्रों के पुनर्समायोजन से संबंधित गोवा विधेयक2025, मर्चेंट शिपिंग विधेयक 2025, मणिपुर वस्तु एवं सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2025, मणिपुर विनियोग (संख्या 2) विधेयक 2025, राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक 2025 और राष्ट्रीय एंटी-डोपिंग (संशोधन) विधेयक 2025शामिल हैं। इनके अलावा आयकर विधेयक 2025, कराधान कानून (संशोधन) विधेयक 2025, भारतीय बंदरगाह विधेयक 2025, खनिज और खनिज विकास (विनियमन और संशोधन) विधेयक 2025, भारतीय प्रबंधन संस्थान (संशोधन) विधेयक 2025 और ऑनलाइन खेल संवर्धन और विनियमन विधेयक, 2025भी हंगामे के बीच लोकसभा में पारित किए गए। लोकसभा ने प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्रियों और मंत्रियों को गंभीर आपराधिक आरोपों में गिरफ्तार किए जाने और लगातार 30 दिन तक हिरासत में रहने पर पद से हटाए जाने के प्रावधान वाले 'संविधान (130वां संशोधन) विधेयक, 2025', 'संघ राज्य क्षेत्र शासन (संशोधन) विधेयक, 2025' और 'जम्मू कश्मीर पुनर्गठ्म (संशोधन) विधेयक, 2025' को संसद की संयुक्त समिति को भेजने का निर्णय लिया। सदन में 28 और 29 जुलाई को ऑपरेशन सिंदूर पर विशेष चर्चा बिना किसी व्यवधान के पूरी हुई जिसका जवाब प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने दिया। राज्यसभा का 268वां सत्र बृहस्पतिवार को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया और सत्र के दौरान जहां बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन परीक्षण (एसआईआर) के मुद्दे पर चर्चा को लेकर विपक्ष के भारी हंगामे के कारण लगातार गतिरोध बना रहा, वहीं हंगामे के बीच कई महत्वपूर्ण विधेयकों को संक्षिप्त चर्चा के बाद पारित करवाया गया।

राष्ट्रपति पुतिन से मिले विदेश मंत्री जयशंकर

मॉस्को, 21 अगस्त ।। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने गुरुवार को मॉस्को में रूसके राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की। रूसी राष्ट्रपति कार्यालयसे जारी बयान के अनुसार, इस बैठक में रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव, रूस के प्रथम उपप्रधानमंत्री और भारत-रूस अंतर-सरकारी आयोग(व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग) के रूसीहिस्से के अध्यक्ष डेनिस मांटुरोव तथा रूस में भारत के राजदूत विनयकुमार भी मौजूद रहे। एस जयशंकर ने अपने एक्स पोस्ट में लिखा, आजक्रेमलिन में राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात कर सम्मानित महसूस किया। मैंनेराष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हार्दिक शुभकामनाएंउन्हें प्रेषित कीं। मैंने उन्हें प्रथम उपप्रधानमंत्री डेनिस मांटुरोव और विदेशमंत्री सर्गेई लावरोव के साथ हुई अपनी चर्चाओं से अवगत कराया। वार्षिकशिखर सम्मेलन की तैयारियां तेज़ी से

आगे बढ़ रही हैं। वैश्विक परिदृश्यऔर यूक्रेन पर हालिया घटनाक्रम को लेकर उनके विचार साझा करने कीसराहना करता हूं। इससे पहले जयशंकर ने रूसी विदेश मंत्री सर्गेईलावरोव से मुलाकात कर द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने पर विस्तृतचर्चा की। दोनों नेताओं ने यूक्रेन, यूरोप, ईरान, पश्चिम एशिया, अफगानिस्तान और भारतीय उपमहाद्वीप से जुड़े मुद्दों पर भी विचार साझाकिए। जयशंकर ने 'एक्स' पर पोस्ट करते हुए कहा, फआज मॉस्को मेंविदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से मिलकर खुशी हुई। हमारे बीच व्यापार, निवेश, ऊर्जा, उर्वरक, स्वास्थ्य, कौशल व गतिशीलता, रक्षा और लोगों सेलोगों के बीच संबंधों पर विस्तृत चर्चा हुई। हमने यूक्रेन, यूरोप, ईरान, पश्चिम एशिया, अफगानिस्तान और भारतीय उपमहाद्वीप पर विचारसाझा किए। साथ ही, संयुक्त राष्ट्र, जी20, एससीओ और ब्रिक्स मेंसहयोग पर भी बातचीत हुई। हमारी बैठक ने इस वर्ष के अंत में होने वालेवार्षिक शिखर सम्मेलन के लिए परिणामों और निर्णयों को तैयार करने मेंमदद की।फरूसी विदेश मंत्रालय के बयान के अनुसार, दोनों नेताओं नेअंतरराष्ट्रीय व्यवस्था को मजबूत करने और ग्लोबल साउथ के देशों कोउनकी राजनीतिक संप्रभुता की रक्षा में सहयोग देने की आवश्यकता परबल दिया। उन्होंने राजनीतिक संपर्कों को और आगे बढ़ाने, व्यापार औरआर्थिक सहयोग को गहरा करने, सतत परिवहन व लॉजिस्टिक श्रृंखलाओंतथा वित्तीय चैनलों को मज़बूत करने और शांतिपूर्ण परमाणु ऊर्जा वहाइड्रोकार्बन उत्पादन के क्षेत्र में साझेदारी का विस्तार करने पर भी चर्चाकी। वार्ता की शुरुआत में लावरोव ने कहा कि भारत और रूस एक-दूसरेको फविशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारफ मानते हैं और मौजूदावैश्विक परिदृश्य में बहुध्रुवीय व्यवस्था के निर्माण में दोनों देशों कीभूमिका महत्वपूर्ण है। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र, जी20, ब्रिक्स और एससीओजैसे मंचों पर सहयोग को और मजबूत करने की आवश्यकता पर जोरदिया।

सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी हबीबुल हसन बेग 1997 के भ्रष्टाचार मामले में दोषी करार

श्रीनगर, 21 अगस्त। माननीय अतिरिक्त विशेष न्यायाधीश, भ्रष्टाचार निरोधक न्यायालय, श्रीनगर ने पी/एस वीओके (वर्तमान एसीबी) श्रीनगर के एफआईआर संख्या 22/1997 के मामले में एक अभियुक्त, सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी हबीबुल हसन बेग, तत्कालीन सदस्य, विशेष न्यायाधिकरण, जम्मू-कश्मीर सरकार को एक वर्ष के कारावास और 15 लाख जुर्माने की सजा सुनाई है। माननीय अतिरिक्त विशेष न्यायाधीश, भ्रष्टाचार निरोधक न्यायालय, श्रीनगर फैजान-उल-हक इकबाल ने एक निर्णय सुनाया, जिसमें माननीय न्यायाधीश ने एक अभियुक्त, सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी हबीबुल हसन बेग, तत्कालीन सदस्य, विशेष न्यायाधिकरण, जम्मू-कश्मीर सरकार, पुत्र घ. हसन बेग, निवासी चिनार कॉलोनी, बरजुल्ला, श्रीनगर को पुलिस स्टेशन वीओके (अब एसीबी श्रीनगर) के एफआईआर नंबर 22/1997 के तहत एक साल की कैद और 15 लाख जुर्माने की सजा सुनाई गई है।

मामला एफआईआर नंबर 22/1997, यू/एस 5(1)(ई), 5(2) पी.सी. एक्ट 2006 के तहत जो जम्मू-कश्मीर लोक सेवक संपत्ति घोषणा एवं अन्य प्रावधान अधिनियम 1983 की धारा 12/14 के साथ है, 24-04-1997 को पुलिस स्टेशन वीओके (अब एसीबी श्रीनगर) में इस आरोप के तहत दर्ज किया गया था कि उक्त लोक सेवक ने अपनी सेवा के दौरान चल/अचल संपत्ति के रूप में भारी संपत्ति अर्जित की है।

मुख्यमंत्री उमर द्वारा आपदा प्रभावित किश्तवाड़ और कठुआ में राहत और पुनर्वास प्रयासों की समीक्षा

श्रीनगर , 21 अगस्त। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने किश्तवाड़ और कठुआ जिलों में हाल ही में बादल फ टने और अचानक आई बाढ़ से प्रभावित लोगों के लिए चल रहे राहत और पुनर्वास उपायों की समीक्षा हेतु एक बैठक की अध्यक्षता की।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को संबोधित करते हुए त्वरित राहत सहायता, आवश्यक सेवाओं की बहाली और संवेदनशील क्षेत्रों को बार-बार होने वाली प्राकृतिक आपदाओं से बचाने के लिए दीर्घकालिक रणनीतियों की आवश्यकता पर बल दिया।

मुख्यमंत्री ने कहा, चाहे वह बादल फटना हो या हिमनद झील का विस्फोट, सच्चाई यही है कि यह त्रासदी चशोती गाँव में साल के सबसे व्यस्त समय में हुई। अगर यह किसी और समय हुआ होता, तो शायद इसका असर इतना गंभीर नहीं होता। ये ऐसे सबक हैं जिन्हें हमें आगे ले जाना चाहिए।

मौसम विभाग ने अनावश्यक यात्रा के खिलाफ सलाह सहित चेतावनियाँ जारी की थीं, जो अत्यधिक संवेदनशील क्षेत्रों के लिए स्पष्ट मानक संचालन प्रक्रिया और दिशानिर्देश अपनाने के महत्व को रेखांकित करता है।

उन्होंने कहा कि अल्पकालिक प्राथमिकताएँ राहत और पुनर्वास पर ही बनी रहनी चाहिए, जबकि मध्यम और दीर्घकालिक उपायों में विशेषज्ञों द्वारा संवेदनशील क्षेत्रों का समग्र मूल्यांकन, कृषि भूमि की सुरक्षा, बाढ़-प्रवण नालों के किनारे बस्तियों को हतोत्साहित करना और निवारक तंत्र का निर्माण शामिल होना चाहिए।

चल रहे बचाव कार्यों के बारे में, मुख्यमंत्री ने कहा फदुर्भाग्य से, 33 लोग अभी भी लापता हैं, इसलिए यह मान लेना उचित होगा कि हम उनमें से किसी को भी जीवित नहीं पाएँगे। अब हमारी प्राथमिकता शवों को निकालकर उनके परिवारों को सौंपना है। उन लोगों का पुनर्वास करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है जिनके घर और आजीविका तबाह हो गए हैं।

उन्होंने क्षतिग्रस्त घरों के पुनर्निर्माण, कृषि भूमि की बहाली और आवश्यक सेवाओं के प्रावधान में हर संभव सरकारी सहायता का आश्वासन दिया। उन्होंने संबंधित विभागों को निर्देश दिया कि वे प्रभावित क्षेत्रों में सड़क संपर्क पूरी तरह से बहाल होने तक बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए जनरेटर की व्यवस्था सहित अस्थायी व्यवस्था करें।

जम्मू-कश्मीर सरकार ने एफएसएसएआई के नियमों का सख्ती से पालन करने का दिया आदेश

श्रीनगर, 21 अगस्त । जम्मू-कश्मीर सरकार ने गुरुवार को फोजन मीट, चिकन और अन्य मांस उत्पादों के संचालन, भंडारण, पैकेजिंग और बिक्री के संबंध में भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) के नियमों का सख्ती से पालन करने के आदेश जारी किए और उल्लंघन की स्थिति में गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी दी। हाल ही में कश्मीर में एक सनसनीखेज मामला सामने आया जब अधिकारियों ने अनधिकृत और अपर्याप्त भंडारण सुविधाओं से सैकड़ों किलो सड़ा हुआ मांस बरामद किया।इस खुलासे ने समाज को झकझोर कर रख दिया कि घाटी में इसका पर्दाफाश होने से पहले यह व्यापार संभवत: कई वर्षों से चल रहा था। जम्मू-कश्मीर खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने एक सार्वजनिक सूचना जारी कर सभी खाद्य व्यवसाय संचालकों के लिए फोजन कच्चे मांस, चिकन और मांस उत्पादों के संचालन, भंडारण, पैकेजिंग और बिक्री के संबंध में दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन करना अनिवार्य कर दिया है। एफडीए आयुक्त ने अधिसूचना में कहा कि ये निर्देश सभी निर्माताओं, प्रसंस्करणकर्ताओं, थोक विक्रेताओं, खुदरा विक्रेताओं, कोल्ड स्टोरेज संचालकों, ट्रांसपोर्टरों के साथ-साथ मांस उत्पादों की बिक्री या वितरण में लगे ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर भी लागू होते हैं नोटिस में स्पष्ट रूप से चेतावनी दी गई है कि उचित और पूर्ण लेबलिंग के बिना पैकेज्ड फोजन मीट या चिकन की बिक्री प्रतिबंधित है और उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

संदिग्ध ड्रोन देखे जाने पर सुरक्षा बलों ने शुरू किया तलाशी अभियान

जम्मू, 21 अगस्त। गुरुवार को जम्मू जिले के गजनसू सीमावर्ती इलाके में स्थानीय लोगों ने एक संदिग्ध ड्रोन देखा जिसके बाद सुरक्षा बलों ने तलाशी अभियान शुरू कर दिया है।

उन्होंने बताया कि निवासियों ने गुरुवार को गजनसू सीमा क्षेत्र में सुरक्षा एजेंसियों को इसकी सूचना दी। अधिकारियों ने बताया कि पुलिस और अन्य सुरक्षाबलों ने तुरंत इलाके में तलाशी अभियान शुरू कर दिया।

एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि अभी यह स्पष्ट नहीं है कि ड्रोन इस तरफ से आया था या सीमा पार से। मामले की जाँच जारी है।

संभागीय आयुक्त पुलिस महानिरीक्षक जम्मू ने कठुआ के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया

कठुआ 21 अगस्त। संभागीय आयुक्त जम्मू रमेश कुमार और पुलिस महानिरीक्षक जम्मू बीएस टूटी ने कठुआ जिले के बादल फटने और अचानक आई बाढ़ से प्रभावित भूस्खलन प्रभावित इलाकों का व्यापक दौरा किया ताकि स्थिति का आकलन किया जा सके और चल रहे राहत एवं पुनर्वास कार्यों की समीक्षा की जा सके।

सिडको घाटी में स्थापित राहत शिविर में संभागीय आयुक्त ने जोड क्षेत्र के प्रभावित परिवारों से मुलाकात की जहाँ हाल ही में आई आपदा में पाँच लोगों की जान चली गई थी। उन्होंने विस्थापित परिवारों

से बातचीत की, जानमाल के नुकसान पर गहरी चिंता व्यक्त की और संवेदना व्यक्त की। उन्होंने पीड़ितों को सरकार की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया और बताया कि जिला प्रशासन द्वारा राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (एसडीआरएफ) के तहत तत्काल वित्तीय सहायता प्रदान की जा चुकी है। उन्होंने कठुआ के उपायुक्त को प्रभावित क्षेत्रों में सड़क संपर्क की शीघ्र बहाली सुनिश्चित करने का

शीघ्र राहत और सेवाओं की बहाली का आश्वासन

निर्देश दिया। मंडलायुक्त ने दिलवान गाँव का भी दौरा किया जहाँ अचानक आई बाढ़ के कारण सड़क ढाँचे और बस्तियों को भारी नुकसान पहुँचा है। उन्होंने लोक निर्माण विभाग, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग और पीडीडी के संबंधित अधिशासी अभियंताओं को प्रभावित परिवारों की कठिनाइयों को कम करने के लिए आवश्यक सेवाओं को यथाशीघ्र बहाल करने हेतु निकट समन्वय से कार्य करने के निर्देश दिए।

जम्मू-कश्मीर बिजली क्षेत्र पर भारत सरकार का 143 करोड़ रुपये से अधिक बकाया

श्रीनगर, 21 अगस्त। जम्मू-कश्मीर बिजली क्षेत्र पर पूल घाटा वसूली के मद में भारत सरकार का 143 करोड़ रुपये से अधिक का बकाया है। उत्तरी क्षेत्रीय विद्युत समिति (एनआरपीसी) के प्रतिनिधि ने फोरम को बताया कि पूल घाटा वसूली (विरासत बकाया) के तहत उत्तर प्रदेश और जम्मू-कश्मीर पर क्रमश: 221.54 करोड़ रुपये और 45.37 करोड़ रुपये का कुल बकाया है। एनआरपीसी ने कहा, उत्तर प्रदेश और जम्मू-कश्मीर से अनुरोध है कि वे पूल खाते में नकदी प्रवाह को सुचारू बनाए रखने और किसी भी ब्याज दंड से बचने के लिए लंबित भुगतान में तेजी लाएँ। आधिकारिक दस्तावेज़ में कहा गया है, उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधियों ने फोरम को सूचित किया कि उन्होंने पहले ही यूपीएसईआरसी में विरासत बकाया के भुगतान के लिए एक याचिका दायर कर दी है और यूपीईआरसी के निर्देश के आधार पर वे विरासत बकाया का भुगतान कर देंगे। एनआरपीसी की अध्यक्ष ने बताया कि जम्मू-कश्मीर के बकाया भुगतान का मामला सरकार के उच्चतम स्तर पर उठाया जा चुका है और वर्तमान में प्रक्रियाधीन है तथा बकाया राशि का भुगतान शीघ्र ही कर दिया जाएगा। फोरम ने उत्तर प्रदेश और जम्मू-कश्मीर से अनुरोध किया है कि वे अपने लंबित बकाया का जल्द से जल्द भुगतान करें। आधिकारिक दस्तावेजों से यह भी पता चलता है कि एनआरएलडीसी के प्रतिनिधि ने फोरम को अवगत कराया कि एनआरएलडीसी विभिन्न सीईआरसी विनियमों के प्रावधानों के अनुसार विचलन शुल्क, प्रतिक्रियाशील ऊर्जा शुल्क और संकुलन शुल्क के लिए उत्तरी क्षेत्र पूल खाते का संचालन और रखरखाव कर रहा है। इसमें लिखा है, विनियमों के अनुसार, वैधानिक पूल खाते में भुगतान को उच्च प्राथमिकता दी जाती है और संबंधित उपयोगिताओं को एनआरपीसी सचिवालय द्वारा साप्ताहिक ऊर्जा खाता जारी होने के 10 दिनों के भीतर संकेतित राशि का भुगतान करना आवश्यक है इस संबंध में दस्तावेज में कहा गया है कि जम्मू-कश्मीर के विचलन शुल्क और प्रतिक्रियाशील ऊर्जा शुल्क का भुगतान लंबे समय से लंबित है।

श्रद्धालुओं को वैष्णो देवी दर्शन को ले जा रही बस दुर्घटनाग्रस्त, एक की मौत, 40 घायल

जम्मू, 21 अगस्त। श्री माता वैष्णो देवी तीर्थयात्रियों को ले जा रही एक बस गुरुवार सुबह सांबा जिले के जटवाल इलाके में दुर्घटनाग्रस्त हो गई जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई और कम से कम 40 अन्य घायल हो गए।

अधिकारियों ने बताया कि उत्तर प्रदेश से कटरा जा रही बस में दुर्घटना के समय लगभग 70 लोग सवार थे। यह दुर्घटना सांबा जिले के जटवाल गाँव में हुई। अधिकारी ने बताया कि दुर्घटना सुबह 3 :20 बजे हुई जब बस (यूपी8 1बीटी 7688) घगवाल तहसील के हाई स्कूल जटवाल के पास टायर फटने के कारण पलट गई।

आपातकालीन सेवाएँ और स्थानीय लोग घायलों को बचाने के

लिए घटनास्थल पर पहुँचे। सभी 40 घायल यात्रियों को तुरंत इलाज के लिए एम्स विजयपुर भेज दिया गया है। अधिकारियों ने दुर्घटना के कारणों की आगे की जाँच शुरू कर दी है।

पहले मुगलों ने लूटा, अंग्रेजों ने तबाह किया, फिर कांग्रेस-सपा ने पहचान मिटाई : सीएम योगी

एटा, 21 अगस्त। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर करारा वार करते हुए कहा कि पहले भारत को मुगलों ने लूटा, फिर अंग्रेजों ने तबाह किया और जो कुछ बचा रह गया, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने तबाही का नया मंजर पैदा कर देश के सामने पहचान का संकट खड़ा कर दिया। आज डबल इंजन सरकार की साफ नीयत, स्पष्ट नीति और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की वजह से उत्तर प्रदेश विकास की नई ऊंचाइयों पर पहुंचा है। सीएम योगी ये यह बातें जनपद एटा में 750 करोड़ रुपये की लागत से स्थापित श्री सीमेंट प्लांट के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए कहीं। सीएम योगी ने कहा कि कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी, इनकी नीयत कभी सबके विकास की नहीं रही। इन्होंने साथ तो सबका लिया, लेकिन विकास सिर्फ अपने परिवार का किया। इनके समय में न व्यापारी सुरक्षित था, न बेटी सुरक्षित थी। यही वजह रही कि देश और प्रदेश पिछड़ते चले गए। उन्होंने कहा कि आज मोदी सरकार और डबल इंजन की यूपी सरकार ने सबका साथ, सबका विकास के मंत्र से देश और प्रदेश को नई पहचान दी है।

माफिया का गढ़ अब बना निवेश का केंद्र

सीएम योगी ने कहा कि 8-9 साल पहले एटा की पहचान अपराध और माफिया के गढ़ के रूप में थी। गरीबों की जमीन पर कब्जा होता था, उनकी सुनवाई नहीं होती थी। जब नागरिक की संपत्ति ही सुरक्षित न हो, तब सरकार उसके कल्याण के लिए क्या करेगी? यही स्थिति तब थी।

लेकिन आज एटा बेहतरीन कानून व्यवस्था और निवेश की नई पहचान बना है। उन्होंने कहा कि सरकार के स्तर पर जवाहरपुर थर्मल पावर प्लांट से 1500 मेगावाट बिजली का उत्पादन हो रहा है और उसके बगल में श्री सीमेंट परिवार ने 750 करोड़ रुपये का नया प्लांट लगाया है।

भारत की अर्थव्यवस्था की कहानी

सीएम योगी ने कहा कि भारत 17वीं-18वीं सदी में दुनिया की नंबर-1 अर्थव्यवस्था था। 1947 से 1960 तक छठे स्थान पर रहा, लेकिन कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की नीतियों ने इसे 2014 तक 11वें स्थान पर पहुंचा दिया। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने सबका साथ, सबका विकास का मंत्र दिया और आज भारत चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। अगले दो वर्षों में यह तीसरे स्थान पर होगा।

रोजगार और व्यापार के नए अवसर

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस निवेश से सिर्फ सीधे रोजगार ही नहीं, बल्कि ट्रांसपोर्ट, व्यापार और डिस्ट्रीब्यूशन चैनल से जुड़े हजारों लोगों को भी काम का अवसर मिला है। यही है आत्मनिर्भर भारत की नींव, यही है विकसित भारत की आधारशिला। सीएम योगी ने कांग्रेस काल को याद करते हुए कहा कि एक समय ऐसा था जब सीमेंट कंट्रोल से मिलता था।

मुख्यमंत्री ने कहा- डबल इंजन सरकार ने माफिया के अड्डे को बनाया निवेश का हब

कैनेडा में आपका स्वागत है

पिछले समय से कैनेडा की तरफ़ पंजाबियों का रुझान बढ़ा है। इसके चलते उन्हें बहुत सारी मुश्किलों का सामना भी करना पड़ रहा है। वे कुछ सवालों के भी सम्मुख हो रहे हैं...

आप अपने काम से वापस घर आते हैं। कार पार्क कर जैसे ही आपने दरवाज़ा खोला, तो घर के बाहर लैटर बॉस में हाथ डालते ही ट्रैफिक विभाग का पत्र मिलता है, जिसमें ओवर स्पीड गाड़ी चलाने या रैड लाइटपार करने के कारण आपको जुर्माने का भुगतान करने का निर्देश दिया गया होता है। साथ में यह भी स्लोगन होता है कि यह जुर्म आपने किस दिन, किस समय, किस सड़क पर किया फिर आपके मन में उस दिन की पूरी कहानी आ जाती है।'

ये शब्द हैं पॉइंट बेसिस पर पिछले वर्ष कैनेडा गए मास्टर चरनजीत सिंह सरोआ के। कैनेडा के नियमों, वहां की ट्रैफिक सिकल्ड वर्कर्स को पॉइंट सस्टम पर परिवार समेत कैनेडा आने के क़ानून के अधीन पंजाब प्रांत से टीचिंग क्षेत्र से संबंधित हज़ारों परिवार कैनेडा प्रवास कर चुके हैं और हज़ारों अपने नंबर का इंतज़ार कर रहे हैं।

मास्टर चरनजीत सिंह सरोआ ने बताया कि इस श्रेणी में जाने के लिए आवेदन के बाद पांच से छह वर्ष तक का समय लग जाता था,लेकिन अब नियमों में कुछ ढील देते हुए यह समय कम करके तीन से चार वर्ष का कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि बेशक आर्थिक मंदी के चलते कैनेडा में इस वर्ष प्रवासियों की सख्या में कमी करने की चर्चा दिन प्रति दिन ज़ोर पकड़ रही है, लेकिन पॉइंट सिस्टम के अधीन कुछ एक श्रेणियों के लिए समय सीमा को कम करके 6 से12 महीने भी कर दिया गया है।

कैनेडा आकर आप के पास डॉलर तो होंगे, गाड़ी होगी,साधन होंगे, लेकिन किसी के पास आप से बात करने का समय नहीं होगा। यहां आकर आपको अलगाव का सामना करना होगा, तेज़ बर्फ़ीली हवाओं का और साथ ही संवेदना रहित ठंडे माहौल का भी। आप तीस मंजिल ऊंची तीन चार सौ घरों की बिल्डिंग में हजारों लोगों के साथ रह तो रहे होंगे, लेकिन उनमें से न कोई आपको जानता होगा और न आप किसी को। जैसे-जैसे आप कैनेडा के नज़दीक होते जाएंगे, आपको महसूस होगा कि आप ख़ुद से दूर होते जा रहे हैं।

पॉइंट सिस्टम पर वहां जाने के लिए कतार में लगे पंजाबियों को परिवार समेत वहां पहुंचकर किस माहौल में ख़ुद को ढालना होगा, किन मुश्किलों का सामना करना होगा या फिर जिन परीक्षाओं से गुज़रना है उनके बारे में विस्तार से बात करते हुए मास्टर चरनजीत सिंह सरोआ ने कुछ यूं बताया–

पॉइंट सिस्टम पर कैनेडा पहुंचते ही जो बात सबसे ज़्यादा सुख देती है, वो है एयरपोर्ट पर उतरते ही आपको कैनेडा में नागरिक बनने के लिए ज़रूरी फार्म भरवाकर जमां कर लेना। फिर नए देश में आने वाली मुश्किलों का सामना करने के लिए नए प्रवासियों के लिए प्रावधान है। वहां पर आपको हर प्रकार का फार्म भरने की सलाह मु.क्त दी जाती है। साथ ही फैक्स, टैलीफोन व इंटरनैट की सुविधा भी बिल्कुल मु.क्त प्रदान की जाती है। अगर आप कैनेडा स्टाइल की इंग्लिश में ख़ुद को मास्टर बनाना चाहते हैं,तो यह सैंटर आपका टैस्ट लेकर आपको फ्री कलास में दाखिला दिलाएगा। घर से सैंटर तक आने-जाने के लिए रोज़ाना बस का किराया भी सरकार इस सैंटर के माध्यम से आप तक पहुंचाती है। कैनेडा प्रवेश से पहले आपको अंग्रेज़ी व कंप्यूटर पर पूर्ण महारत होनी चाहिए। अंग्रेजी भाषा और कंप्यूटर ही दो ऐसे माध्यम हैं, जिससे वहां पर आप अच्छे वेतन वाला काम जल्द से जल्द ढूंढ़ सकते हैं। नहीं तो वहां जाकर इन दोनों कामों के एलासें लगानी ज़रूरी हैं। इस श्रेणी के अधीन कैनेडा प्रवास करने वाले पढ़े लिखे व कारीगर होते हैं। वे वहां पर अपने प्रोफैशन में ही कामयाब होने के लिए प्रयासरत होते हैं, परंतु इस बात को अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि वहां आपको उस देश के स्टैंडर्ड के हिसाब से स्वयं अपडेट करना पड़ता है।

भारत से गए डॉक्टर को तो सारे टैस्ट दोबारा देने पड़ते हैं। जो टीचर वहां जाकर टीचिंग में भविष्य बनाना चाहते हैं, उन्हें न केवल आवश्यक टैस्ट पास करना पड़ता है,बल्कि भारत में प्राप्त की गई डिग्रियों के प्रमाण के लिए सभी विश्वविद्यालयों से पत्र भी बनवाने पड़ते हैं। अन्य कामों में हाथ आज़माने के लिए भी अलग-अलग टैस्टपास करने पड़ते हैं। ड्राइविंग लाइसेंस के बिना आप वहां कुछ भी नही हैं। वहां लाइसैंस प्राप्त करने के लिए लिखित टैस्ट केबाद ट्रेनिग लेनी भी ज़रूरी है, उसके बाद ही आप रोड टैस्ट देकर लाइसैंस के हकदार बन सकते हैं। वहां के सिस्टम के हिसाब से आपको हर चीज़ जरुरी से शुरू करनी पड़ती है। आम तौर पर नए प्रवासी वहां पर बेसमैंट किराए पर लेकर रहते हैं,जिसमें हर प्रकार की सहूलियत होती है।

वहां रहने के लिए घर ज़रूरी तो है, लेकिन अगर आप अपना घर ख़रीदने की सोच में हैं, तो आपको बैंक से कर्ज़ लेनापड़ेगा 20 से 30 साल तक इसकी क़िस्तें अदाकरनी पड़ेंगी। खाने-पीने की चीजें काफ़ी सस्ती हैं। तीन-चार दिन की सैलरी से ही आप महीने भर के लिए खाने की चीज़े ख़रीद सकते हैं। खाने-पीने की चीज़ों में मिलावट का कोई ख़तरा वहां पर नहीं है। दिसंबर महीने के आख़िरी दस दिन इलैट्रोनिक चीज़ों पर भारी छूट मिलती है। कई बार तो यह छूट 80 प्रतिशत तक पहुंच जाती है। अगर आप में थोड़ा सब्र करने की क्षमता है, तो चार पांच स्टोर घूमकर कपड़ों की ख़रीद में 50 गुणा तक की बचत कर सकते हैं।

सैकिंड हैंड कारों की ख़रीद आप इंटरनैट के माध्यम से घर बैठे ही कर सकते हैं। यही माध्यम आपके लिए सही रहता है। चूंकि अगर आप डॉलर के माध्यम से कार ख़रीदते हैं, तो आपको उसके कमीशन के साथ-साथ लगभग 13 प्रतिशत टैस देना पड़ता है। कैनेडा शिप्ट होने से पहले यह बात ख़ुद भी समझ लेनी चाहिए व परिवार के साथ जा रहे सदस्यों को भी कि वहां नियमों को नियम समझा जाता है। ट्रैफिक मेंक भी भी इसलिए व्यवधान नहीं पड़ता, क्योंकि सब लोग नियमों का पालन करते हैं। अगर आपने गाड़ी चलाते वक़्त सीट बैल्ट नहीं पहनी, तो दो सौ डॉलर का जुर्माना देना ही पड़ेगा और अगर आप ग़लती से भी रैड लाइट पार कर गए, हों तो पांच सौ डॉलर का जुर्माना आपको तुरंत लगा दिया जाएगा। वहां पर रास्ते में कुछ फैंकने का भी जुर्माना है और बे वजह हार्न बजाने का भी। वहां पर लोग आपको शांति से जीने देते हैं और फिर आपके लिए भी ज़रूरी है कि आप भी ऐसा ही करें। ?

पोर्टब्लेयर में एक सप्ताह

चारों ओर समुद्र से घिरे पोर्टब्लेयर में घूमना, बिलकुल किसी पहाड़ी स्थल हिलस्टेशन की याद दिला रहा था। वही घुमावदार ऊंची-नीची सड़के, छोटे-छोटे शिकरों व घाटियों का जमघट और पहाड़ी नगरों से साफ- सुथरे, छोटे-छोटे बाजार तथा पहाड़ी नगरों जैसे कूं टीर और इमारते। इनसे स्पष्ट हो जाता है कि अंग्रेजों द्वारा जिस तरह पहाड़ी नगरों की परिकल्पना साकार की गई, पोर्टब्लेर भी उन्हीं मानदंडो पर बनाया हुआ था।

अंडमान लक्ष्यद्वीप बन्दरगाह निर्माण कार्य, गेस्ट हाउस से पहले ही बंगाल की खाड़ी के विराट समुंद्र की झलकियां और ऊचे -नीचे सुन्दर- सुगम्यद्वीप की हरीतिमा एवं प्रदूषण रहित वातावरण की सुषमा, हमारे तन मन को झंकृत कर रही थी । एक ऊचें टीले पर स्थित गेस्ट हाउस की ऊचाई से एकदम समुद्र के निकटस्थ थे ही ओर दूर-सुदूर तक फैले- पसरे आकाश से मिलती समुद्र की दृश्यावली ने तो हमारे तन की एक-एक शिरा को पुलकित कर दिया था। गेस्ट हाउस भी बहुत सुन्दर बना था और सबसे बड़ी विशेषता थी- शीतल समीर ,प्रदूशण मुक्त, कालिमा लिए विशाल उत्तंगों के सम्पुट में खड़े कलकत्ता , चेन्नाई के बडें - बड़ें जलयान, आसपास के द्वीपों तक ले जाने वाले, लोटाने वाले बोट,डोगियां और समुद्र की अपरंपार बालू के ढेर को फेंकती ,शोर मचाती जेट मशीन। जॉली बॉय आइलैण्ड ग्रीन पर्ल या मुंगे कारेल की बहुतायत के कारण मूंगे के द्वीप के नाम से प्रख्यात है। हमारे अतिरिक्त रेडस्किव,ऑरासिक द्वीपाके के लिए यहां पर स्टीमर और मोटर - बोट्स उपलब्ध थीं। इस तट से अथाह सागर की छाती चीरते हुए लगभग 70-80 मिनट में स्टीमर, जॉली बॉय द्वीप पहुचा देते थे । हमारे सहित 30 पर्यटक और भी होंगे, जो देश-विदेश से पोर्टब्लेयर की यात्रा पर आए हुए थें। दो स्विट्जरलैण्ड की युवतियां और दो नव-युगलों के अतिरिक्त शेष पर्यटकों में कुछ परिवार थे। स्टीमर जब द्वीपों के दायरे से निकलकर समुद्र की सीधी मुख्यधारा में आया तो उस समय उत्ताल तरंगो के जबरदस्त थपेड़ों में वह जिस प्रकार डूबता-उतरता था,उससे एक अजीब - सा रोमांच पैदा होता था। लगभग आठ-दस द्वीपों को छोड़कर घण्टे भर की यात्रा के बाद, जॉली बॉय के तट से कुछ दूर स्टीमर ने लंगर डाल दिया था। अब स्टिमर से 10-12 पर्यटकों को लेकर मेग्नीफाइड कांच की तली वाली मोटर -बोट्स समुद्र के नीचे 25 फुट तक की गहराई के दृश्य का अवलोकन कराती हुई, जॉली बॉय पर छोड़ने का सिलसिला शरू कर चुकी थी। हम लोगों को मोटर -बोट्स संचालकों ने हमारी इच्छा के मुताबिक काफी देर तक उस समुद्र के नीचे, रहस्यलोक की लुभावनी मनोरम आकर्षक झाकियों का अवलोकन कराया। निश्चय ही उस समुद्री सुषमा और सौंदर्य को देखकर , हम अभिभूत रह गए थे। जॉली बॉय के तट पर काफी लम्बे दायरे तक ऐसा स्वच्छ निर्मल समुद्र था, जो पर्यटकों के अनूसार कन्या कुमारी, चेन्नई का मेरीना बीच एवं गोवा के बीच आदि सभी समुद्रीय तटों को को फीका कर देता था हालांकि मेरा समुद्र में स्नान करने का कतई विचार नहीं था, लेकिन उस निर्मल,मणिकांत व दुग्ध फेनिल जल राशियों को देखकर ,मैने तुरन्त कपड़े उतारकर समुद्र के पानी में उतरने का निर्णय लिया। अन्यान्य स्टीमरों में सें आए सैकड़ों पर्यटक जलक्रीड़ा का आनंद ले रहे थे और सागर की गहराई में कोरल को और करीब से देखने के लिए डाइविंग सैट, मैग्नी फाइड चश्में और बड़े-बड़े ट्यूब्स का आधार लेकर कई तैराकी युवक-युवती सागर में दूर तक तैरते नजर आ रहे थे।

जॉली बॉय में कोरल की खोज किसी अंग्रेज़ अफसर के जॉली नामक साहबजादे द्वारा की गई थी, इसीलिए इस टापू का नाम 'जाली बॉय' रखा गया था। जॉली बॉय के उस नैसर्गिक स्वच्छ पानी के दायरे से काफी दूर अथाह सागर एकदम काला दिखाई दे रहा था और इसकी विभाजन रेखा को स्पष्ट देखा जा सकता था। वापसी में भी मैग्नीफाइड मोटरबोट्स द्वारा ग्रीन पर्ल के अद्भुत दृश्य देखते हुए सभी यात्री जब स्टीमर पर पहुच गए तो वापसी यात्रा शरु हो गई । पोर्ट ब्लेयर आकाशवाणी केन्द्र द्वारा आयोतिज अ.भा. कवि सम्मेलन में आगरा से सुशील सरित सहित मैं लेखक सम्मिलत हुआ था। आकाशवाणी केन्द्र द्वारा हमें सेल्यूलर जेल, कारवाइन बीच, रोस्स आइलैंड तथा जॉली बॉय आदि प्रमुख दर्शनीय स्थलों है।

कला-शिल्प का अद्भुत संगम :खजुराहो

खजुराहो के मंदिर भारतीय कला का एक उत्कृष्ट नमूना है। इन मंदिरों की दीवारों पर उकरी देवी-देवताओं की विभिन्न मुद्राओं की मनोहारी प्रतिमा अपने आप में दुलर्भ है, जिसके समान कोई ओर नहीं है। मध्यप्रदेश में स्थित खजुराहो पर्यटकों के आकर्षण का प्रमुख केंद्र है।

हर साल लाखों की संख्या में देशी व विदेशी पर्यटक खजुराहों आते हैं व यहाँ की खूबसूरती को अपनी स्मृति में कैद करके ले जाते हैं। यहाँ शाम के वक्त होने वाले लाइट शो में खजुराहो के मंदिरों की खूबसूरती का चरम देखने को मिलता है, जो एक यादगार व अविस्मरणीय अनुभव होता है।

भारतीय कला व संस्कृति के संगम स्थल खजुराहों के आसपास भी कई ऐसे स्थान है, जो आपकी खजुराहो यात्रा को पूर्णता प्रदान करते हैं। इनमें खजुराहो से 25 किमी दूर स्थित राजगढ़ पैलेस (हैरिटेज होटल), रंगून झील (पिकनिक स्पॉट), पन्ना राष्ट्रीय उद्यान आदि स्थल है। खजुराहो को प्यार का प्रतीक भी कहा जाता है। यहाँ काम मुद्रा में मग्न देवताओं की भी मूर्तियाँ है, जो अश्लीलता नहीं बल्कि सौंदर्य और प्यार की प्रतीक हैं। प्यार के साक्षी इन्हीं मंदिरों में प्रतिवर्ष कई जोड़े परिणय सूत्र में बँधकर अपने दांपत्य जीवन की शुरुआत करते हैं।

खजुराहो एक पर्यटक स्थल होने के साथ-साथ मंदिरों के गाँव के रूप में भी विख्यात है। यहाँ के मंदिर लगभग 1000 सालों से भी अधिक पुराने हैं, जिन्हें मध्यभारत के चंदेल राजपूत राजाओं ने बनवाया था।

वर्तमान में प्राचीन 85 मंदिरों में से मात्र 22 मंदिर ही सुरक्षित बचे हैं। शेष मंदिर आज खंडहर के रूप में तब्दील होकर जीर्ण-शीर्ण अवस्था में हैं। खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिर पूर्वी, पश्चिमी व दक्षिणी आदि तीन भागों में विभाजित हैं।

पश्चिमी भाग के मंदिर :- खजुराहो में पश्चिमी भाग के मंदिरों में प्रमुख मंदिर कंडरिया महादेव मंदिर, चौंसठ योगिनी मंदिर (ग्रेनाइट से बना सुंदर मंदिर), काली माँ का मंदिर, देवी जगदंबा मंदिर आदि प्रमुख हैं। इन मंदिरों के उत्तर में चित्रगुप्त मंदिर (सूर्य देवता का मंदिर), विश्वनाथन मंदिर (तीन मुखी ब्रह्मा की प्रतिमा तथा 6 फीट ऊँची नंदी प्रतिमा), मटंगेश्वर मंदिर (8 फीट ऊँचा शिवलिंग) आदि स्थित है।

मंदिरों में स्थित प्रतिमाओं की जर्जर स्थिति को देखते हुए इनमें से कई मंदिरों में पूजा करना प्रतिबंधित है। इनमें से केवल ममटंगेश्वर मंदिर में ही अब तक पूजा करना जारी है।

पूर्वी भाग के मंदिर :

इस भाग में हिंदू व जैन दोनों के देवी-देवताओं की दुर्लभ प्रतिमाएँ स्थित हैं। मंदिरों का यह भाग खजुराहो गाँव के समीप स्थित है। पूर्वी भाग का सबसे बड़ा मंदिर जैन तीर्थंकर 'भगवान पार्श्वनाथ जी का मंदिर' है। इसके बाद दूसरा जैन मंदिर 'घाटी मंदिर' है। इस मंदिर के उत्तर में 'आदिनाथ मंदिर' हैं। मंदिरों के इस समूह में ब्रह्मा, वामन आदि हिंदू देवताओं के मंदिर भी शोभायमान है।

दक्षिणी भाग के मंदिर :

मंदिरों का यह समूह खजुराहो गाँव से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इनमें सबसे अच्छा मंदिर 'चित्रभुज मंदिर' है। इस भाग के मंदिरों से कुछ दूरी पर सड़क के उस पार जैन मंदिरों का एक समूह है, जिनमें कई जैन तीर्थंकरों के सुंदर व आकर्षक मंदिर है।

खजुराहो के आसपास: भारतीय कला व संस्कृति के संगम स्थल खजुराहों के आसपास भी कई ऐसे स्थान है, जो आपकी खजुराहो यात्रा को पूर्णता प्रदान करते हैं। इनमें खजुराहो से 25 किमी दूर स्थित राजगढ़ पैलेस (हैरिटेज होटल), रंगून झील (पिकनिक स्पॉट), पन्ना राष्ट्रीय उद्यान (34 किमी दूर) आदि रमणीय स्थल हैं।

भारत की इस विरासत को देखना मात्र ही अपने आप में भारतीय कला से रूबरू होना है, जो अपने आप में अनूठी है, प्राचीन है व गौरवशाली है। आप भी मंदिरों के इस गाँव की सुंदरता को निहारने एक बार अवश्य खजुराहों जाएँ।

स्वामी, प्रकाशक एवं मुंद्रक – नीलम सिंह गिल द्वारा देहात संदेश, गुरूद्वारा सुंदर सिंह रोड़, जम्मू से प्रकाशित एवं नार्थलाईनस पबलिशर्स, 18-बी, फेस-2, इंडस्ट्रियल इस्टेट, गंग्याल, जम्मू से मुद्रित। संपादक– नीलम सिंह गिल। फोन नंबर : (95) 191-2574109, 2548103 RNI Regd. No: JKBIL/2004/13144 Email: dehatsandesh@gmail.com, dehatsandesh@yahoo.com, dehatsandesh@rediffmail.com

नौशहरा के सेरी विद्यालय में ग्रामलोक कार्यक्रम, डोगरी कविताओं से गूँजा साहित्यिक उत्सव

जम्मू, 21 अगस्त (हि.स.)। राजौरी ज़िले की तहसील नौशहरा स्थित सरकारी उच्च माध्यमिक विद्यालय, सेरी का प्रांगण वीरवार सुबह से ही साहित्यिक उत्सव में तब्दील हो गया, जब साहित्य अकादेमी, नई दिल्ली द्वारा ग्रामलोक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर स्थानीय डोगरी कवियों की काव्य प्रस्तुतियों ने श्रोताओं को भावविभोर कर दिया।

कार्यक्रम की अध्यक्षता साहित्य अकादेमी, नई दिल्ली की डोगरी परामर्श मंडल के संयोजक मोहन सिंह ने की। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि साहित्य अकादेमी ही देश की एकमात्र संस्था है, जो संविधान में शामिल 24 भारतीय भाषाओं के साहित्य के संरक्षण और संवर्धन के लिए निरंतर कार्यरत है। उन्होंने ग्रामलोक की विशेषता बताते हुए कहा कि यह कार्यक्रम दूर-दराज़ के कवियों व लेखकों को मंच प्रदान कर उनकी साहित्यिक पहचान बनाने में सहायक है। स्थानीय कवियों, बालक राम ब्राल, अमरजीत हरताल, मदन मोहन शर्मा, पुष्प राज और ओम भजोवालिया, ने अपनी कविताओं के माध्यम से डोगरी जीवन की सादगी, लोक संस्कृति की सुगंध और सामाजिक सरोकारों को अभिव्यक्त किया। तालियों की गड़गड़ाहट ने वातावरण को और भी जीवंत बना दिया। इस अवसर पर जम्मू से आए वरिष्ठ साहित्यकार शिवदेव सुशील, पूरन चंदर शर्मा और रंधीर सिंह रैपुरिया की उपस्थिति ने कार्यक्रम की गरिमा बढ़ा दी। मोहन सिंह ने अंत में कहा कि डोगरी भाषा व साहित्य की समृद्ध परंपरा को नई पीढ़ी तक पहुँचाने के लिए ऐसे आयोजनों का होना अनिवार्य है और साहित्य अकादेमी इस दिशा में लगातार प्रयासरत है। कुल मिलाकर, नौशहरा का यह ग्रामलोक कार्यक्रम डोगरी साहित्य प्रेमियों के लिए एक ऐतिहासिक और अविस्मरणीय अनुभव बन गया

सेना ने छात्रों को करियर मार्गदर्शन व व्यक्तित्व विकास पर दी प्रेरक जानकारी

जम्मू, 21 अगस्त (हि.स.)। भारतीय सेना द्वारा राजौरी जिले के सरकारी मिडिल स्कूल, मोरिया में छात्रों के लिए व्यक्तित्व विकास पर विशेष व्याख्यान का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य युवाओं को रोज़गार के अवसरों के प्रति जागरूक करना और उन्हें भारतीय सशस्त्र बलों में भविष्य बनाने के लिए प्रेरित करना था। व्याख्यान के दौरान छात्रों को स्कूल के बाद उपलब्ध विभिन्न करियर विकल्पों के बारे में विस्तार से बताया गया। विशेष रूप से भारतीय सेना में शामिल होने की प्रक्रिया, उसकी संभावनाएँ और अग्निवीर योजना के लाभों पर जानकारी दी गई। भारतीय सेना ने इस पहल के माध्यम से युवाओं को उत्कृष्टता के लिए प्रयासरत रहने और राष्ट्र की सुरक्षा में योगदान देने का आह्वान किया। इस कार्यक्रम ने छात्रों को न केवल नई दिशा प्रदान की बल्कि सेना और स्थानीय समुदाय के बीच सकारात्मक संबंधों को भी और मजबूत किया। छात्रों और शिक्षकों ने इस व्याख्यान को उत्साहपूर्वक स्वीकार किया और इसे भविष्य की राह दिखाने वाला उपयोगी मंच बताया।

जीजीएम साइंस कॉलेज में दो दिवसीय अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन आईसीईटीएमआर-2025 सम्पन्न

जम्मू, 21 अगस्त (हि.स.)। गवर्नमेंट गांधी मेमोरियल (जीजीएम) साइंस कॉलेज द्वारा आयोजित इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन इमर्जिंग ट्रेंड्स इन मल्टीडिसिप्लिनरी रिसर्च (आईसीईटीएमआर-2025) का समापन वीरवार को यहां भव्य वैलेडिक्ट्री सत्र के साथ हुआ। मुख्य अतिथि क्लस्टर यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू के कुलपति प्रो. (डॉ.) के.एस. चंद्रशेखर और विशिष्ट अतिथि उच्च शिक्षा विभाग, जम्मू-कश्मीर की निदेशक (योजना) सुहलीन कौर ने कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। सम्मेलन ने देश-विदेश के शिक्षाविदों, शोधकर्ताओं और विद्वानों को नए शोध क्षेत्रों पर विचार-विमर्श और नवीन विचारों के आदान-प्रदान का अवसर प्रदान किया। दो दिनों में तीन स्थलों पर नौ तकनीकी सत्र आयोजित हुए, जिनमें ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों माध्यमों से सक्रिय भागीदारी देखी गई।

रसायन विज्ञान में 32 से अधिक शोध-पत्र, वाणिज्य, प्रबंधन और अर्थशास्त्र में 13 प्रस्तुतियाँ, भाषा एवं सामाजिक विज्ञान में 44 शोध-पत्र, जीवन एवं पर्यावरण विज्ञान में 41, गणितीय व कम्प्यूटेशनल विज्ञान में 18 तथा भौतिक व पृथ्वी विज्ञान में 31 शोध-पत्र प्रस्तुत किए गए। इन विषयों ने सतत ऊर्जा, जैव विविधता संरक्षण, डिजिटल उद्यमिता, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, नैनोमैटेरियल्स और सांस्कृतिक विमर्श जैसे मुद्दों को केंद्र में रखा। सम्मेलन में राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञों के आमंत्रित व्याख्यान भी शामिल रहे। पहले दिन अभिनेव थिएटर में जेके आर्ट्स, कल्चर एंड लैंग्वेजेज अकादमी द्वारा आयोजित सांस्कृतिक संध्या ने जम्मू-कश्मीर की धरोहर को जीवंत कर दिया। समापन अवसर पर संयोजक डॉ. पी.एस. मनहास ने विस्तृत प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। अपने अध्यक्षीय भाषण में प्रो. चंद्रशेखर ने सम्मेलन को युवा और वरिष्ठ शोधकर्ताओं के बीच सहयोग का सेतु बताते हुए शोध को सामाजिक जरूरतों से जोड़ने पर बल दिया। सम्मेलन की कार्यवाही का संचालन डॉ. रेविका अरोड़ा ने किया और धन्यवाद ज्ञापन प्रो. आकांक्षा परिहार ने प्रस्तुत किया। इस प्रकार दो दिनों का यह शैक्षणिक उत्सव सार्थक संवाद और शोध सहयोग की नई संभावनाओं के साथ सम्पन्न हुआ।

पुलिस को मिली एक बड़ी सफलता

कटरा , 21 अगस्त (हि.स.)। नशे और अपराध के विरुद्ध अपने निरंतर अभियान में, रियासी ज़िला पुलिस को आज एक बड़ी सफलता मिली जब पुलिस चौकी बान गंगा की पुलिस पार्टी ने बलिनी पुल से बान गंगा लिंक रोड पर एक नाका लगाया।

नाका जाँच के दौरान बलिनी पुल की ओर से बान गंगा की ओर पैदल आ रहे दो व्यक्ति जो आपस में बातचीत कर रहे थे को पूछताछ के लिए रोका गया। पूछताछ करने पर उन्होंने अपनी पहचान बादल कुमार पुत्र दलीप कुमार निवासी पंजर, तहसील मोंगरी, जिला उधमपुर और बलवान चंद पुत्र बोध राज निवासी दुबी गली, तहसील मोंगरी, जिला उधमपुर के रूप में बताई।

संदेह के आधार पर दोनों की तलाशी ली गई। बादल कुमार के पास से पुलिस ने 3.350 ग्राम हेरोइन जैसा पदार्थ युक्त एक पारदर्शी पॉली पैक और 3 मोबाइल फोन बरामद किए। बलवान चंद के पास से 4 मोबाइल फोन बरामद किए गए।

जब उनसे तस्करी के सामान और इतनी बड़ी संख्या में मोबाइल फोन के बारे में पूछताछ की गई तो दोनों कोई संतोषजनक जवाब या बरामद मोबाइल फोन के स्वामित्व का प्रमाण नहीं दे पाए। यहाँ यह बताना उचित होगा कि ज़ब्त किए गए मोबाइल फोन की कुल कीमत लगभग 1 लाख है और इनके चोरी के होने का संदेह है।

तदनुसार इस संबंध में पुलिस स्टेशन कटरा में एफआईआर संख्या 239/2025 यू/एस 8/21/22/29 एनडीपीएस अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है और आगे और पीछे के संबंधों का पता लगाने के लिए आगे की जांच जारी है।

सेना ने राजौरी के दुर्गम क्षेत्रों में मेडिकल पेट्रोल कर 36 लोगों को स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान कीं

जम्मू, 21 अगस्त (हि.स.)। भारतीय सेना ने राजौरी ज़िले के दुर्गम क्षेत्र बुढ़ की खानरी में मेडिकल पेट्रोलिंग अभियान सफलतापूर्वक संचालित किया। इस दौरान सेना की चिकित्सा टीम ने बुजुवाला क्षेत्र और उसके अंतर्गत आने वाले धोक बुढ़ की खानरी, दराटे वाली और जरीवाली में रह रहे लोगों को स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान कीं। इस पहल का मुख्य उद्देश्य दूरदराज़ के उन ग्रामीणों तक बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाएँ पहुँचाना था, जो नियमित चिकित्सा केंद्रों से कोसों दूर रहते हैं। अभियान के दौरान कुल 36 लोगों का इलाज किया गया, जिनमें 3 बच्चे, 14 महिलाएँ और 19 पुरुष शामिल थे। उपचार में सामान्य स्वास्थ्य जांच से लेकर आम बीमारियों का इलाज किया गया, ताकि लोगों को तुरंत राहत मिल सके। भारतीय सेना की यह पहल न केवल स्थानीय लोगों को चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने में सहायक रही, बल्कि सेना और नागरिकों के बीच आपसी विश्वास और सद्भाव को भी और मजबूत करने वाली साबित हुई। सेना ने स्पष्ट किया कि वह कठिन भौगोलिक परिस्थितियों में भी जनता के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है।

जेडीए ने पुलिस प्रशासन के साथ मिलकर एंटी-एन्क्रोचमेंट ड्राइव चलाई

जम्मू , 21 अगस्त (हि.स.)। जम्मू-कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश में आज जेडीए (जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी) की ओर से सख़्त कार्रवाई देखने को मिली। जम्मू के सिद्रा इलाके में जेडीए ने पुलिस प्रशासन के साथ मिलकर एंटी-एन्क्रोचमेंट ड्राइव चलाई।

मौके से मिली जानकारी के अनुसार जिन लोगों ने जेडीए की ज़मीन पर अवैध निर्माण किया था उनके निर्माण को आज ढहा दिया गया। कार्रवाई के दौरान प्रभावित लोग प्रशासन से रहम की गुहार लगाते रहे लेकिन जेडीए और पुलिस के सामने उनकी एक न चली। जेडीए का पीला पंजा लगातार चलता रहा और अवैध निर्माण ध्वस्त होते रहे।

उपमुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री के सलाहकार ने जम्मू-कश्मीर में आठ युवाओं को आरएएस के तहत नियुक्ति पत्र सौंपे

श्रीनगर 21 अगस्त (हि.स.)। सार्वजनिक सेवाओं को मजबूत करने और युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए उपमुख्यमंत्री सुरिंदर चौधरी ने मुख्यमंत्री के सलाहकार नासिर असलम वानी के साथ नागरिक सचिवालय श्रीनगर में पुनर्वास सहायता योजना-2022 के तहत आठ नियुक्ति पत्र सौंपे।

इस अवसर पर उपमुख्यमंत्री ने नियुक्त लोगों को बधाई दी और उनसे समर्पण और ईमानदारी से काम करने का आग्रह किया। ये नियुक्ति पत्र केवल नौकरी के आदेश नहीं हैं बल्कि जम्मू-कश्मीर के लोगों के प्रति एक जिम्मेदारी हैं। उन्होंने कहा कि मुझे विश्वास है कि आज नियुक्त हुए युवा ईमानदारी से काम करेंगे और जवाबदेही और जन सेवा के मूल्यों को बनाए रखेंगे।

मुख्यमंत्री के सलाहकार ने भी इसी तरह की भावनाओं को व्यक्त किया और रोजगार के अवसरों का विस्तार करने और निष्पक्ष भर्ती सुनिश्चित करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता पर प्रकाश डाला। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व में प्रशासन युवाओं को सशक्त बनाने के लिए निरंतर काम कर रहा है।

नियुक्त व्यक्तियों ने जिन्हें गणमान्य व्यक्तियों से पत्र प्राप्त हुए, समाज में योगदान करने का अवसर प्रदान करने के लिए सरकार के प्रति आभार व्यक्त किया तथा आश्वासन दिया कि वे अपने कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक निर्वहन करेंगे।

वीरों को श्रद्धांजलि अर्पित की और कैडेटों से बातचीत की

द्रास, 21 अगस्त (हि.स.)। लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीरपाल सिंह, पीवीएसएम, एवीएसएम, वीएसएम, राष्ट्रीय कैडेट कोर (डीजीएनसीसी) के महानिदेशक, मेजर जनरल अनुपिंदर बेवली, वीएसएम, एडीजी जेके एंड एल निदेशालय के साथ 20 अगस्त 2025 को 2 लद्दाख बटालियन एनसीसी, कारगिल का दौरा किया। यह यात्रा विशेष महत्व रखती है क्योंकि 2 लद्दाख बटालियन एनसीसी की स्थापना के बाद जनरल ऑफिसर की यह केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की पहली यात्रा थी। इस दिन की शुरुआत कारगिल युद्ध स्मारक, द्रास में आयोजित एक भव्य पुष्पांजलि समारोह के साथ हुई, जहाँ लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीरपाल सिंह ने कर्तव्य निभाते हुए अपने प्राणों की आहुति देने वाले सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस कार्यक्रम में 2 लद्दाख बटालियन, एनसीसी के नवगठित एनसीसी कैडेटों द्वारा शहीद नायकों को भावभीनी श्रद्धांजलि देने के लिए शस्त्रों की औपचारिक प्रस्तुति के उच्च स्तर की विशेषता थी। उन्होंने आगे बताया कि भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप, एनसीसी पाठ्यक्रम में हाल ही में संशोधन किया गया है जिसमें ड्रोन और कौशल आधारित प्रशिक्षण को शामिल किया गया है। उन्होंने कैडेटों से आग्रह किया कि वे अपनी रुचि के अनुसार क्षेत्र चुनें और असफलता से न डरें। सभी को अपने स्वास्थ्य को उचित महत्व देते हुए हमेशा फिट रहना चाहिए और राष्ट्र के जिम्मेदार नागरिक बनने का प्रयास करना चाहिए क्योंकि ये सभी राष्ट्रीय गौरव हैं। उत्कृष्ट एनसीसी कैडेटों, एएनओ और पीआई स्टाफ को एनसीसी गतिविधियों, खेलों में उनकी उपलब्धियों और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उनके अनुकरणीय योगदान के लिए सम्मानित किया गया।

रामकृष्ण मिशन मेडिकल सेंटर में लगेगा नि:शुल्क मेगा मल्टी-स्पेशलिटी हेल्थ कैंप

जम्मू, 21 अगस्त (हि.स.)। रामकृष्ण मिशन मेडिकल सेंटर (आरएमएमसी), रामकृष्ण विहार, उधेयवाला, जम्मू में शनिवार, 23 अगस्त को प्रातः 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक एक नि:शुल्क मेगा मल्टी-स्पेशलिटी हेल्थ कैंप आयोजित किया जा रहा है। यह पहल सरकारी आयुर्वेदिक अस्पताल जम्मू और आयुष विभाग के सहयोग से हो रही है, जिसका उद्देश्य आम जनता को समग्र स्वास्थ्य सेवाएँ उपलब्ध कराना है। कैंप का नेतृत्व डॉ. विश्व देव सिंह, एमबीबीएस, एमडी (मेडिसिन), डीएनबी गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी एवं हेपेटोलॉजी (नारायणा अस्पताल) करेंगे। उनके साथ एलोपैथिक व आयुर्वेदिक चिकित्सकों की टीम अपनी सेवाएँ देगी।

इस शिविर में जनरल फिजीशियन, स्त्री रोग विशेषज्ञ, ईएनटी विशेषज्ञ, नेत्र रोग विशेषज्ञ, अस्थि रोग विशेषज्ञ, फिजियोथेरेपिस्ट तथा आयुर्वेदिक विशेषज्ञ (डाइटिशियन सहित) परामर्श देंगे। इसके अतिरिक्त फुल बॉडी चेकअप पैकेज में विशेष रियायती दर पर उपलब्ध होगी। कैंप की विशेष आकर्षण सेवाओं में फ्री फाइब्रोस्कैन और फ्री न्यूरोपैथी टेस्ट शामिल हैं, जो क्रमशः लीवर और नसों से जुड़ी बीमारियों की जांच में सहायक होंगे। साथ ही, मरीजों को नि:शुल्क आयुर्वेदिक दवाएँ भी वितरित की जाएँगी

डोगरी संस्था जम्मू ने किया डॉ. निर्मल विनोद की चार पुस्तकों का विमोचन

जम्मू, 21 अगस्त (हि.स.)। डोगरी संस्था जम्मू ने वीरवार को राइटर्स क्लब, के.एल. सहगल हॉल में डॉ. निर्मल विनोद की चार पुस्तकें खरा फकीरी ठाठ (सांस्कृतिक रचना संग्रह), समे दे खंडे पर (कविता संग्रह), कनियां सुन्ने दियां (कविता संग्रह) और रंग रंगीला भारत देश (गीत संग्रह) का विमोचन किया। कार्यक्रम में प्रो. आर.डी. शर्मा, पूर्व वाइस चांसलर, जम्मू विश्वविद्यालय मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए, जबकि अध्यक्षता पद्मश्री प्रो. ललित मगोत्रा, प्रधान, डोगरी संस्था जम्मू ने की। कार्यक्रम की शुरुआत प्रो. वीणा गुप्ता के स्वागत भाषण से हुई। इस दौरान उन्होंने डॉ. निर्मल विनोद की साहित्यिक यात्रा पर प्रकाश डाला।

समारोह में विमोचित पुस्तकों पर विस्तृत पत्र वाचन पद्मश्री डॉ. जितेंद्र उधमपुरी, डॉ. बंसीलाल शर्मा, नरेंद्र भसीन, इंद्रजीत केसर और डॉ. रतन बसोत्रा ने किया। अपने पत्र वाचन में उन्होंने डॉ. निर्मल विनोद की साहित्यिक रचनाओं की विशेषताओं को रेखांकित किया। वक्ताओं ने कहा कि डॉ. विनोद की लेखनी जीवन और समाज के गहन अनुभवों की सजीव अभिव्यक्ति है। उन्होंने डॉ. निर्मल विनोद के साहित्य को गहन चिंतन, रचनात्मकता और सामाजिक सरोकारों का संगम बताया।

मुख्य अतिथि प्रो. आर.डी. शर्मा ने कहा कि इन रचनाओं में डॉ. निर्मल विनोद की बहुआयामी प्रतिभा का स्पष्ट परिचय मिलता है। खरा फकीरी ठाठ उनकी सांस्कृतिक समझ और सामाजिक दृष्टि को सामने लाती है, जबकि समे दे खंडे पर और कनियां सुन्ने दियां में जीवन के विविध आयामों को कविता के माध्यम से सहज और प्रभावशाली ढंग से अभिव्यक्त किया गया है। वहीं रंग रंगीला भारत देश गीत संग्रह के रूप में भारतीय संस्कृति की विविधता और एकता का उत्सव प्रस्तुत करता है।

भाद्रपद अमावस्या 22-23 अगस्त को

जम्मू, 21 अगस्त (हि.स.)। सनातन धर्म में भाद्रपद मास की अमावस्या का विशेष महत्व माना गया है।

इस दिन वर्ष भर के धार्मिक कार्यों हेतु कुश एकत्र की जाती है, इसलिए इसे कुशोत्पाटिनी अमावस्या या कुशाग्रहणी अमावस्या कहा जाता है। डोगरी भाषा में कुश को दर्भ अथवा दाभ कहा जाता है।

FORMAT FOR CORRECTION OF FATHER NAME & MOTHER & DAUGHTER' NAME IN CASE OF DAUGHTER'S MARKS CARD

I Mani Ram Ahirwar F/o Anju Ahirwar do hereby declare that my name and my wife name & Daughter Name has been wrongly written in my Daughter's 8th Class Marks card bearing Class 8th Roll no 8150104 Registration No PU-23-V111-00269 Session -2023-2024

My name has been wrongly written as Mani Ram and my Wife's name Yashoda & Daughter name Anju instead of correct name Mani Ram Ahirwar & Wife Name Jasoda Ahirwar & Daughter Name Anju Ahirwar I have applied for the above correction DIET Jammu Objection. If any may kindly be conveyed to the Principal DIET Jammu within Seven days from date of publication of this notice

डीडीसी ने विकासात्मक गतिविधियों की प्रगति की समीक्षा की

पुंछ 21 अगस्त (हि.स.)। जिला विकास आयुक्त पुंछ अशोक कुमार शर्मा ने डीसी कार्यालय के कॉन्फ्रेंस हॉल में जिले भर में विकास कार्यों की प्रगति का आकलन करने के लिए एक बैठक की अध्यक्षता की।

बैठक में जिला पूंजीगत व्यय, पंचायती राज संस्थान और डीडीसी अनुदान, शिक्षा, स्वास्थ्य, पीएचई, एनएफबी, युवा सेवा एवं खेल, एसएसवाई, एबीडीओ, एपीडीपी सहित प्रमुख विकासात्मक क्षेत्रों और विकासात्मक पहलों की समग्र स्थिति पर विचार-विमर्श किया गया।समीक्षा के दौरान जिला विकास आयुक्त ने जिला पूंजीगत व्यय बजट के तहत निविदा की स्थिति की जाँच की और संबंधित अधिकारियों को प्रक्रिया में जल्द से जल्द तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने जिले भर में सड़कों और पुलों के साथ-साथ पूरे हो चुके, चल रहे और लंबित कार्यों की प्रगति की भी समीक्षा की। डीडीसी ने जेपीडीसीएल के कार्यकारी अभियंता को प्रधानमंत्री सूर्य मुफ्त बिजली योजना के बारे में जन जागरूकता बढ़ाने और सौर पैनलों की स्थापना में वृद्धि सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने जल जीवन मिशन के तहत घरेलू नल जल कनेक्शनों की गति में तेजी लाने पर जोर दिया ताकि निर्धारित लक्ष्यों को समयबद्ध तरीके से प्राप्त किया जा सके। गुणवत्ता मानकों का पालन करने के महत्व पर जोर देते हुए, डीडीसी ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे बाधाओं को दूर करें और जनता के लाभ के लिए सभी परियोजनाओं को समय पर पूरा करना सुनिश्चित करें।

घायल पर्यटकों का हालचाल जानने के लिए उपायुक्त ने एम्स और जिला अस्पताल का किया दौरा

सांबा 21 अगस्त (हि.स.)। सांबा की उपायुक्त आयुषी सूदन ने सांबा जिला अस्पताल और एम्स विजयपुर का दौरा किया और सांबा जिले में कल देर रात हुई एक सड़क दुर्घटना में घायल हुए पर्यटकों का हालचाल जाना।

इस दौरान उपायुक्त ने घायल मरीजों और उनके तीमारदारों से बातचीत की और उनकी समस्याओं को धैर्यपूर्वक सुना। उन्होंने चिकित्सा कर्मचारियों को पीड़ितों को सर्वोत्तम संभव उपचार और सभी आवश्यक सहायता सुविधाएँ प्रदान करने के लिए कहा।

बाद में उपायुक्त ने विजयपुर के सांगवाल गाँव का दौरा किया जहाँ उन्होंने अशोक कुमार के परिवार से मुलाकात की जिनकी हाल ही में किश्तवाड़ जिले में बादल फटने की घटना में मृत्यु हो गई थी।

उपायुक्त ने शोक संतप्त परिवार के प्रति हार्दिक संवेदना व्यक्त की। उन्होंने परिवार को प्रशासन की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया।

Government of Jammu and Kashmir
OFFICE OF THE DIVISIONAL FOREST OFFICER
KISHTWAR FOREST DIVISION, KISHTWAR

Tender Notice: e-NIT No.: 25 of 2025 Dated: 19-08-2025

For and on behalf of the Hon'ble President of India, e-tenders (Two cover system) are invited from registered, reputed and resourceful Contractors/Firms registered with Jammu & Kashmir Govt./Central Govt. Organizations for the following works:
Name of Work:Laying of Wire Crates in Comptt. 65/K of Kishtwar Range of Kishtwar Forest Division, construction of RCC Check Dam in Comptt. 65/K of Kishtwar Range of Kishtwar Forest Division and DRSM work in Comptt. 65/K of Kishtwar Range of Kishtwar Forest Division under CAMPA NPV for the year 2025-26.

S. No	Particular of works	Qty.	Adv. Cost	Earnest Money 3% (in Rs.)	Class of contractor	Cost of Tender Documents	Time of completion	Receiving/ opening Authority
1	Laying of Wire Crates in Co. 65/K	4	1.05	3151	A, B, C, D	Rs. 600/-	6 Months	Tender Opening Committee
2	Construction of RCC Check Dam in Comptt. 65/K	1	4.50	13500				
3	DRSM works in Comptt. 65/K	235	2.58359	7751				
	Total:		8.13359	24402				

The position of codal formalities in respect of above work(s) is as under:

Position of Funds Approved
Position of AA/TS Accorded

The e-NIT Consisting of qualifying information, eligibility criteria, scope of work, Bills of Quantities, (B.O.Q), Terms & Conditions of contract and other details can be seen/downloaded from the website:-www.jktenders.gov.in

Publishing Date	20-08-2025 at 09:00 AM
Download Start Date	20-08-2025 at 09:00 AM
Bid Submission Start Date	20-08-2025 at 09:00 AM
Bid submission End Date	15-09-2025 upto 01:30 PM
Date of opening of Technical Bid (online).	17-09-2025 at 12:30 PM (In the Office of Divisional Forest Officer, Kishtwar).
Date of opening of Financial Bid (online)	19-09-2025 at 12:30 PM (In the Office of Divisional Forest Officer, Kishtwar).

DIP/J-4874/25
Dtd: 21-8-2025

Sd/-
Mahesh Thakur, JKFS
Divisional Forest Officer,
Kishtwar.

No.: KFD/ 2025-26/ Tender/ 467-73 Dated: 19-08-2025

संपादकीय

ई-रिक्शा को सुव्यवस्थित करें

इसमें कोई संदेह नहीं है कि कुछ साल पहले केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में ई-रिक्शा की संख्या में तेज़ी से वृद्धि हुई है और परिवहन का यह साधन, खासकर अंतिम छोर तक कनेक्टिविटी के लिए, प्रमुखता से उभर रहा है। दिलचस्प बात यह है कि उपरोक्त तथ्य के अलावा, परिवहन के इस नए साधन के आने से कई नई चुनौतियाँ भी आई हैं जो पहले मौजूद नहीं थीं। मुख्य समस्या यह है कि इन वाहनों (ई-रिक्शा) का क्षेत्र की पहले से ही भीड़भाड़ वाली सड़कों पर आना, वह भी सैकड़ों की संख्या में और काफी लंबे होने के कारण, इनकी उपस्थिति विशेष रूप से परेशानी का कारण बन रही है। दूसरी समस्या इन वाहनों को चलाने वालों का खराब ड्राइविंग कौशल है क्योंकि ये वाहन केंद्र शासित प्रदेश के शहरों और कस्बों की आंतरिक सड़कों पर छोटी-मोटी दुर्घटनाओं का कारण बनते हैं। यह भी एक तथ्य है कि इन वाहनों के अधिकांश संचालकों के पास उचित ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होते हैं क्योंकि ये ऐसे इलाकों में चलते हैं जहाँ यातायात नियमों का पालन कराने के लिए यातायात पुलिस की पहुँच नहीं है, जिससे सड़कों और गलियों में और भी ज़्यादा अव्यवस्था हो जाती है। एक और चिंताजनक बात इन वाहनों के संचालकों द्वारा नशीले पदार्थों का सेवन है। हालाँकि कोई आधिकारिक आँकड़े उपलब्ध नहीं हैं, लेकिन नियमित यात्री, खासकर शाम के समय यात्रा करने वाले, इस बात से सहमत होंगे कि कई ई-रिक्शा चालक अक्सर शराब या अन्य नशीले पदार्थों के प्रभाव में होते हैं, क्योंकि जम्मू-कश्मीर में यातायात पुलिस शायद ही कभी नशे में गाड़ी चलाने वालों की जाँच करती है, जिससे इस तरह का व्यवहार अनियंत्रित हो जाता है। इसके अलावा, इस नए परिवहन माध्यम से अधिक किराया वसूलना और अन्य यातायात उल्लंघन भी जुड़े हुए हैं, जिसे इस क्षेत्र और पूरे देश में बढ़ते प्रदूषण के स्तर से निपटने के लिए शुरू किया गया था। जहाँ तक प्रदूषण नियंत्रण का सवाल है, विभिन्न स्तरों पर वर्तमान में चल रही बहसों को देखते हुए, इन इलेक्ट्रिक वाहनों की बैटरियों के निपटान ने एक बड़ा प्रश्नचिह्न खड़ा कर दिया है क्योंकि कई विशेषज्ञों का मानना है कि इस क्रिया से होने वाला प्रदूषण पारंपरिक परिवहन माध्यमों में जीवाश्म ईंधन के अपव्यय से होने वाले प्रदूषण से कई गुना अधिक होगा। हालाँकि लिथियम के निपटान का मुद्दा सरकार के शीर्ष स्तर पर ही सुलझाया जाना है, इसलिए इस समय जम्मू-कश्मीर, खासकर जम्मू क्षेत्र में ई-रिक्शा को सुव्यवस्थित करने पर ध्यान देना ज़रूरी है क्योंकि राजमार्गों पर उनके प्रवेश पर प्रतिबंध संबंधी आदेश का भी अक्षरशः पालन नहीं किया गया है और उनके संचालन को विशिष्ट क्षेत्रों तक सीमित रखने से भी उद्देश्य पूरा नहीं हुआ है। हालाँकि इस विधा ने कई बेरोजगार युवाओं को अपनी ओर आकर्षित किया है क्योंकि अब उनके पास आजीविका का ज़रिया है, लेकिन कुल मिलाकर, सरकार को इन बैटरी चालित ध्वनिरहित रिक्शा से जुड़ी चुनौतियों को सुव्यवस्थित करने के लिए बहुत कुछ करने की आवश्यकता है।

ऑनलाइन गेमिंग और सोशल मीडिया, ऑस्ट्रेलिया जैसे प्रयोग की भी जरूरत

-डॉ. निवेदिता शर्मा

लोकसभा में 20 अगस्त 2025 को जब इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ऑनलाइन खेल संवर्धन और विनियमन विधेयक, 2025 प्रस्तुत किया तब इस दिशा में यह भी स्पष्ट हो गया कि यह केवल एक विधायी औपचारिकता नहीं थी, डिजिटल युग की नई चुनौतियों के प्रति सरकार के दृष्टिकोण में आए बदलाव का इसे आप पुख्ता प्रमाण मान सकते हैं। इस विधेयक में रियल मनी गेमिंग और उसके विज्ञापनों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने, उल्लंघन करने वालों के लिए जेल और जुर्माने जैसी कठोर सजा का प्रावधान करने और साथ ही ई-स्पोर्ट्स, शैक्षणिक तथा सामाजिक खेलों को बढ़ावा देने का प्रावधान करता है। विधेयक में स्पष्ट शब्दों में कहा गया है कि इस कदम का उद्देश्य समाज, विशेषकर युवाओं और कमजोर वर्गों को डिजिटल व्यसन के दुष्प्रभावों से बचाना है।

भारत में एक तरह से देखा जाए तो ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री पिछले एक दशक में अप्रत्याशित रफ्तार से बढ़ी है। आज इसका आकार 32,000 करोड़ रुपये तक पहुँच चुका है और अनुमान था कि 2029 तक यह उद्योग 80,000 करोड़ रुपये के स्तर को छू लेगा। लेकिन इस वृद्धि की असल नींव रियल मनी गेमिंग यानी पैसों के लालच और जुए जैसे खेलों पर आधारित रही। आँकड़े बताते हैं कि इंडस्ट्री का 86 प्रतिशत राजस्व इन्हीं खेलों से आता रहा है। यह वही खेल हैं, जिनमें किशोर और युवा अपनी मेहनत की कमाई, यहाँ तक कि उधार लिए पैसे भी गँवाते रहे। परिवार टूटे, सामाजिक रिश्ते बिगड़े, अवसाद और आत्महत्या के मामले बढ़े। अब तक हजार से कई अधिक की संख्या में लोग गेम के चक्कर में मौत को गले लगा चुके हैं। ऐसे में स्वभाविक है कि देश भर में सरकार का यह कदम ऐसे हालात में न केवल उचित है बल्कि यह समय की माँग भी है। लेकिन इसके साथ ही जिम्मेदारीपूर्ण यह मांग भी उठना स्वभाविक है कि यदि सरकार डिजिटल व्यसन की इस समस्या को ऑनलाइन गेमिंग के संदर्भ में गंभीरता से देख सकती है तो क्या वही तर्क सोशल मीडिया पर लागू नहीं होना चाहिए

इससे जुड़े तथ्य दुनिया के सामने आज मौजूद है, फिर अनुभव भी यही बताता है कि सोशल मीडिया का असर कहीं अधिक व्यापक और कहीं अधिक गहरा है। यह न केवल आर्थिक नुकसान का कारण बनता है बल्कि मानसिक स्वास्थ्य, सामाजिक ताने-बाने और लोकतांत्रिक विमर्श के लिए भी गंभीर खतरा है। ऑस्ट्रेलिया का हालिया निर्णय इस संदर्भ में बेहद प्रासंगिक है। वहाँ संघीय सरकार ने ऐलान किया है कि 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, यूट्यूब, स्नैपचैट, रेडिट और एक्स जैसे प्लेटफ़ॉर्म्स पर किसी भी रूप में सक्रिय रहने की अनुमति नहीं होगी। यह कानून आने वाले चार महीनों में लागू होगा और सोशल मीडिया कंपनियों को 10 दिसंबर तक सभी नाबालिग खातों को हटाना होगा। केवल इतना ही नहीं, इन कंपनियों को आयु सत्यापन की ऐसी प्रणाली लागू करनी होगी जिससे भविष्य में नाबालिग नए खाते न बना सकें। यह प्रतिबंध इतना कठोर है कि माता-पिता की अनुमति से भी बच्चों को इन प्लेटफ़ॉर्म्स तक पहुँचने की छूट नहीं दी जाएगी।

ऑस्ट्रेलिया में यह निर्णय एकाएक नहीं लिया गया है, सोशल मीडिया ने बच्चों और किशोरों को जिस तरह की लत में जकड़ा है, उसने मानसिक स्वास्थ्य की समस्याओं को कहीं अधिक बढ़ा दिया है। आत्महत्या के मामलों में वृद्धि, अवसाद और चिंता जैसी बीमारियों का फैलाव और नींद के गंभीर संकट अब विश्व स्तर पर दर्ज किए जा रहे हैं। स्वभाविक है ऑस्ट्रेलिया में यही सब कुछ बड़े स्तर पर देखा गया, जिसके बाद ऑस्ट्रेलियाई सरकार इस निष्कर्ष पर पहुंची कि बच्चों को वास्तविक जीवन और डिजिटल जीवन के बीच संतुलन बनाना सिखाना होगा और इसके लिए कठोर कानून ही कारगर उपाय है।

भारत के संदर्भ में स्थिति और भी गंभीर है। यहाँ युवाओं की संख्या सबसे अधिक है और इंटरनेट तक पहुँच अब गाँव-गाँव तक हो चुकी है। रिपोर्टों के अनुसार, भारतीय किशोर प्रतिदिन औसतन चार से पाँच घंटे सोशल मीडिया पर बिताते हैं। यह समय उनके अध्ययन, परिवार के साथ बिताए जाने वाले पलों और वास्तविक सामाजिक संबंधों से छीन लिया जाता है। जिस दौर में शिक्षा और कौशल विकास पर अधिक ध्यान देना चाहिए, उसी समय उनका मन टिकटॉक, इंस्टाग्राम रील्स और यूट्यूब शॉर्ट्स जैसी सतही चीज़ों में उलझा रहता है। सोशल मीडिया के दुष्प्रभाव केवल समय की बर्बादी तक सीमित नहीं हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन और अनेक मानसिक स्वास्थ्य अध्ययनों ने स्पष्ट किया है कि इन प्लेटफ़ॉर्म्स का अत्यधिक प्रयोग अवसाद, चिंता और नींद की कमी का कारण बन रहा है। किशोरावस्था में यह मानसिक असंतुलन और भी खतरनाक रूप ले लेता है। भारत जैसे देश में, जहाँ मानसिक स्वास्थ्य सुविधाओं की भारी कमी है, वहाँ यह समस्या एक राष्ट्रीय संकट से किसी भी स्तर पर कम नहीं मानना चाहिए।

इसके अतिरिक्त, सोशल मीडिया बच्चों के लिए आर्थिक शोषण का कारण भी बन रहा है। इन-ऐप परचेज़ और वर्चुअल गिफ्टिंग जैसी व्यवस्थाओं ने नाबालिगों को पैसे खर्च करने की आदत डाल दी है। कई बार यह खर्च उनकी आर्थिक क्षमता से कहीं अधिक होता है, जिससे परिवारों पर बोझ पड़ता है। सांस्कृतिक दृष्टि से भी यह प्रवृत्ति चिंताजनक है। हिंसा, अश्लीलता और असंस्कारी कंटेंट ने किशोरों के मन-मस्तिष्क को गहराई से प्रभावित किया है और पारंपरिक भारतीय मूल्यों से उन्हें दूर कर दिया है।

यदि भारत ने ऑनलाइन गेमिंग पर सख्ती दिखाते हुए रियल मनी गेमिंग को पूरी तरह प्रतिबंधित किया है तो अब समय है कि वही दृष्टिकोण सोशल मीडिया पर भी अपनाया जाए। इसके लिए सरकार को सबसे पहले आयु-आधारित प्रतिबंध लागू करना चाहिए। 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर पूर्ण रोक लगाई जाए और 16 से 18 वर्ष तक के किशोरों के लिए प्रतिदिन अधिकतम एक घंटे की सीमा तय की जाए। कंपनियों पर यह जिम्मेदारी डाली जाए कि वे आयु सत्यापन और स्क्रीन टाइम नियंत्रण सुनिश्चित करें। साथ ही, हानिकारक सामग्री के प्रसार पर कठोर दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए। एल्गोरिद्म आधारित डोपामीन ट्रैप यानी बार-बार दिखाए जाने वाले शॉर्ट वीडियो, रील्स और ट्रेंड्स को सीमित किया जाना चाहिए क्योंकि ये युवाओं को लगातार स्क्रीन से चिपकाए रखते हैं। इस दिशा में यूरोप और अमेरिका में भी बहस चल रही है, लेकिन भारत को ऑस्ट्रेलिया की तरह ठोस कदम उठाने होंगे।

शिक्षा और जागरूकता का पहलू भी उतना ही महत्वपूर्ण है। स्कूलों में डिजिटल साक्षरता और सोशल मीडिया व्यसन पर अध्याय जोड़े जाने चाहिए ताकि बच्चों को छोटी उम्र से ही इन खतरों की समझ हो। साथ ही युवाओं को विकल्प उपलब्ध कराना भी जरूरी है। कला, खेल, संगीत, हस्तशिल्प और सामुदायिक गतिविधियाँ इसका अच्छा विकल्प हैं। इसके अलावा सरकार द्वारा सुरक्षित भारतीय सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स को प्रोत्साहित करना चाहिए जो ज्ञान, संवाद और रचनात्मकता पर आधारित हों। यदि भारत समय रहते इस दिशा में कदम उठाता है तो इसके दूरगामी लाभ होंगे। युवाओं का मानसिक स्वास्थ्य बेहतर होगा, वे पढ़ाई और करियर पर अधिक ध्यान देंगे, परिवार और समाज में वास्तविक संबंध मजबूत होंगे और राष्ट्र की सांस्कृतिक दिशा सुरक्षित रहेगी। फेक न्यूज़ और नफ़रत की राजनीति का असर भी कम होगा और लोकतंत्र अधिक स्वस्थ बनेगा।

यहां कहना यही है कि जैसे भारत ने ऑनलाइन गेमिंग पर सख्ती दिखाकर यह संकेत दिया है कि वह युवाओं के भविष्य को लेकर गंभीर है। अब आवश्यकता है कि यही दृष्टिकोण सोशल मीडिया पर भी अपनाया जाए। युवा पीढ़ी राष्ट्र की रीढ़ है। यदि उसे डिजिटल गुलामी, व्यसन और मानसिक असंतुलन की ओर धकेल दिया गया तो यह केवल परिवारों का नहीं, पूरे राष्ट्र का संकट होगा। इसलिए भारत सरकार को ऑस्ट्रेलिया के उदाहरण से प्रेरणा लेकर, अपने संदर्भ के अनुसार, कठोर और स्पष्ट नीति तुरंत लागू करनी चाहिए। यही समय की मांग है और यही आने वाली पीढ़ियों के प्रति हमारी जिम्मेदारी भी है ।

(लेखिका, मध्य प्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग की सदस्य हैं।)

अग्नि-5 : भारत की रक्षा क्षमता में ऐतिहासिक छलांग

- डॉ. मयंक चतुर्वेदी

दुनिया भर में युद्ध और तनाव का माहौल है। रूस-यूक्रेन युद्ध थमने का नाम नहीं ले रहा, चीन-ताइवान विवाद गहराता जा रहा और मध्य-पूर्व में लगातार संघर्ष जारी है। ऐसे समय में भारत ने अपनी रक्षा क्षमता को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। 20 अगस्त 2025 को ओडिशा के चांदीपुर स्थित इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज से भारत ने लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि-5 का सफल परीक्षण किया। यह न केवल तकनीकी सफलता है, बल्कि भारत की बढ़ती सैन्य और सामरिक ताक़त का स्पष्ट संकेत भी है।

अग्नि-5 मिसाइल की सबसे बड़ी विशेषता इसकी लंबी दूरी की क्षमता है। यह मिसाइल 5000 किलोमीटर से अधिक की मारक क्षमता रखती है और परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। तीन चरण वाले ठोस ईंधन रॉकेट मोटर से उड़ान भरने वाली यह मिसाइल आधुनिक नेविगेशन सिस्टम से लैस है और इसमें मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री-एंट्री व्हीकल तकनीक का इस्तेमाल हुआ है। यानी यह एक साथ कई लक्ष्यों को साध सकती है। DRDO प्रमुख डॉ. समीर वी कामत ने कहना है कि अग्नि-5 का यह परीक्षण भारत की सामरिक शक्ति को नए स्तर पर ले जाता है। यह न केवल हमारी वैज्ञानिक क्षमता का प्रतीक है, बल्कि आने वाले समय में भारत की सुरक्षा का मजबूत आधार भी बनेगा।

उल्लेखनीय है कि भारत का मिसाइल कार्यक्रम कोई नया नहीं है। यह यात्रा 1980 के दशक में इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम से शुरू हुई थी। इसके साथ ही पूर्व राष्?ट्रपति एवं भारत के महान वैज्ञानिक डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम की अगुवाई में अग्नि श्रृंखला की नींव रखी गई थी। जिसने अपना साकार रूप लेना शुरू किया 2002 से, जब अग्नि-1 के साथ शुरुआत हुई जिसकी रेंज 700-900 किलोमीटर थी। इसके बाद अग्नि-2, अग्नि-3 और अग्नि-4 का विकास हुआ और हर नए संस्करण द्वारा भारत की क्षमता को एक कदम आगे बढ़ाया गया। अब अग्नि-5 उस श्रृंखला का सबसे आधुनिक और दूर तक मार करने वाला हथियार है। यह भारत को उन चुनिंदा देशों की कतार में खड़ा करता है जिनके पास इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलें हैं।

इस परीक्षण का महत्व केवल तकनीकी नहीं, बल्कि रणनीतिक भी है। पाकिस्तान के पास शहीन-III जैसी मिसाइलें हैं जिनकी रेंज लगभग 2750 किलोमीटर है। चीन के पास DF-41 है जिसकी क्षमता 12000 किलोमीटर तक मानी जाती है। अग्नि-5 भारत को इस सामरिक संतुलन में बराबरी की स्थिति देता है।

रक्षा विशेषज्ञ डॉ. राजेश शर्मा कहते हैं, यह मिसाइल किसी देश के खिलाफ नहीं, बल्कि भारत की डिटरेंस पॉलिसी का हिस्सा है। कहने का तात्पर्य है कि निवारण नीति किसी संभावित दुश्मन को हमला करने से रोकने के लिए पहले से ही तैयार की जाती है। यह एक ऐसी नीति है जिसमें किसी देश या संगठन द्वारा अपनी सैन्य शक्ति, आर्थिक शक्ति, या राजनीतिक प्रभाव का उपयोग करके दूसरे पक्ष को किसी गलत काम को करने से रोकने की कोशिश होती है। अत- इसका मकसद स्पष्ट है- कोई भी देश भारत के खिलाफ आक्रामक कदम उठाने से पहले सौ बार सोचे।

वे कहते हैं कि अग्नि-5 का सफल परीक्षण आत्मनिर्भर भारत की दिशा में बड़ी उपलब्धि है। यह हमारी वैज्ञानिक क्षमता का नतीजा है।

इससे निश्चित ही भारतीय सेना को और मजबूती मिलेगी। साथ ही यहां यह भी स्पष्ट करना जरूरी है कि भारत की नो फर्स्ट यूज़ परमाणु नीति हमेशा से स्पष्ट रही है।

यानी भारत परमाणु हथियारों का पहले इस्तेमाल नहीं करेगा, लेकिन हमला होने पर जवाब अवश्य दिया जाएगा। इस नीति के साथ अग्नि-5 जैसी मिसाइल भारत की सुरक्षा को विश्वसनीयता प्रदान करती है। यह मिसाइल यह सुनिश्चित करती है कि भारत पर कोई भी देश हमला करने से पहले उसकी ताकत को समझे। उन्होंने कहा, हम अब केवल इस दिशा में आत्मनिर्भर नहीं हुए हैं, बल्कि तकनीकी दृष्टि से विकसित देशों की बराबरी कर रहे हैं। अग्नि-5 इसका एक बड़ा प्रमाण है।

वैश्विक परिप्रेक्ष्य में देखें तो अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और ब्रिटेन जैसे देशों के पास ही अब तक 5000 किलोमीटर से अधिक दूरी की मिसाइलें थीं।

भारत अब इस क्लब में शामिल होकर अपनी स्थिति और मजबूत कर चुका है। यह न केवल भारत को एशिया में बल्कि वैश्विक स्तर पर भी एक भरोसेमंद और जिम्मेदार सामरिक शक्ति बनाता है। अत इस सफलता के बाद भारत का ध्यान अब भविष्य की परियोजनाओं पर है। अग्नि-6 की संभावित रेंज 8000 से 10000 किलोमीटर बताई जा रही है। साथ ही भारत हाइपरसोनिक मिसाइल तकनीक पर भी काम कर रहा है, जो आने वाले समय की जरूरत है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर यह प्रोजेक्ट सफल होते हैं तो भारत आने वाले दशक में दुनिया की शीर्ष तीन-चार मिसाइल शक्तियों में शामिल रहेगा।

अग्नि-5 का सफल परीक्षण आम जनता में भी गर्व का विषय बना हुआ है। सोशल मीडिया पर #Agni5 ट्रेंड करता दिखा। लोगों ने लिखा कि अब भारत को कोई भी आंख उठाकर देखने की हिम्मत नहीं करेगा। युवाओं ने इसे नई आज़ादी की सुरक्षा गारंटी बताया। कुल मिलाकर यह परीक्षण केवल एक मिसाइल का उड़ान भरना भर नहीं, बल्कि यह भारत के आत्मविश्वास, वैज्ञानिक प्रगति और सामरिक ताकत की उड़ान है । यह संदेश देती है कि भारत शांति चाहता है लेकिन अपनी सुरक्षा को लेकर सतर्क और तैयार है। अग्नि-5 के सफल परीक्षण के साथ भारत ने दुनिया को यह जता दिया है कि वह न केवल क्षेत्रीय बल्कि वैश्विक शक्ति के रूप में अपनी जगह बना चुका है।

दिल्ली को बचाना और बनाना ही दिल्ली की नई सरकार की जिम्मेदारी

मनोज कुमार मिश्र

इसी 17 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने दिल्ली-एनसीआर (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना) को करोड़ों की लागत से बनी दो बड़ी सड़कों का सौगात देते हुए कहा कि आने वाले दिनों में दिल्ली को विकास मॉडल बनाएंगे। इससे पहले भी दिल्ली पर यातायात का दबाव घटाने के लिए मोदी सरकार ने ईस्टर्न पेरिफेरियल एक्सप्रेसवे, वेस्टर्न पेरिफेरियल एक्सप्रेसवे, दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे और दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे बनाया। दिल्ली मेट्रो रेल दिल्ली और एनसीआर में 295 किलोमीटर तक बन चुका है।

चौथे चरण में इसमें 65 किलोमीटर और जुड़ जाएगा। दिल्ली मेट्रो से हर रोज यात्रा करने वालों की औसत संख्या पचास लाख से ऊपर है। यह संख्या 70 लाख भी पार कर जाती है।

दिल्ली-मेरठ नमो भारत रेल कोरिडोर के बाद दिल्ली- करनाल और दिल्ली- अरवल कोरिडोर बनने वाला है। इनसे यातायात सुगम होने के साथ-साथ इस इलाके का प्रदूषण भी कम होगा।

प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में यमुना की सफाई के प्रयास और गरीबों को पक्के मकान मिलने आदि का उल्लेख किया। जाहिर है कि केन्द्र से लेकर दिल्ली नगर निगम में भाजपा का ही शासन होने से दिल्ली को संवारने का दिल्ली की सरकार के पास भरपूर अवसर है। इन सभी के साथ-साथ 1985 में बनते ही दम तोड़ चुकी एनसीआर परियोजना पर नए सिरे से काम करने की जरूरत है।

जिस रफ्तार से दिल्ली और एनसीआर की राजधानी की आबादी बढ़ रही है, उसमें इसे बचाने और बनाने के लिए कुछ कठोर फैसले लेने होंगे।

दिल्ली की समस्या यह है कि दिल्ली का अपना ज्यादा कुछ नहीं है। मौसम भी पड़ोसी राज्यों पर निर्भर है। इतना ही नहीं दिल्ली अपनी जरूरत के संसाधनों के लिए भी दूसरे राज्यों पर निर्भर है। 1911 में दिल्ली देश की राजधानी बनी, आज इसकी आबादी करीब ढाई करोड़ है और एनसीआर की कुल आबादी की करीब साढ़े चार करोड़ हो गई है। एनसीआर की आबादी भी मूल रूप से दिल्ली की आबादी ही है। दिल्ली से बाहर बसने वाले ज्यादातर लोग आज भी दिल्ली से ही जुड़े हुए हैं। उनमें ज्यादातर के कारोबार या नौकरी दिल्ली में ही है।

राजधानी बनने के बाद 1915 में यमुना पार के 65 गांव दिल्ली में जुड़े। तब से दिल्ली का इलाका 1483 किलोमीटर ही बना हुआ है। निकट भविष्य में इसमें बढ़ोतरी होने की संभावना नहीं दिख रही है। दिल्ली की शासन व्यवस्था कम अधिकारों वाली विधानसभा, नगर निगम, महानगर परिषद से 1993 में विधानसभा बनने तक बदलती रही। अभी भी दिल्ली केन्द्र शासित प्रदेश है और जमीन और पुलिस केन्द्र सरकार के अधीन है।

दिल्ली को विकसित करने की जिम्मेदारी दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) को दी गई। 1959 से डीडीए लगातार दिल्ली का मास्टर प्लान बनाती रही है और दिल्ली में लगातार अनधिकृत कालोनी बनती गई। आज हालात ऐसे बन गए कि इन अनधिकृत निर्माण से दिल्ली नियोजित कम और अनियोजित ज्यादा बस गई। वोट और नोट की राजनीति में राजनीतिक दल के नेता भू माफिया, पुलिस और सरकारी भ्रष्ट कर्मचारियों के सहयोगी बन गए हैं।

दिल्ली पर से आबादी का दबाव घटाने और अब बेकार मानी जाने वाली डीडीए को सहयोग देने के लिए डीडीए की तरह केन्द्रीय शहरी विकास मंत्रालय के अधीन एनसीआर बनाने की योजना तो 1962 में ही बनी लेकिन उसका गठन 1985 में हो पाया।

केन्द्रीय शहरी विकास मंत्री इसके अध्यक्ष और दिल्ली के उप राज्यपाल के अलावा उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान के मुख्यमंत्री इसके सदस्य बनाए गए। एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी इसके सदस्य सचिव होते हैं। दिल्ली में एसडीएम से लेकर मुख्य सचिव के पद पर रहने वाले वरिष्ठ आईएएस अधिकारी ओमेश सहगल बोर्ड के सदस्य सचिव भी थे। सदस्य सचिव रहते हुए 1996 में उन्होंने एक मुलाकात में कहा था कि एनसीआर योजना तो फेल हो गई।

योजना पर कार्यान्वयन देरी से शुरू हुआ। 1985 में बोर्ड बनने पर 2001 की आबादी को लक्ष्य मानकर 1988 में काम शुरू हुआ तब तक योजना से ज्यादा आबादी हो गई थी। एनसीआर के शहरों और दिल्ली के बीच में एक किलोमीटर का गलियारा हरियाली के लिए छोड़ना था। यानी एनसीआर बसना था दिल्ली से हट कर, वे बस गए दिल्ली से सटकर।

इतना ही नहीं दिल्ली में एक तरह से हर किसी को हर जगह अवैध निर्माण की छूट दे दी गई। जो योजनाएं पहले से बनी उसमें खामियां ही खामियां हैं।

दुनिया के सबसे महंगे इलाके कनाट प्लेस में हर वर्ग के सरकारी कर्मचारियों के लिए फ्लैट बना दिए गए। यह तो मान भी लिया जाए कि गरीब लोगों को खाली जगह पर मुफ्त में सरकार आवास उपलब्ध करवाए लेकिन अमीरों की कई-कई करोड़ की एक-एक अवैध सैनिक फार्म हाऊस को भी न तोड़ा जाए, यह समझ से परे है। इतना ही नहीं, इसके लिए अदालत से संरक्षण लिया जाए तो भला दिल्ली अवैध निर्माणों से कैसे बच सकती है।

यह तो तय सा मान लिया गया है कि डीडीए अपना काम करने में विफल रही। न तो उसने ठीक से योजना बनाई और न ही दिल्ली की हजारों एकड़ जमीन की रक्षा कर पाई।

कई प्रयास के बावजूद डीडीए के अधिकारी यह तक नहीं बता पाते कि उनकी कितना जमीन पर कब्जा है और कितने वे कब्जे से छुड़ा पाए हैं।

डीडीए से भी बुरा हाल तो एनसीआर योजना बोर्ड का है। अब तो उसे केवल कागजों में ही मान लिया गया। 1985 में इसके गठन के समय इसे दिल्ली के 1483 के अलावा हरियाणा के छह जिलों के 13,413, उत्तर प्रदेश के चार जिलों के 10,885 और राजस्थान के 4,493 यानी 30, 240 वर्ग किलोमीटर इलाके को एनसीआर में शामिल किया गया। तब योजना थी कि 2001 में 20 लाख आबादी को इन इलाकों में भेजा जाए। इसके लिए इन सभी जगहों में दिल्ली जैसी सुविधा उपलब्ध कराई जाए। इन्हें चार क्षेत्रों में बांटा गया था।

हर क्षेत्र के लिए विस्तार से योजनाएं बनाई गई थी। इन इलाकों में स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार के अवसर बढाने के साथ-साथ आवागमन सुलभ कराना प्रमुख था। केन्द्र सरकार के अनेक दफ्तर भी दिल्ली से हटाने थे। इसमें कुछ तो सफलता मिली लेकिन अनियोजित तरीके से काम होने के चलते बहुत लाभ नहीं हुआ। इसके अलावा इन राज्यों के अनेक शहरों को भी मेगनेट (चुंबक) सेंटर की तरह विकसित किया जाना था।

तब 2001 में जो आबादी होने का अनुमान लगाया गया था, योजना के शुरू होने के समय ही दिल्ली की आबादी उतनी हो गई थी। ऐसा नहीं है कि बोर्ड की पूरी कवायत बेकार हो गई। अगर दिल्ली सरकार इस पर केन्द्र सरकार से ठीक से पहल करवाए तो लक्ष्य हासिल हो पाएगा। एनसीआर के हर राज्य की जरूरत इस योजना पर ठोस काम कराने की है लेकिन सबसे ज्यादा जरूरत दिल्ली को है। इसलिए अगुवाई दिल्ली को करनी होगी। जब प्रधानमंत्री की प्राथमिकता में दिल्ली है तो यह काम आसानी से शुरू हो सकता है। इससे ही दिल्ली सुंदर बनेगी और उसका भविष्य सुरक्षित रहेगा। इतना ही नहीं प्रधानमंत्री ने गांवों से पलायन रोकने के लिए गांवों को हर सुविधा से युक्त करना तय किया है। देश के ज्यादातर शहरों को बेहतर बनाने का काम तेज गति से हो रहा है। ऐसे में प्रधानमंत्री दिल्ली को विकास का मॉडल बनाना चाहते हैं तो इसका लाभ दिल्ली सरकार को उठाना चाहिए।

(लेखक, जाने-माने वरिष्ठ पत्रकार हैं।)

कबड्डी प्रतियोगिता : आरपी रस्तोगी, हनुमंत दत्त और शेरवानी इंटर कालेज बना विजेता

एजेंसी

प्रयागराज। आरपी रस्तोगी इंटर कालेज, पं. हनुमत दत्त त्रिपाठी इंटर कालेज इस्माइलगंज और शेरवानी इंटर कालेज मुकुन्दपुर ने गंगापार 'अ' सम्भागीय बालिका कबड्डी प्रतियोगिता में क्रमशः अंडर-14, 17 एवं अंडर-19 आयु वर्ग के खिताब पर कब्जा जमा लिया।पं. हनुमत दत्त त्रिपाठी इंटर कालेज इस्माइलगंज में हुई प्रतियोगिता में अंडर-14 आयु वर्ग में आरपी रस्तोगी इंटर कालेज विजेता, प्राथमिक विद्यालय सोरांव उपविजेता, अंडर-17 आयु वर्ग में पं. हनुमत दत्त त्रिपाठी इंटर कालेज इस्माइलगंज विजेता, आरपी रस्तोगी इंटर कालेज उपविजेता एवं अंडर-19 आयु वर्ग में शेरवानी इंटर कालेज मुकुन्दपुर विजेता एवं विक्रमादित्य इंटर कालेज गोरापुर उपविजेता रहा। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रो. राजेंद सिंह (रज्जू भईया) विश्वविद्यालय के खेल सचिव डॉ. भाष्कर शुक्ल, विशिष्ट अतिथि क्रीड़ा भारती काशी प्रांत के मंत्री वीरेन्द्र नाथ उपाध्याय, प्रबन्ध समिति के अध्यक्ष डॉ. अजय त्रिपाठी, प्रबन्धक महेश पति त्रिपाठी करारी इंटर कालेज कौशाम्बी के प्रबन्धक दिलीप कुमार जायसवाल, उप प्रबन्धक बृजेश पति त्रिपाठी ने खिलाड़ियों का पुरस्कार वितरित किये। विद्यालय के प्रधानाचार्य वेद प्रकाश मिश्र ने अतिथियों का स्वागत एवं विद्यालय के खेल अध्यापक एवं क्रिकेट कोच हसवीन अहमद ने कार्यक्रम का संचालन किया। इस मौके पर इरशाद मंसूरी, अली अहमद, राजेश सरोज, अनिल पटेल, अंकुर, जितेंद्र कुमार पटेल आदि मौजूद रहे।

गुजरात के जयेश सुथार ने पावरलिफ्टिंग में जीता गोल्ड, परिवार और कोच को दिया सफलता का श्रेय

गांधीनगर। नेपाल में 15 अगस्त से 17 अगस्त तक आयोजित एशियन पावरलिफ्टिंग चैंपियनशिप 2025 में गुजरात के मेहसाणा जिले के युवा खिलाड़ी जयेश जगदीशभाई सुथार ने स्वर्ण पदक जीता है। उन्होंने 53 किलो बॉडीवेट कैटेगरी के तहत बेंच प्रेस इवेंट में 75 किलो वजन उठाकर सबका ध्यान आकर्षित किया। भारत सहित पांच देशों के बीच आयोजित इस प्रतियोगिता में जयेश ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। जयेश ने अपनी उपलब्धि पर खुशी जताई। उन्होंने कहा कि प्रतियोगिता में मेडल जीतने से मुझे अत्यंत खुशी हुई है। मेरे परिवारजन तथा गांव के लोग भी गर्व और प्रसन्नता की भावना का अनुभव कर रहे हैं। इस सफलता के पीछे मेरे परिवार और मेरे कोच दिव्यभाई पटेल का बहुत बड़ा योगदान रहा है। जयेश सुथार वर्तमान में मेहसाणा के पास स्थित गणपत यूनिवर्सिटी में कंप्यूटर इंजीनियरिंग में डिप्लोमा की पढ़ाई कर रहे हैं। इसके साथ ही वे पिछले एक वर्ष से पावरलिफ्टिंग में लगातार मेहनत कर रहे हैं। खेल के प्रति उनका जुनून, अनुशासन और निरंतर अभ्यास ने ही उन्हें आज अंतरराष्ट्रीय मंच पर सफलता दिलाई है। खेल के दौरान उनके प्रदर्शन को देखकर प्रतियोगिता स्थल पर मौजूद दर्शकों में उत्साह का माहौल छा गया था।

एसएसबी के जवानों ने खो-खो प्रतियोगिता में दिखाया अपना जलवा

लखीमपुर खीरी। सशस्त्र सीमा बल द्वारा राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप आयोजित अंतर सीमान्त खो-खो प्रतियोगिता 2025 का आयोजन मंगलवार को हुआ। रोमांचक मुकाबले में विजयी टीमों को पुरस्कृत किया गया। पुरुष वर्ग में खेले गए मैचों में सीमान्त मुख्यालय पटना ने बल मुख्यालय नई दिल्ली को एक इनिंग्स व 25 अंकों से हराया। वहीं, सीमान्त मुख्यालय लखनऊ ने सीमान्त मुख्यालय रानीखेत को 6 अंकों से मात दी। तीसरे मुकाबले में सीमान्त मुख्यालय तेजपुर ने पटना को एक इनिंग्स व 18 अंकों से पराजित किया। महिला वर्ग में सीमान्त मुख्यालय पटना ने सीमान्त मुख्यालय तेजपुर को एक इनिंग्स व 41 अंकों से हराकर शानदार जीत दर्ज की। सीमान्त मुख्यालय लखनऊ ने सिलिगुरी को 8 अंकों से मात दी। वहीं, रानीखेत ने तेजपुर को एक इनिंग्स व 34 अंकों से परास्त किया। सेमीफाइनल मुकाबले भी घोषित कर दिए गए हैं। पुरुष वर्ग में लखनऊ का सामना सिलिगुरी से होगा जबकि दूसरा मैच तेजपुर व रानीखेत के बीच खेला जाएगा। महिला वर्ग में लखनऊ का मुकाबला पटना से तथा गुवाहाटी का रानीखेत से होगा। प्रतियोगिता के दौरान बड़ी संख्या में छात्र दर्शक के रूप में मौजूद रहे।

इंग्लिश टीम जनवरी 2026 में करेगी श्रीलंका का दौरा, विश्व कप की तैयारियों को मिलेगा बल

कोलंबो (श्रीलंका)। इंग्लैंड क्रिकेट टीम जनवरी 2026 में श्रीलंका का दौरा करेगी, जहां वह सीमित ओवरों की श्रृंखला खेलेगी। यह दौरा आगामी आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप की तैयारियों का अहम हिस्सा होगा। दौरे की शुरुआत 22 जनवरी से तीन मैचों की वनडे श्रृंखला के साथ होगी, जिसके बाद 30 जनवरी से तीन मैचों की टी20 अंतरराष्ट्रीय श्रृंखला खेली जाएगी। भारत और श्रीलंका द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित होने वाले टी20 विश्व कप से पहले यह दौरा इंग्लैंड को उपमहाद्वीपीय परिस्थितियों में खेलने का अनुभव देगा। इंग्लैंड इससे पहले 2009 और 2022 में खिताब जीत चुका है और अब तीसरी बार विश्व चैंपियन बनने का लक्ष्य साधेगा। गौरतलब है कि इंग्लैंड सात साल बाद श्रीलंका में सीमित ओवरों की श्रृंखला खेलेगा। पिछला दौरा 2018 में हुआ था, जिसमें इंग्लैंड ने वनडे श्रृंखला 3-1 से जीती थी और एकमात्र टी20 मैच पर भी कब्जा जमाया था। दोनों टीमों की आखिरी भिड़ंत टी20 प्रारूप में 2022 विश्व कप (ऑस्ट्रेलिया) में हुई थी, जहां इंग्लैंड ने ग्रुप चरण के मुकाबले में श्रीलंका को चार विकेट से हराया था और आगे चलकर खिताब भी अपने नाम किया।

लीग्स कप 2025: सुआरेज के दो गोलों से इंटर मियामी की जीत

एजेंसी

मियामी। इंटर मियामी ने अपने स्टार स्ट्राइकर लुइस सुआरेज के दम पर लीग्स कप क्वार्टर फाइनल में टाइग्रेस यूएएनएल को 2-1 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली। 38 वर्षीय उरुग्वे स्ट्राइकर ने दोनों हाफ में पेनल्टी पर गोल दागे और लियोनेल मेसी की गैरमौजूदगी में टीम के लिए हीरो बने। मेसी मांसपेशियों में खिंचाव के कारण इस मुकाबले से बाहर रहे। हालांकि, वे 2 अगस्त को चोटिल होने के बाद पिछले हफ्ते लॉस एंजिलिस गैलेक्सी के खिलाफ लौटे थे और सब्सटीट्यूट के रूप में उतरकर गोल भी किया था। लेकिन क्वार्टर फाइनल में कोच ने उन्हें आराम देने का फैसला किया। मैच का पहला गोल 20वें मिनट में आया जब टाइग्रेस डिफेंडर जेवियर एक्विनो के हैंडबॉल पर रेफरी ने पेनल्टी दी और सुआरेज ने इसे गोल में बदल दिया। इसके

बाद मैदान पर गरमा-गरमी भी देखने को मिली, लेकिन सुआरेज ने साथी खिलाड़ियों को शांत किया। हाफटाइम पर इंटर मियामी के कोच जेवियर माशेरानो को रेफरी से बहस करने पर लाल कार्ड दिखाकर मैदान से बाहर भेज दिया गया। 67वें मिनट में एंजेल कोरिया ने दो डिफेंडरों को छकाते हुए गोल दागकर टाइग्रेस को बराबरी दिलाई। लेकिन 87वें मिनट में एक बार फिर एक्विनो के हाथ से गेंद लगने पर पेनल्टी मिली और सुषह्द्द5 ने गोलकीपर नहुएल गुजमान को धोखा देते हुए दूसरा गोल कर जीत पक्की कर दी। इंटर मियामी ने 2023 में मेसी के पहले MLS सीजन में लीग्स कप जीता था और अब टीम खिताब दोबारा हासिल करने की राह पर है। लीग्स कप के इस दौर के अन्य क्वार्टर फाइनल मुकाबलों में टोलुका बनाम ऑरलैंडो सिटी, एलए गैलेक्सी बनाम पाचुका और सिएटल साउंडर्स बनाम प्यूब्ला के मैच खेले जाने हैं। ट्रॉफी के अलावा इस टूर्नामेंट से कॉनकाकाफ चैंपियंस कप का टिकट भी दांव पर है। दोनों फाइनलिस्ट और तीसरे स्थान का विजेता इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट के लिए क्वालिफाई करेंगे, जबकि लीग्स कप चैंपियन सीधे चैंपियंस कप के राउंड ऑफ 16 में प्रवेश पाएगा।

पीकेएल 12 : दबंग दिल्ली केसी के कप्तान बने आशु मलिक

एजेंसी

नई दिल्ली। प्रो कबड्डी लीग (पीकेएल) के सीज़न 12 में दबंग दिल्ली केसी एक बार फिर नई ऊर्जा के साथ उतरने को तैयार है। टीम ने पिछले सीज़न की तरह इस बार भी युवा रेडर आशु मलिक को कप्तान बनाए रखने की घोषणा की है। आशु सीज़न 11 में टॉप स्कोरर थे। सिर्फ 22 साल की उम्र में ही आशु ने लगातार शानदार प्रदर्शन और परिपक्व नेतृत्व क्षमता दिखाई है। दिल्ली की टीम पिछले छह सीज़नों से लगातार प्लेऑफ़ तक पहुंची है और इस बार भी आशु की अगुवाई में खिताब जीतने की उम्मीद कर रही है।टीम के सीईओ प्रशांत मिश्रा ने कहा, यह सीज़न हमारे लिए बेहद अहम है। लगातार छह बार प्लेऑफ़ तक पहुंचने के बाद अब हमारा लक्ष्य खिताब जीतना है। इसके लिए मजबूत नेतृत्व की जरूरत होती है और आशु ने खुद को इस भूमिका के लिए साबित किया है। हमें पूरा विश्वास है कि वह टीम को नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगे।मुख्य कोच जोगिंदर नरवाल ने भी आशु पर भरोसा जताते हुए कहा,आशु मलिक ने पिछले सीज़न में लगातार टीम को आगे बढ़ाया और एक अच्छे लीडर के रूप में खुद को स्थापित किया।

इस बार हमारा लक्ष्य सिर्फ प्लेऑफ़ तक सीमित नहीं है बल्कि चैंपियनशिप जीतना है। दबंग दिल्ली केसी अपना पहला मुकाबला 2 सितंबर को बेंगलुरु बुल्स के खिलाफ खेलेगी। आशु मलिक की कप्तानी में टीम इस सीज़न में नई ऊर्जा और जीत के जज्बे के साथ मैदान में उतरेगी।

सिंकफील्ड कप में गुकेश ने दूसरे दौर में अब्दुसत्तोरोव को हराया

एजेंसी

मुरादाबाद। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जनपद में आरएसडी स्पोर्ट्स एकेडमी कांठ रोड में गुरुवार को जिला स्तरीय रोल बॉल की अंडर 11 और 17 टीम का चयन किया गया। जिसमें जिले के 10 से अधिक स्कूलों के 50 खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया। जिला रोल बाल सचिव शाहवेज अली ने बताया कि अंडर 11 बालक वर्ग में अविराज सिंह, सक्षम, पुरु भटनागर, अगस्त्या सिंह, यश्मित, युग अग्रवाल का चयन हुआ। वहीं अंडर 17 बालक वर्ग में विवान अग्रवाल, विहान अग्रवाल, सिद्धांत कुमार, आयुष वर्मा, राघव विश्नोई, शुभ सिंघल, वैकुंठ यादव, वेदांग यादव, पर्व, दिव्यांश, प्रीत चौधरी का चयन हुआ। अंडर 17 बालिका वर्ग वैष्णवी कश्यप, प्रभुश्री, चारु, पीहू सिंघल, कृतिका पाल का चयन हुआ। चयन प्रक्रिया कोच शाहवेज अली, अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी सचिन सैनी व राष्ट्रीय रेफरी तरुण

यादव ने किया। जिला सचिव ने बताया कि 16वीं मिनी व 18वीं जूनियर बालक एवं बालिका उत्तर प्रदेश रोल बॉल प्रतियोगिता आने वाली 30 अगस्त से 1 सितम्बर 2025 तक लखनऊ चौक स्टेडियम में आयोजित होगी। जिसमें उत्तर प्रदेश के लगभग 20 जिलों की 40 टीमें हिस्सा लेंगी। इस अवसर पर आरएसडी एकेडमी के निदेशक डा. विनोद कुमार, डा. जी कुमार, डा अजय शर्मा, डा. गरिमा शर्मा, डा. गौरव कुमार आदि ने सभी चयनित खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दीं व उनका मनोबल बढ़ाया।

महिला एशिया कपः भारतीय हॉकी टीम घोषित, सलीमा टेटे के हाथों में होगी कमान

एजेंसी

नई दिल्ली। हॉकी इंडिया ने गुरुवार को हांगझोउ (चीन) में 5 से 14 सितंबर तक होने वाले महिला एशिया कप 2025 के लिए 20 सदस्यीय भारतीय महिला हॉकी टीम की घोषणा कर दी। यह टूर्नामेंट बेहद अहम है क्योंकि इसके विजेता को सीधे एफआईएच महिला हॉकी विश्व कप 2026 का टिकट मिलेगा। भारत को पूल-बी में जगह मिली है, जहां उसका मुकाबला जापान, थाईलैंड और सिंगापुर से होगा। टीम अपना पहला मैच 5 सितंबर को थाईलैंड के खिलाफ खेलेगी। इसके बाद 6 सितंबर को जापान से और 8 सितंबर को सिंगापुर से भिड़ेगी। टीम की कमान सलीमा टेटे को सौंपी गई है। मुख्य कोच हरेंद्र सिंह ने कहा, हमने जिस टीम का चयन किया है, उसमें अनुभव और युवा खिलाड़ियों का संतुलन है। खिलाड़ी आक्रामक और अनुशासित हॉकी खेलने के लिए तैयार हैं। एशिया कप सिर्फ एक प्रतिष्ठित खिताबी टूर्नामेंट ही नहीं बल्कि विश्व कप क्वालिफिकेशन का

भी मौका है। हर मैच हमारे धैर्य, फिटनेस और रणनीति की परीक्षा होगा और हमें विश्वास है कि यह टीम भारत को गर्व महसूस कराएगी।

भारतीय टीम इस प्रकार है-

गोलकीपर- बनसारी सोलंकी बिचु देवी खरिबाम।

डिफेंडर- निक्की प्रधान, उदिता, मनीषा चौहान, ज्योति, सुमन देवी थौदम और ईशिका चौधरी।

मिडफील्डर- सलीमा टेटे (कप्तान), नेहा,लालरेमसियामी, शर्मिला देवी, सुनेलिता टोप्पो और वैष्णवी विट्ठल फाल्के।

फॉरवर्डस- नवनीत कौर, संगीता कुमारी, मुमताज़ खान, दीपिका, ब्यूटी डुंगडुंग और रुताजा ददासो पिसाल।

'खेलो इंडिया वॉटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल 2025' में उतरेगा देश का युवा जोश, मप्र के खिलाड़ी भी ले रहे भाग

एजेंसी

भोपाल। जम्मू-कश्मीर के श्रीनगर की शान मानी जाने वाली डल झील अगले तीन दिनों तक खेल और उत्सव के रंगों में रंगी रहेगी। इस ऐतिहासिक और खूबसूरत झील में आज गुरुवार से शुरू हुआ पहला खेलो इंडिया वॉटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल-2025 न केवल खिलाड़ियों के हुनर की परीक्षा है, बल्कि जल क्रीड़ाओं को नई पहचान देने का भी प्रयास है। तीन दिवसीय इस आयोजन में देश के कोने-कोने से आए करीब 400 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। रोइंग, क्याकिंग-केनोइंग, वॉटर स्कीइंग, ड्रैगन बोट रेस और शिकारा स्प्रिंट जैसी स्पर्धाएं झील की लहरों पर खिलाड़ियों की ताकत और संतुलन की कहानी लिखेंगी। शिकारा स्प्रिंट को डेमो खेल के रूप में रखा गया है, जो कश्मीर की सांस्कृतिक पहचान को खेल के मंच पर भी प्रदर्शित करेगा। इस आयोजन में मध्य प्रदेश का 54 सदस्यीय दल भी शामिल है, जिसमें 44 खिलाड़ी और

10 सहयोगी स्टाफ हैं। प्रदेश के खिलाड़ी इस राष्ट्रीय स्तर की महत्वपूर्ण प्रतियोगिता में रोइंग और क्याकिंग-केनोइंग स्पर्धाओं में राज्य का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। दल का नेतृत्व वॉटर स्पोर्ट्स रोइंग अकादमी के मुख्य प्रशिक्षक दलबीर सिंह कर रहे हैं। खेल एवं युवा कल्याण मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने मप्र के खिलाड़ियों को लेकर कहा है कि उन्हें उम्मीद है कि खिलाड़ी शानदार प्रदर्शन कर प्रदेश का गौरव बढ़ाएँगे।

डल झील का नाम सुनते ही पर्यटकों की आंखों के सामने शिकारे और हाउसबोट की तस्वीर उभर आती है। झील की यही पहचान अब खेलों के नए इतिहास से जुड़ रही है। इस आयोजन से जहां खिलाड़ियों को अंतरराष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं जैसा अनुभव मिलेगा, वहीं पर्यटन को भी नया आयाम मिलेगा। आयोजकों का कहना है कि झील का शांत और आकर्षक वातावरण खिलाड़ियों को प्रेरित करेगा और दर्शकों के लिए यह खेल किसी उत्सव से कम नहीं होगा। इस फेस्टिवल में कुल 5 खेलों का आयोजन किया जा रहा है। इनमें रोइंग, क्याकिंग-केनोइंग (पदकीय स्पर्धा), वॉटर स्कीइंग, ड्रैगन बोट रेस और शिकारा स्प्रिंट (डेमो खेल) शामिल हैं। आयोजन में देश के सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। डल झील की प्राकृतिक खूबसूरती और पर्यावरणीय महत्व को देखते हुए इस आयोजन को पर्यटन और खेलों का संगम माना जा रहा है। आयोजन समिति का मानना है।

ओलंपिक चैम्पियन इमान खलीफ ने संन्यास की खबरों का किया खंडन

एजेंसी

नई दिल्ली। अल्जीरियाई मुक्केबाज़ और ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता इमान खलीफ ने अपने पूर्व मैनेजर द्वारा किए गए दावे को खारिज कर दिया कि वह बॉक्सिंग से संन्यास ले रही हैं। पेरिस ओलंपिक में महिलाओं की 66 किग्रा भारवर्ग में स्वर्ण जीतने वाली खलीफ ने सोशल मीडिया पर लिखा, मैं स्पष्ट करना चाहती हूं कि मेरे संन्यास की खबरें पूरी तरह झूठी हैं। 26 वर्षीय खलीफ ने अपने पूर्व मैनेजर नासिर यस्फाह पर भरोसा तोड़ने और झूठे बयान देने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, यह व्यक्ति अब किसी भी रूप में मेरा प्रतिनिधित्व नहीं करता। मैंने कभी संन्यास की

घोषणा नहीं की। मैं अपने खेल करियर के प्रति पूरी तरह समर्पित हूं। अल्जीरिया और क़तर में नियमित अभ्यास कर रही हूं और आने वाली प्रतियोगिताओं की तैयारी कर रही हूं। गौरतलब है कि फ्रांसीसी अख़बार नाइस मातिन ने उनके पूर्व मैनेजर के हवाले से दावा किया था कि खलीफ ने बॉक्सिंग छोड़ दी है। विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप 4 से 14 सितंबर तक लिवरपूल में आयोजित की जानी है, जिसके लिए पंजीकरण की अंतिम तिथि सोमवार तक है।

महिल द हंड्रेड : सुपरचार्जर्स ने लंदन स्पिरिट को 8 विकेट से हराया

एजेंसी

लॉर्ड्स। महिला द हंड्रेड टूर्नामेंट में रात खेले गए मुकाबले में फीबी लिचफील्ड की तूफानी अर्धशतकीय पारी और एनेबल सदरलैंड के ऑलराउंड प्रदर्शन (3/20 और नाबाद 29 रन) की बदौलत नॉर्दर्न सुपरचार्जर्स ने लंदन स्पिरिट को आठ विकेट से करारी शिकस्त दी। इस जीत के साथ सुपरचार्जर्स ने इस सीजन में अपनी चौथी जीत दर्ज करते हुए अंक तालिका में दूसरा स्थान हासिल कर लिया। पहले बल्लेबाजी का फैसला करने उतरी लंदन स्पिरिट की शुरुआत खराब रही। केट क्रॉस और ग्रेस बैलिंजर ने शुरुआती झटके दिए। जॉर्जिया रेडमेन (21 रन) ने पारी संभालने की कोशिश की, लेकिन दूसरे छोर से सहयोग नहीं मिल पाया। निकोल कैरी

और एनेबल सदरलैंड ने मिलकर पांच विकेट चटकाए, वहीं बैलिंजर ने भी दो विकेट झटके। हालांकि, इज़ी वोंग (24 रन) और चार्ली डीन ने 33 रन की अहम साझेदारी की, लेकिन दोनों धीमी गति से खेलते हुए टीम को केवल 90/8 तक ही पहुंचा पाई। लक्ष्य का पीछा करते हुए सुपरचार्जर्स को शुरुआत में झटका जरूर लगा जब रेबेका टायसन ने दोनों ओपनरों को सस्ते में पवेलियन भेजा। लेकिन इसके बाद लिचफील्ड और सदरलैंड ने कोई और मौका नहीं दिया। लिचफील्ड ने वोंग के एक ओवर में लगातार तीन चौके जमाकर लय पकड़ी और फिर आक्रामक खेल जारी रखा। सदरलैंड ने संयमित पारी खेलते हुए बीच-बीच में बड़े शॉट लगाए और वोंग की गेंद पर शानदार छक्का भी लगाया। आखिरकार, लिचफील्ड (नाबाद 55 रन) ने 66वीं गेंद पर चौका लगाकर टीम को जीत दिलाई।

संक्षिप्त स्कोरकार्ड:

लंदन स्पिरिट - 90/8 (100 गेंदों में) - जॉर्जिया रेडमेन 21, इज़ी वोंग 24; एनेबल सदरलैंड 3/20, ग्रेस बैलिंजर 2/12।

नॉर्दर्न सुपरचार्जर्स - 93/2 (66 गेंदों में) - फीबी लिचफील्ड 55*, एनेबल सदरलैंड 29*; रेबेका टायसन 2/6

डल झील में पहले खेलो इंडिया वॉटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल में मप्र के 44 खिलाड़ी करेंगे प्रतिभाग

एजेंसी

भोपाल। जम्मू-कश्मीर स्थित प्रतिष्ठित डल झील में प्रथम 'खेलो इंडिया वॉटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल-2025' का आयोजन 21 से 23 अगस्त तक किया जा रहा है। तीन दिवसीय इस आयोजन में मध्य प्रदेश के 44 प्रतिभाशाली खिलाड़ी एवं 10 सहायक स्टाफ सहित कुल 54 सदस्यों का दल शामिल होगा। मप्र राज्य वॉटर स्पोर्ट्स रोइंग अकादमी के मुख्य प्रशिक्षक दलबीर सिंह भी दल में शामिल हैं। मुख्य प्रशिक्षक दलबीर सिंह ने बताया कि खेलो इंडिया वॉटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल 2025 में तीन खेलों का अभियान किया जा रहा हैं, जिसमें मध्य प्रदेश के खिलाड़ी दो खेलों रोइंग और क्याकिंग-केनोइंग में राज्य का प्रतिनिधित्व करेंगे। प्रदेश के खेल एवं युवा कल्याण मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने खेलो इंडिया वॉटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल- 2025 जम्मू-कश्मीर में प्रतिभागिता करने जा रहे मध्य प्रदेश के सभी वॉटर स्पोर्ट्स के प्रतिभावन खिलाड़ियों को शानदार खेल का प्रदर्शन कर विजेता बनने के लिए उत्साहित करते हुये शुभकामनाएं दी हैं। गौरतलब है कि खेलो इण्डिया वॉटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल राष्ट्रीय स्तर की महत्वपूर्ण खेल प्रतियोगिता है। प्रतियोगिता में 5 खेलों

रोइंग, क्याकिंग केनोइंग (पदकीय स्पर्धा), वॉटर स्कीइंग, डेगन बोट और शिकारा स्प्रिंट (डेमो खेल) शामिल किये गये हैं। आयोजन में देश के 36 राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के लगभग 400 खिलाड़ी प्रतिभागिता कर रहे हैं।

खेलों से खिलाड़ी अपने शहर, प्रदेश और देश का नाम रोशन करते हैं- देवेंद्र कुमार पांडे

एजेंसी

मुरादाबाद। हेविट मुस्लिम इंटर कालेज मुरादाबाद में तीन दिवसीय जनपदीय विद्यालयीय कुश्ती प्रतियोगिता (बालक व बालिका) का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि जिला विद्यालय निरीक्षक देवेंद्र कुमार पांडे ने पहलवान खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर प्रतियोगिता का शुभारम्भ किया। इस अवसर पर जिला विद्यालय निरीक्षक ने छात्रों को खेल भावना से खेलने के लिए प्रोत्साहित करते हुए कहा कि खेलों के माध्यम से खिलाड़ी अपने शहर, प्रदेश और देश का नाम रोशन करते हैं। कार्यक्रम की अध्यक्षता विद्यालय प्रबंध समिति के अध्यक्ष चौधरी जईम अहमद ने की। सभी अतिथियों, कुश्ती संघ के पदाधिकारी, शारीरिक शिक्षा शिक्षकों-शिक्षिकाओं का कार्यक्रम के सफल आयोजन हेतु प्रधानाचार्य नोमान जलील ने धन्यवाद दिया। कार्यक्रम का संचालन हेविट मुस्लिम इंटर कॉलेज के प्रवक्ता मसरूर हसन ने किया। कार्यक्रम की संयोजिका कौशल्या कन्या इंटर कालेज की प्रधानाचार्य डा मधुबाला त्यागी ने छात्रों को खेलों में हार जीत से ऊपर उठकर खेल भावना से खेलने एवं जी जान लगाकर अपना सर्वश्रेष्ठ देने के लिए छात्रों को आह्वान किया। इस अवसर पर मंडलीय क्रीड़ा सचिव बंश बहादुर का भी सक्रिय योगदान रहा। अंडर 17 वर्ग में 65 किलोग्राम भार वर्ग में जुबेर अली ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया।

डायमंड लीग के अंतिम चरण में भाग नहीं लेंगे नीरज चोपड़ा

नई दिल्ली। हाई-प्रोफाइल डायमंड लीग फाइनल में पहले ही पहुंच चुके स्टार भारतीय भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा बेल्जियम के ब्रुसेल्स में होने वाली प्रतिष्ठित श्रृंखला के अंतिम चरण में भाग नहीं लेंगे। 14 डायमंड लीग मुकाबलों में से चार में पुरुषों की भाला फेंक प्रतियोगिता शामिल है। चोपड़ा ने केवल दो में भाग लिया, लेकिन 28 अगस्त को स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख में होने वाले डायमंड लीग फाइनल के लिए क्वालीफाई कर गए। उन्होंने 16 अगस्त को सिलेसिया चरण में भी हिस्सा नहीं लिया था। 27 वर्षीय मौजूदा विश्व चैंपियन ने मई में दोहा डायमंड लीग में 90.23 मीटर भाला फेंककर प्रतिष्ठित 90 मीटर का आंकड़ा पार किया, लेकिन जर्मनी के जूलियन वेबर के बाद दूसरे स्थान पर रहे। इसके बाद उन्होंने जून में 88.16 मीटर भाला फेंककर पेरिस डायमंड लीग जीता। ब्रुसेल्स चरण के बाद शीर्ष छह धावक ज्यूरिख में होने वाले डायमंड लीग फ़ाइनल में पहुंचेंगे। चोपड़ा ने आखिरी बार 5 जुलाई को बेंगलुरु में एनसी

क्लासिक में भाग लिया था, जहाँ उन्होंने 86.18 मीटर भाला फेंककर खिताब जीता था। इस सीज़न में अब तक उन्होंने कुल छह स्पर्धाओं में भाग लिया है, जिनमें से चार में उन्हें जीत मिली है और दो बार वे दूसरे स्थान पर रहे हैं। चोपड़ा 13-21 सितंबर तक टोक्यो में होने वाली विश्व चैंपियनशिप में अपना खिताब बरकरार रखेंगे। डायमंड लीग वैश्विक एथलेटिक्स में एक विशिष्ट एक दिवसीय प्रतियोगिता श्रृंखला है। 27 और 28 अगस्त को ज्यूरिख में आयोजित होने वाले दो दिवसीय डायमंड लीग फ़ाइनल के लिए क्वालीफाई करने हेतु, खिलाड़ी 14-सीरीज़ की प्रतियोगिताओं में अंकों के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं। प्रत्येक विजेता को प्रतिष्ठित डायमंड ट्रॉफी, 30,000 अमेरिकी डॉलर की पुरस्कार राशि और विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप के लिए वाइल्ड कार्ड प्रदान किया जाता है। दूसरे स्थान पर रहने वाले को 12,000 अमेरिकी डॉलर और तीसरे स्थान पर रहने वाले को 7,000 अमेरिकी डॉलर का पुरस्कार मिलेगा। पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा 28 अगस्त को होगी। इस वर्ष 32 में से आठ स्पर्धाओं - 100 मीटर पुरुष, 1500 मीटर पुरुष, 400 मीटर बाधा दौड़ पुरुष, पोल वॉल्ट पुरुष, 100 मीटर महिला, 100 मीटर बाधा दौड़ महिला, 3000 मीटर महिला और लंबी कूद महिला - के विजेताओं को बढ़ी हुई पुरस्कार राशि मिलेगी। इन स्पर्धाओं में विजेता को 50 हजार अमेरिकी डॉलर, जबकि दूसरे और तीसरे स्थान पर रहने वाले को क्रमशः 20 हजार अमेरिकी डॉलर और 10 हजार अमेरिकी डॉलर मिलेंगे।

विक्रान इंजीनियरिंग लिमिटेड का आईपीओ 26 अगस्त को खुलेगा

एजेंसी

नई दिल्ली। विक्रान इंजीनियरिंग लिमिटेड का आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) 26 अगस्त को खुलेगा। निवेशक इसमें निवेश के लिए 29 अगस्त तक बोली लगा सकते हैं। इसके लिए मूल्य का दायरा (प्राइस बैंड) 92-97 रुपये प्रति शेयर तय किया गया है। विक्रान इंजीनियरिंग लिमिटेड ने एक बयान में बताया कि उसका इश्यू 26 अगस्त को खुलकर 29 अगस्त, 2025 को बंद होगा। कंपनी ने 1 रुपये अंकित मूल्य वाले अपने इस आईपीओ के लिए मूल्य का दायरा 92-97 रुपये प्रति शेयर तय किया है। यह आईपीओ 721 करोड़ रुपये के नए शेयरों और प्रवर्तकों द्वारा 51 करोड़ रुपये की बिक्री पेशकश (ओएफएस) का संयोजन है। निवेशक इसमें न्यूनतम 148 इक्विटी शेयरों और उसके बाद 148 इक्विटी शेयरों के गुणकों के लिए बोली लगा सकते हैं। कंपनी नए शेयरों की बिक्री से प्राप्त 541 करोड़ रुपये की राशि का उपयोग कार्यशील पूंजी आवश्यकताओं के वित्तपोषण और शेष राशि का उपयोग सामान्य कंपनी कामकाज के लिए करेगी। मुंबई स्थित विक्रान इंजीनियरिंग लिमिटेड तेजी से बढ़ती भारतीय इंजीनियरिंग, खरीद और निर्माण कंपनियों में से एक है। एनटीपीसी लिमिटेड, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड, नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड आदि इसके सरकारी क्षेत्र के प्रमुख ग्राहक हैं।

पीएलआई योजना से दुर्लभ बीमारियों की दवाओं की कीमतें 90फीसदी तक घटीं

नई दिल्ली। सरकार की प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव (पीएलआई) योजना ने दुर्लभ बीमारियों की दवाओं की कीमतों में भारी कमी लाकर मरीजों को बड़ी राहत दी है। इस योजना के तहत देश में इन दवाओं के उत्पादन को बढ़ावा मिला है, जिससे आयात पर निर्भरता कम हुई है और कीमतें 90फीसदी तक नीचे आ गई हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों के अनुसार, पीएलआई योजना के तहत कई भारतीय फार्मा कंपनियों ने दुर्लभ बीमारियों के इलाज के लिए आवश्यक दवाओं का उत्पादन शुरू किया है। इससे न केवल इन दवाओं की उपलब्धता बढ़ी है, बल्कि उनकी कीमतें भी बहुत कम हो गई हैं। यह उन लाखों मरीजों के लिए एक बड़ी राहत है, जिन्हें पहले इन महंगी दवाओं के लिए संघर्ष करना पड़ता था।

रूस-भारत व्यापार ने तोड़े रिकॉर्ड

नई दिल्ली। विदेश मंत्री एस. जयशंकर की रूस यात्रा के दौरान भारत और रूस के बीच अंतर-सरकारी आयोग की 26वीं बैठक आयोजित हुई। इस बैठक में व्यापार, ऊर्जा, कृषि और विदेश मंत्री एस. जयशंकर इन दिनों रूस यात्रा पर हैं। उन्होंने रूस के प्रथम उप-प्रधानमंत्री डेनिस मंटुरोव से भेंट की और दोनों नेताओं ने मिलकर 26वीं भारत-रूस अंतर-सरकारी आयोग की बैठक की सह-अध्यक्षता की।इस बैठक में दोनों नेताओं ने व्यापार, अर्थव्यवस्था, विज्ञान-तकनीक और सांस्कृतिक साझेदारी पर विस्तार से चर्चा की। साथ ही कृषि, ऊर्जा, उद्योग, कौशल विकास, गतिशीलता, शिक्षा और संस्कृति जैसे कई क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया गया। बैठक के दौरान जयशंकर ने भारत की ओर से रिश्तों को और मजबूत करने के लिए कई अहम सुझाव भी पेश किए।

ईपीएफओ के सदस्यों की संख्या में जून में रिकॉर्ड 21.9 लाख की वृद्धि

नई दिल्ली। देश में इस साल जून में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के सदस्यों की संख्या में रिकॉर्ड 21.89 लाख की वृद्धि हुई। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने बताया कि अप्रैल 2018 में ट्रैकिंग शुरू होने के बाद से यह सदस्यों की संख्या में सबसे बड़ी बढ़ोतरी है। इस साल मई की तुलना में अंशधारकों की संख्या 9.14 प्रतिशत और पिछले साल जून की तुलना में 13.46 प्रतिशत बढ़ी है। इस साल जून में ईपीएफओ से 10.62 लाख नये अंशधारक जुड़े जो मई के मुकाबले 12.68 प्रतिशत अधिक है। नये अंशधारकों में 18 से 25 साल की आयु वर्ग में 6.39 लाख हैं। फिर से जुड़ने वाले अंशधारकों को मिलाकर इस आयु वर्ग में जून में सदस्यों की संख्या 9.72 लाख बढ़ी। सभी आयु वर्ग के दुबारा सदस्य बनने वाले अंशधारकों की संख्या 16.93 लाख रही। मंत्रालय ने बताया कि जून में महिला अंशधारकों की संख्या में 4.72 लाख की वृद्धि हुई जो मई के मुकाबले 11.11 प्रतिशत अधिक है। अंशधारकों की संख्या में महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 20.03 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इसके बाद क्रमशः कर्नाटक, तमिलनाडु, गुजरात, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और तेलंगाना का स्थान रहा।

जीएसटी दरों में बदलाव से आम आदमी, किसानों और मध्यम वर्ग को फायदा होगा: सीतारमण

एजेंसी

नई दिल्ली। केंद्रीय एवं कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) सुधारों में दरों में फेरबदल से आम आदमी, किसानों, मध्यम वर्ग और एमएसएमई को राहत मिलेगी। इनमें कर दरों में कटौती और व्यवसायों के लिए अनुपालन बोझ को कम करना शामिल है। उन्होंने बताया कि नए जीएसटी सुधार आम आदमी, किसानों, मध्यम वर्ग, एमएसएमई को अधिक राहत प्रदान करेंगे।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में जीएसटी परिषद द्वारा क्षतिपूर्ति उपकर, स्वास्थ्य एवं जीवन बीमा तथा दरों के युक्तिकरण पर राज्यों के मंत्री समूहों (जीओएम) को संबोधित कर रही थीं। इस बैठक में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी, गोवा के मुख्यमंत्री, बिहार के उप-मुख्यमंत्री और तीनों जीओएम में शामिल राज्यों के वित्त मंत्री भी

उपस्थित थे। सीतारमण ने राज्यों के मंत्रियों के समूहों के जीएसटी व्यवस्था में व्यापक सुधारों के लिए सरकार की योजनाओं की जानकारी दी। केंद्रीय वित्त मंत्री ने बैठक में इस बात पर जोर दिया कि केंद्र सरकार का यह प्रस्ताव भारत के आत्मनिर्भर भारत बनने की यात्रा में जीएसटी सुधारों की अगली पीढ़ी की शुरुआत करने के दृष्टिकोण से है। वित्त मंत्री की जीएमओ के साथ बैठक में तीन प्रमुख स्तंभों पर आधारित प्रस्तावित सुधारों पर चर्चा हुई। ये सुधार इनपुट टैक्स क्रेडिट संचयन में कमी लाने और घरेलू मूल्यवर्धन को बढ़ावा देने के लिए उल्टे शुल्क ढांचों को सही करेंगे। सरल अनुपालन और कम विवादों के लिए वर्गीकरण संबंधी मुद्दों का समाधान करेंगे और उद्योग के विश्वास और दीर्घकालिक योजना को मजबूत करने के लिए जीएसटी नीति में स्थिरता और पूर्वानुमेयता सुनिश्चित करेंगे। बैठक में कहा गया कि दरों के युक्तिकरण का उद्देश्य आम आदमी, किसानों, मध्यम वर्ग और एमएसएमई को अधिक राहत प्रदान करना है। इसके साथ ही एक सरलीकृत, पारदर्शी और विकासोन्मुखी कर व्यवस्था सुनिश्चित करना है। इससे सामर्थ्य में वृद्धि होगी, उपभोग को बढ़ावा मिलेगा और आवश्यक एवं आकांक्षी वस्तुओं को व्यापक जनसंख्या तक अधिक पहुंच प्राप्त होगी। इसके अलावा आगामी जीएसटी सुधार निर्बाध, तकनीक-चालित और समयबद्ध पंजीकरण सुनिश्चित करेंगे, त्रुटियों और विसंगतियों को कम करने के लिए पहले से भरे हुए रिटर्न की शुरुआत करेंगे और तेज, स्वचालित रिफंड को सक्षम करेंगे। इन सभी का उद्देश्य अनुपालन को सरल बनाना, व्यवसायों का समर्थन करना और जीवन और व्यापार करने में समग्र सुगमता को बढ़ाना है।

स्टोर आधारित से एकीकृत इकाई लाइसेंसिंग की ओर बढ़ने की जरूरत : रवि गांधी

एजेंसी

नई दिल्ली। रिलायंस रिटेल के अध्यक्ष रवि गांधी ने कहा कि आधुनिक संगठित खुदरा क्षेत्र के तेजी से विकास के साथ इस क्षेत्र में नियामक सुधारों की जरूरत है। यह स्टोर आधारित लाइसेंसिंग से इकाई आधारित एकीकृत लाइसेंसिंग की ओर बढ़ रहा है। वह उद्योग निकाय फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (फिक्की) की ओर से आज एक होटल में आयोजित 'मासमेराइज 2025' कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। खुदरा, एफएमसीजी और ई-कॉमर्स पर आधारित सम्मेलन का मुख्य विषय मेक इन इंडिया: एफएमसीजी, खुदरा और ई-कॉमर्स के भविष्य को सशक्त बनाना रखा है। उन्होंने कहा कि स्टोर खोलने में तेजी लाने के लिए लाइसेंस-पूर्व निरीक्षण के स्थान पर लाइसेंस पश्चात निरीक्षण की ओर बढ़ने की भी जरूरत है।उन्होंने जोर देकर कहा कि इस बदलाव से संगठित खुदरा विक्रेताओं के लिए व्यापार करने में आसानी में उल्लेखनीय सुधार होगा। रवि गांधी ने कहा कि आज देश में (खुदरा क्षेत्र से संबंधित) सभी कानून व्यक्तिगत दुकानों के लिए बनाए गए हैं। सभी लाइसेंस व्यक्तिगत स्टोर आधारित हैं।

ईपीएफओ ने जून महीने में रिकॉर्ड 21.89 लाख सदस्य जोड़े

एजेंसी

नई दिल्ली। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने जून महीने में रिकॉर्ड 21.89 लाख सदस्यों को जोड़े हैं। ये अप्रैल 2018 में पेरोल यानी नियमित वेतन पर रखे गए लोगों की संख्या जारी होने की शुरुआत के बाद सबसे अधिक है।

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने बताया कि ईपीएफओ ने जून, 2025 में शुद्ध रूप से 21.89 लाख सदस्यों को जोड़ा है, जो सालाना आधार पर 13.46 फीसदी और मासिक आधार पर 9.14 फीसदी अधिक है। यह आंकड़ा बढ़ते रोजगार के अवसरों और कर्मचारी लाभों के बारे में बढ़ती जागरूकता को रेखांकित करता है। ईपीएफओ ने जून में लगभग 10.62 लाख नए ग्राहकों को नामांकित किया, जो पिछले महीने मई की तुलना में 12.68 फीसदी की वृद्धि और जून, 2024 की तुलना में 3.61 फीसदी की वृद्धि

को दर्शाता है। नए ग्राहकों में यह वृद्धि बढ़ते रोजगार अवसरों, कर्मचारी लाभों के बारे में बढ़ती जागरूकता और ईपीएफओ के सफल आउटरीच कार्यक्रमों के कारण है। आंकड़ों के मुताबिक जून में 18-25 आयु वर्ग का प्रभुत्व है। ईपीएफओ ने 18-25 आयु वर्ग में इस दौरान 6.39 लाख नए ग्राहक को जोड़े, जो जून 2025 में जुड़े कुल नए ग्राहकों का 60.22 फीसदी है। जून में जुड़े 18-25 आयु वर्ग के नए ग्राहकों की संख्या पिछले महीने मई की तुलना में 14.08 फीसदी अधिक है। जून में लगभग 3.02 लाख नई महिला ग्राहक ईपीएफओ में शामिल हुईं। यह आंकड़ा मई, 2025 के पिछले महीने की तुलना में 14.92 फीसदी की वृद्धि को दर्शाता है। यह जून 2024 की तुलना में 1.34 फीसदी की साल-दर-साल वृद्धि भी दर्शाता है। आंकड़ों के मुताबिक शीर्ष पांच राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों ने लगभग 61.51 फीसदी शुद्ध पेरोल वृद्धि दर्ज की, जिससे इस दौरान कुल 13.46 लाख शुद्ध पेरोल जुड़े। इन सभी राज्यों में महाराष्ट्र जून के दौरान 20.03 फीसदी शुद्ध पेरोल जोड़कर सबसे आगे है।

लगातार दो दिन की तेजी के बाद डॉलर के मुकाबले 11 पैसे की कमजोरी के साथ बंद हुआ रुपया

एजेंसी

नई दिल्ली,। लगातार दो दिन तक तेजी दिखाने के बाद भारतीय मुद्रा रुपये में आज डॉलर की तुलना में कमजोरी आ गई। माना जा रहा है कि कच्चे तेल की कीमत में उछाल आने, और डॉलर की मांग में तेजी आने के कारण आज रुपये पर दबाव बढ़ गया। मुद्रा बाजार में पूरे दिन उतार-चढ़ाव का सामना करने के बाद भारतीय मुद्रा आज डॉलर की तुलना में 11 पैसे की कमजोरी के साथ 87.07 (अनंतिम) के स्तर पर बंद हुई। इसके पहले पिछले कारोबारी दिन मंगलवार को भारतीय मुद्रा 86.96 रुपये प्रति डॉलर के स्तर पर बंद हुई थी। रुपये ने आज के कारोबार की शुरुआत भी कमजोरी के साथ ही की थी। इंटरबैंक फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में भारतीय मुद्रा ने आज सुबह डॉलर के मुकाबले 20 पैसे की गिरावट के साथ 87.16 रुपये के स्तर से कारोबार की शुरुआत की थी। आज का कारोबार शुरू होने के थोड़ी देर बाद ही रुपया फिसल कर 87.18 के स्तर तक भी पहुंचा, लेकिन इसके बाद बाजार में बने सकारात्मक माहौल के कारण रुपये की चाल में तेजी आ गई। मुद्रा बाजार में डॉलर की आवक कारोबार में रुपये ने डॉलर की तुलना में कमजोरी दिखाई, लेकिन यूरो की तुलना में रुपया आज मजबूती के साथ बंद होने में सफल रहा। वहीं ब्रिटिश पौंड (जीबीपी) की तुलना में रुपया सपाट

बढ़ने पर रुपये ने निचले स्तर से 20 पैसे की रिकवरी करके 86.98 के स्तर तक पहुंचने में भी सफलता हासिल की। हालांकि ये स्थिति अधिक देर तक टिक नहीं सकी। मुद्रा बाजार में एक बार फिर डॉलर की मांग में तेजी आने पर रुपये की चाल में कमजोरी आ गई। पूरे दिन के कारोबार के बाद डॉलर की तुलना में रुपये ने 11 पैसे की गिरावट के साथ 87.07 के स्तर पर आज के कारोबार का अंत किया। मुद्रा बाजार के आज के स्तर पर कारोबार करता रहा। आज के कारोबार के बाद ब्रिटिश पौंड (जीबीपी) की तुलना में भारतीय मुद्रा 117.67 रुपये से लेकर 117.24 रुपये तक के दायरे में कारोबार करने के बाद बिना किसी बदलाव के कल के स्तर पर यानी 117.55 रुपये (अनंतिम) के स्तर पर ही बंद हुई। दूसरी ओर, यूरो की तुलना में रुपया आज 16 पैसे की उछाल के साथ 101.39 (अनंतिम) के स्तर तक पहुंच गया।

सर्राफा बाजार की गिरावट पर ब्रेक, सोना और चांदी की बढ़ी कीमत

एजेंसी

नई दिल्ली। घरेलू सर्राफा बाजार में लगातार जारी गिरावट पर आज ब्रेक लगता नजर आ रहा है। आज सोना 500 रुपये से लेकर 600 रुपये प्रति 10 ग्राम तक महंगा हो गया है। इसी तरह चांदी के भाव में आज 900 रुपये प्रति किलोग्राम की मजबूती दर्ज की गई है। कीमत में उछाल आने के कारण आज देश के ज्यादातर सर्राफा बाजारों में 24 कैरेट सोना 1,00,750 रुपये से लेकर 1,00,900 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर कारोबार कर रहा है। इसी तरह 22 कैरेट सोना भी आज 92,300 रुपये से लेकर 92,450 रुपये प्रति 10 ग्राम के बीच बिक रहा है। सोना की तरह ही चांदी के भाव में भी तेजी आने के कारण कारण ये चमकीली धातु दिल्ली सर्राफा बाजार में आज 1,16,000 रुपये प्रति किलोग्राम के स्तर पर बिक रही है।

दिल्ली में 24 कैरेट सोना आज 1,00,900 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर कारोबार कर रहा है, जबकि 22 कैरेट सोने की कीमत 92,450 रुपये प्रति 10 ग्राम दर्ज की गई है। वहीं, देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में 24 कैरेट सोना 1,00,750 रुपये प्रति 10 ग्राम और 22 कैरेट सोना 92,300 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर बिक रहा है। इसी तरह अहमदाबाद में 24 कैरेट सोने की रिटेल कीमत 1,00,800 रुपये प्रति 10 ग्राम और 22 कैरेट सोने की कीमत 92,350 रुपये प्रति 10 ग्राम दर्ज की गई है। इन प्रमुख शहरों के अलावा चेन्नई में 24 कैरेट सोना आज 1,00,750 रुपये प्रति 10 ग्राम की कीमत पर और 22 कैरेट सोना 92,300 रुपये प्रति 10 ग्राम की कीमत पर बिक रहा है। कोलकाता में भी 24 कैरेट सोना 1,00,750 रुपये प्रति 10 ग्राम और 22 कैरेट सोना 92,300 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर कारोबार कर रहा है। लखनऊ के सर्राफा बाजार में 24 कैरेट सोना आज 1,00,900 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर और 22 कैरेट सोना 92,450 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर बिक रहा है। पटना में 24 कैरेट सोने की कीमत 1,00,800 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर है, जबकि 22 कैरेट सोना 92,350 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर बिक रहा है। जयपुर में 24 कैरेट सोना 1,00,900 रुपये प्रति 10 ग्राम और 22 कैरेट सोना 92,450 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर बिक रहा है।देश के अन्य राज्यों की तरह कर्नाटक, तेलंगाना और ओडिशा के सर्राफा बाजार में भी आज सोने के भाव में मजबूती आई है। इन तीनों राज्यों की राजधानियों बेंगलुरु, हैदराबाद और भुवनेश्वर में 24 कैरेट सोना आज 1,00,750 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर कारोबार कर रहा है। इसी तरह इन तीनों शहरों के सर्राफा बाजारों में 22 कैरेट सोना 92,300 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर बिक रहा है।

देश के आठ बुनियादी उद्योगों की वृद्धि दर जुलाई में दो फीसदी पर

एजेंसी

नई दिल्ली। देश के आठ प्रमुख बुनियादी उद्योगों की वृद्धि दर जुलाई में सुस्त पड़कर दो फीसदी रही। पिछले साल इसी अवधि में इन क्षेत्रों का उत्पादन 6.3 फीसदी बढ़ा था। इससे पिछले महीने जून में आठ बुनियादी उद्योगों का उत्पादन दर 2.2 फीसदी रहा था। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने एक बयान में बताया कि जुलाई में आठ प्रमुख बुनियादी उद्योगों में से कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस और रिफाइनरी उत्पादों जैसे चार प्रमुख क्षेत्रों के उत्पादन में गिरावट दर्ज की गई।

हालांकि, इस दौरान इस्पात, सीमेंट, उर्वरक और बिजली के उत्पादन में सकारात्मक वृद्धि दर्ज हुई है। मंत्रालय के मुताबिक चालू वित्त वर्ष 2025-26 की अप्रैल-जुलाई चार महीने की अवधि में आठ प्रमुख बुनियादी ढांचा उद्योगों का उत्पादन 1.6 फीसदी बढ़ा है, जबकि पिछले वित्त वर्ष 2024-25 की इसी अवधि में बुनियादी उद्योगों की वृद्धि 6.3 फीसदी रही थी। देश के आठ प्रमुख बुनियादी उद्योगों में कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी उत्पाद, उर्वरक, इस्पात, सीमेंट और बिजली शामिल है। इन आठ कोर इंडस्ट्रीज का संयुक्त सूचकांक भारत के औद्योगिक उत्पादन सूचकांक के कुल भार का 40.27 फीसदी होता है।

सीसीपीए ने भ्रामक विज्ञापनों के लिए रैपिडो पर लगाया 10 लाख रुपये का जुर्माना

एजेंसी

नई दिल्ली। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) ने भ्रामक विज्ञापनों के लिए ऑनलाइन कंपनी रोपेन ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड(रैपिडो) पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। मंत्रालय के मुताबिक इस तरह के विज्ञापन अक्सर झूठे, भ्रामक और उपभोक्ताओं के प्रति अनुचित होते हैं। नियामक ने रैपिडो को तत्काल प्रभाव से भ्रामक विज्ञापन बंद करने का भी निर्देश दिया है। उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के मुताबिक सीसीपीए ने उपभोक्ता अधिकारों के संरक्षण की दिशा में एक और कार्रवाई करते हुए रैपिडो को भ्रामक विज्ञापन प्रकाशित करने और अनुचित व्यापार व्यवहार के लिए 10 लाख रुपये का जुर्माना

भरने का आदेश दिया है। सीसीपीए ने रैपिडो को उन ग्राहकों को बिना किसी देरी के पैसे वापस देने का निर्देश भी दिया है, जिन्होंने कंपनी के पांच मिनट में ऑटो या फिर पाएं 50 रुपये ऑफर का इस्तेमाल किया था, लेकिन उन्हें यह राशि मिली नहीं। राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन (एनसीएच) के आंकड़ों के अनुसार अप्रैल, 2023 से मई, 2024 के बीच रैपिडो के खिलाफ 575 शिकायतें और जून, 2024 से जुलाई, 2025 के बीच 1,224 शिकायतें प्राप्त हुई हैं। पिछले दो वर्षों में एनसीएच को रैपिडो के खिलाफ उपभोक्ताओं की शिकायतों की संख्या में वृद्धि हुई है। सीसीपीए ने उपभोक्ताओं से ऐसे विज्ञापनों के प्रति सतर्क रहने का आग्रह करते हुए कहा कि यदि भ्रामक विज्ञापनों या अनुचित व्यापार प्रथाओं से संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ता है, तो वे निम्न कार्रवाई कर सकते हैं। राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन (1915) पर कॉल करें और शिकायत दर्ज करने के लिए एनसीएच ऐप या वेबसाइट का उपयोग करें।

भारत और यूरेशियन आर्थिक संघ ने एफटीए पर वार्ता शुरू करने के लिए संदर्भ शर्तों पर हस्ताक्षर किए

एजेंसी

नई दिल्ली। भारत और यूरेशियन आर्थिक संघ (ईएईयू) ने मॉस्को में मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) पर आधिकारिक तौर पर बातचीत शुरू करने के लिए संदर्भ शर्तों (टीओआर) पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के मुताबिक यह हस्ताक्षर मॉस्को में भारत सरकार के वाणिज्य विभाग के अतिरिक्त सचिव अजय भादू और यूरेशियन आर्थिक आयोग (ईईसी) के व्यापार नीति विभाग के उप निदेशक मिखाइल चेरेकाएव के बीच हुए हैं। मंत्रालय के मुताबिक भारत और यूरेशियन आर्थिक संघ (ईएईयू) के बीच प्रस्तावित एफटीए निर्यात को बढ़ावा देगा। ईएईयू में आर्मेनिया, बेलारूस, कजाकिस्तान, किर्गिज गणराज्य और रूसी संघ शामिल हैं। भारत-ईएईयू का व?यापार 2024 में 69 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया था, जो 2023 की तुलना में 7 फीसदी की वृद्धि है।भारत सरकार के वाणिज्य विभाग के अपर सचिव अजय भादू ने अपनी यात्रा के दौरान ईईसी के व्यापार प्रभारी मंत्री आंद्रेई स्लेपनेव से भी मुलाकात की। उन्होंने कहा कि प्रस्तावित एफटीए निर्यात को बढ़ावा देगा, एमएसएमई को समर्थन देगा और बाजार पहुंच में विविधता लाएगा। प्रस्तावित एफटीए से भारतीय

निर्यातकों के लिए बाजार पहुंच का विस्तार होने, नए क्षेत्रों और भौगोलिक क्षेत्रों में विविधीकरण का समर्थन करने, गैर-बाजार अर्थव्यवस्थाओं के खिलाफ प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को महत्वपूर्ण लाभ मिलने की उम्मीद है।

वाणिज्यिक कोयला खदानों की 13वें दौर की नीलामी शुरू करेगा कोयला मंत्रालय

नई दिल्ली। कोयला मंत्रालय 21 अगस्त को नई दिल्ली में वाणिज्यिक कोयला खदानों की नीलामी के 13वें दौर की शुरुआत करने जा रहा है। इस दौर में कुल 34 कोयला खदानों की पेशकश की जाएगी। इससे पहले कोयला मंत्रालय ने 27 मार्च को 12वें दौर की नीलामी की थी। कोयला मंत्रालय ने एक बयान में बताया कि वाणिज्यिक कोयला खदानों के 13वें दौर की नीलामी में केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री जी. किशन रेड्डी मुख्य अतिथि और कोयला एवं खान राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे बतौर विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे। इस दौर में कुल 34 कोयला खदानों की पेशकश की जाएगी, जिनमें 5 सीएमएसपी कोयला खदानें और 29 एमएमडीआर कोयला खदानें शामिल हैं। इनमें से 12 पूरी तरह से अन्वेषित और 22 आंशिक रूप से अन्वेषित हैं। इसके अलावा 12वें दौर के दूसरे प्रयास के तहत कोयला मंत्रालय 3 कोयला खदानों की पेशकश कर रहा है, जिनमें से 2 सीएमएसपी और 1 एमएमडीआर है। कोयला मंत्रालय 2020 से वाणिज्यिक कोयला खदानों की नीलामी कर रहा है। मंत्रालय के मुताबिक इससे निवेश की संभावना और बढ़ेगी और घरेलू आपूर्ति मजबूत होगी।

हरित हाइड्रोजन निर्यात का वैश्विक केंद्र बनना है भारत का लक्ष्य: श्रीपद येसो नाइक

एजेंसी

नई दिल्ली। केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्यमंत्री श्रीपद येसो नाइक ने कहा कि भारत का लक्ष्य हरित हाइड्रोजन निर्यात का वैश्विक केंद्र बनना है। उन्होंने कहा कि 2030 तक दुनियाभर की मांग का लगभग 10 फीसदी निर्यात करना भी है। केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्यमंत्री श्रीपद नाइक ने यहां के फिक्की फेडरेशन हाउस, तानसेन मार्ग में आयोजित फिक्की ग्रीन हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2025 को संबोधित करते हुए ये घोषणा की। उन्होंने कहा कि हम भारत को न केवल एक प्रमुख उत्पादक बनाना चाहते हैं, बल्कि हरित हाइड्रोजन निर्यात का एक वैश्विक केंद्र भी बनाना चाहते हैं। फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (फिक्की) की ओर से आयोजित इस सम?मेलन को संबोधि?त करते हुए श्रीपद नाइक ने बताया कि भारत ने अपने महत्वाकांक्षी हरित हाइड्रोजन उत्पादन लक्ष्यों की दिशा में पर्याप्त प्रगति की है, राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत 19 कंपनियों को 862,000 टन प्रति वर्ष उत्पादन क्षमता पहले ही प्रदान की जा चुकी है। उन्होंने बताया कि भारत का लक्ष्य वैश्विक हरित हाइड्रोजन की लगभग 10 फीसदी मांग को पूरा करना है, जिसके 2030 तक 100 मिलियन मीट्रिक टन से अधिक होने की उम्मीद है। सरकार ने 15 कंपनियों को 3,000 मेगावाट इलेक्ट्रोलाइज़र निर्माण क्षमता प्रदान की है, जो

इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण औद्योगिक विकास को दर्शाता है। नाइक ने कहा, हम भारत को न केवल एक प्रमुख उत्पादक बनाना चाहते हैं, बल्कि हरित हाइड्रोजन निर्यात का एक वैश्विक केंद्र भी बनाना चाहते हैं। उन्होंने तेज़ी से बढ़ते वैश्विक बाजार में खुद को एक विश्वसनीय निर्यातक के रूप में स्थापित करने की देश की रणनीति का जिक्र किया। उन?होंने कहा कि भारत की नवीकरणीय ऊर्जा उपलब्धियों को हरित हाइड्रोजन महत्वाकांक्षाओं की नींव बताया। जून 2025 तक कुल स्थापित नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता लगभग 237 गीगावाट तक पहुंच गई, जिसमें 119 गीगावाट सौर ऊर्जा, 52 गीगावाट पवन ऊर्जा और 49 गीगावाट बड़े जलविद्युत ऊर्जा शामिल हैं। नाइक ने कहा कि 8.78 गीगावाट परमाणु ऊर्जा के साथ, गैर-जीवाश्म ईंधन स्रोत अब कुल स्थापित बिजली उत्पादन क्षमता का 50 फीसदी से अधिक प्रतिनिधित्व करते हैं।

पाकिस्तान नेशनल असेंबली में महमूद खान अचकजई और सीनेट में आजम खान स्वाति विपक्ष के नेता नामित

एजेंसी

इस्लामाबाद (पाकिस्तान)। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के संस्थापक इमरान खान ने महमूद खान अचकजई को नेशनल असेंबली में विपक्ष के नेता और आजम खान स्वाति को सीनेट में विपक्ष के नेता के रूप में नामित किया है। पीटीआई महासचिव सलमान अकरम राजा ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि पार्टी ने संसद के दोनों सदनों के लिए अपने फैसले को अंतिम रूप दे दिया है। एआरवाई न्यूज चैनल की खबर के अनुसार इमरान खान का फैसला नेशनल असेंबली में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के तीन प्रमुख पदों विपक्ष के नेता, संसदीय नेता और उप संसदीय नेता के आधिकारिक रूप से रिक्त घोषित होने के बाद आया है। पाकिस्तान चुनाव आयोग (ईसीपी) ने नौ मई के दंगों के मामलों में दोषी ठहराए जाने के बाद नेशनल असेंबली में विपक्ष के नेता उमर अयूब और सीनेट में विपक्ष के नेता शिबली फराज सहित पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के सांसदों को अयोग्य घोषित किया जा चुका है। अयोग्य घोषित सांसदों में नेशनल असेंबली सदस्य जरताज गुल, एमएनए राय हैदर अली, एसआईसी अध्यक्ष हामिद रजा और राय हसन नवाज शामिल हैं। इसके अलावा, सांसद अंसार इकबाल, जुनैद अफजल साही और मोहम्मद मुर्तजा इकबाल को भी अयोग्य घोषित किया जा चुका है। फैसलाबाद स्थित एक आतंकवाद-रोधी अदालत (एटीसी) ने 9 मई के दंगों के मामलों में उमर अयूब, जरताज गुल, शिबली फराज सहित पीटीआई नेताओं को 10 साल की जेल की सजा सुनाए जाने के बाद अयोग्यता की अधिसूचना जारी की गई।

बांग्लादेश सुप्रीम कोर्ट में बीएनपी नेता तारिक व अन्य को बरी करने के मामले में होगी सुनवाई

ढाका (बांग्लादेश)। बांग्लादेश का उच्चतम न्यायालय बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) के कार्यवाहक अध्यक्ष तारिक रहमान व अन्य को उच्च न्यायालय से बरी करने के मामले पर कल भी सुनवाई करेगा। उच्चतम न्यायालय ने आज चौथे दिन भी उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ दायर अपीलों पर सुनवाई की। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सैयद रेफात अहमद की अध्यक्षता वाली छह सदस्यीय अपीलीय खंडपीठ ने गुरुवार को सुनवाई फिर से शुरू करने का निर्णय लिया। द डेली स्टार अखबार की खबर के अनुसार उच्च न्यायालय ने 21 अगस्त, 2004 के ग्रेनेड हमले के मामलों की सुनवाई 22 नवंबर, 2024 पूरी कर अगले माह पहली दिसंबर को फैसला सुनाते हुए आरोपित बीएनपी के कार्यवाहक अध्यक्ष तारिक रहमान, पूर्व राज्य मंत्री लुत्फोज्जमां बाबर और अन्य को बरी कर दिया था। उच्चतम न्यायालय की अपीलीय खंडपीठ में आज सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के वकील एसएम शाहजहां ने कहा कि ग्रेनेड हमले की घटना या साजिश में आरोपितों की संलिप्तता और घटनास्थल पर उनकी मौजूदगी का कोई सबूत नहीं है।

सिडनी में कार के नदी में गिरने से दो लोग लापता

सिडनी। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में रात एक कार के मैकडोनाल्ड नदी में गिर जाने से दो लोग लापता हो गए। न्यू साउथ वेल्स (एनएसडब्ल्यू) की पुलिस ने गुरुवार को एक बयान में कहा कि स्थानीय समयानुसार देर रात लगभग 11:50 बजे सिडनी से 70 किलोमीटर उत्तर-पश्चिम में सेंट एल्बंस शहर के पास मैकडोनाल्ड नदी में एक कार के गिरने की सूचना मिलने पर आपातकालीन सेवाओं को बुलाया गया था। दुर्घटना के बाद अधिकारी घटनास्थल पर पहुँचे। उन्होंने बताया कि कार के नदी में गिर जाने से उसमें सवार 20 वर्षीय एक व्यक्ति तैरकर नदी के किनारे पहुँच गया था, जबकि वाहन में सवार दो अन्य लोगों का कोई पता नहीं चल पाया। एनएसडब्ल्यू राज्य आपातकालीन सेवा और ग्रामीण अग्निशमन सेवा ने लापता लोगों की तलाश शुरू कर दी है। अधिकारियों ने न्यू साउथ वेल्स में भारी बारिश के कारण लोगों को संभावित बाढ़ के लिए तैयार रहने हेतु व्यापक चेतावनी जारी की। मौसम विज्ञान ब्यूरो ने बुधवार को कहा कि राज्य में गुरुवार को भारी बारिश होने की संभावना है।

पूर्व राष्ट्रपति बोल्सोनारो ने अर्जेंटीना से मांगी थी शरण, अब ब्राजील में झेलेंगे मुकदमा

ब्रासीलिया। ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो ने अर्जेंटीना से राजनीतिक शरण मांगी थी, ताकि वे ब्राजील में चल रहे मुकदमों से बच सकें। यह खुलासा अर्जेंटीना के पूर्व राष्ट्रपति अल्बर्टो फर्नांडीज ने किया है। फर्नांडीज के अनुसार, बोल्सोनारो ने उन्हें संदेश भेजकर शरण देने का अनुरोध किया था, लेकिन फर्नांडीज ने उनका अनुरोध ठुकरा दिया। बोल्सोनारो पर आरोप है कि उन्होंने 2022 के चुनाव परिणामों को पलटने की कोशिश की थी। अगर वे दोषी पाए जाते हैं तो उन्हें कई साल की जेल हो सकती है। इस बीच, ब्राजील के सुप्रीम कोर्ट ने बोल्सोनारो के खिलाफ जांच के आदेश दिए हैं, और उन पर मुकदमा चलाया जाएगा। फर्नांडीज के इस खुलासे से बोल्सोनारो की मुश्किलें और भी बढ़ गई हैं।

टेक्सास विधानसभा ने पुनर्सीमांकन मानचित्र को मंजूरी दी, रिपब्लिकन की राह हुई आसान

एजेंसी

ऑस्टिन (टेक्सास) संयुक्त राज्य अमेरिका। टेक्सास विधानसभा ने पुनर्सीमांकन मानचित्र को मंजूरी प्रदान कर दी। इस मंजूरी को राष्ट्रपति डोनाल्ड जे. ट्रंप की बड़ी जीत बताया जा रहा है। सीनेट में गुरुवार को इस पर मतदान होगा। माना जा रहा है सीनेट की मुहर लगने के बाद मध्यावधि चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी को अमेरिकी सदन (हाउस) की पांच और सीटें जीतने की राह आसान हो जाएगी। द न्यूयॉर्क टाइम्स की खबर के अनुसार, टेक्सास विधानसभा में आठ घंटे से ज्यादा समय तक चली तनावपूर्ण और भावनात्मक बहस के बाद अंतिम मतदान, 88-52, दलीय आधार पर हुआ। इसके बाद डेमोक्रेटिक पार्टी के सदस्य हंगामा करते हुए सदन से बहिर्गमन कर गए। सीनेट में गुरुवार शाम तक पुनर्सीमांकन मानचित्र पर मतदान

होने की उम्मीद है। सीनेट की मंजूरी के बाद इसे सप्ताह के अंत तक गवर्नर ग्रेग एबॉट के पास हस्ताक्षर के लिए भेजा जाएगा। उधर, कैलिफोर्निया विधानमंडल में गुरुवार को नए कांग्रेसी नक्शे पर मतदान होने की उम्मीद है। इसे रिपब्लिकन के कब्जे वाली पांच सीटों को डेमोक्रेट्स के पक्ष में करने के लिए तैयार किया गया है। ट्रंप और उनके सहयोगी पहले से ही टेक्सास से आगे बढ़कर इंडियाना, मिसौरी और फ्लोरिडा सहित अन्य रिपब्लिकन राज्यों की ओर देख रहे हैं। कैलिफोर्निया के अलावा डेमोक्रेटिक नेता 2026 के मध्यावधि चुनाव से पहले इलिनॉय, मैरीलैंड और 2028 के राष्ट्रपति चुनाव से पहले न्यूयॉर्क पर नजर गड़ाए हुए हैं। कॉर्पस क्रिस्टी से रिपब्लिकन राज्य प्रतिनिधि टॉड हंटर ने हाउस बिल 4 के नाम से जाने जाने वाले मानचित्र विधेयक का परिचय देते हुए कहा, इस योजना का मूल लक्ष्य रिपब्लिकन के राजनीतिक प्रदर्शन में सुधार करना है। उन्होंने कहा कि अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के अनुसार हम कांग्रेस के जिलों के निर्धारण में राजनीतिक प्रदर्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। और हमने यही किया है।

उत्तर कोरिया के नेता की बहन किम ने दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्युंग के शांति प्रस्ताव की आलोचना की

एजेंसी

प्योंगयांग (उत्तर कोरिया)। उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग-उन की प्रभावशाली बहन किम यो-जोंग ने दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्युंग के सुलह प्रस्ताव की आलोचना की। उन्होंने कहा कि सियोल, प्योंगयांग का राजनयिक समकक्ष नहीं है। किम यो-जोंग उत्तर कोरियाई सत्तारूढ़ पार्टी की केंद्रीय समिति की उप निदेशक हैं। द कोरिया टाइम्स अखबार की खबर में उत्तर कोरिया की कोरियन सेंट्रल न्यूज एजेंसी (केसीएनए) के हवाले से कहा गया है कि किम यो-जोंग ने यह टिप्पणी गत दिवस विदेश मंत्रालय के महानिदेशकों के साथ एक बैठक में की। किम ने दक्षिण कोरिया और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच चल रहे सैन्य अभ्यासों की भी निंदा की। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति ली इतिहास की दिशा बदलने के काबिल नहीं हैं। किम यो-जोंग ने कहा, हमारे देश को केंद्र में रखकर चल रहे क्षेत्रीय कूटनीतिक मंच में दक्षिण कोरिया को छोटी सी भी भूमिका नहीं दी जाएगी। कोरिया गणराज्य हमारा राजनयिक समकक्ष नहीं हो सकता। किम की यह टिप्पणी लंबे समय से खराब अंतर-कोरियाई संबंधों को सुधारने के लिए सियोल की की गई पहल के बाद आई है।दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्युंग ने पिछले हफ्ते अपने मुक्ति दिवस भाषण में कहा था कि वह उत्तर कोरिया की राजनीतिक व्यवस्था का सम्मान करेंगे और विलय के जरिए एकीकरण की कोशिश नहीं करेंगे। उन्होंने तनाव कम करने के लिए 2018 से निलंबित अंतर-कोरियाई सैन्य समझौते को बहाल करने के लिए कदम उठाने का भी वादा किया था।

अमेरिकी नौसेना का युद्धपोत 12 घंटे तक घिरा रहा आग की लपटों में,दो सदस्य झुलसे

एजेंसी

ओकिनावा (नाहा)। ओकिनावा तट पर लंगर डाले खड़े अमेरिकी नौसेना के युद्धपोत यूएसएस न्यू ऑरलियन्स में 12 घंटे तक आग लगी रही। इससे दो सदस्य झुलस गए। इस जहाज में स्थानीय समयानुसार शाम लगभग चार बजे आग लगी और गुरुवार तड़के बुझा दी गई। अमेरिकी समाचार चैनल की खबर के अनुसार आग बुझाने में मदद करने वाले जापान तटरक्षक बल के एक बयान में कहा गया है कि स्थानीय समयानुसार सुबह 9 बजे के बाद आग बुझाने का काम बंद हुआ। अब यह पता लगाने के लिए जांच चल रही है कि आग पूरी तरह बुझी या नहीं। अमेरिकी नौसेना ने कहा कि उसके दो नाविक सदस्य मामूली रूप से झुलस गए। उनका इलाज पोत पर ही किया गया। यह युद्धपोत जापानी द्वीप के पूर्वी तट पर व्हाइट बीच नौसेना सुविधा केंद्र के पास लंगर डाले हुए था। तभी उसमें आग लग गई। नौसेना ने कहा कि न्यू ऑरलियन्स के चालक दल को यूएसएस सैन डिएगो के चालक दल

ने अग्निशमन प्रयासों में सहायता प्रदान की। जापान तटरक्षक बल, जापान समुद्री आत्मरक्षा बल और ओकिनावा स्थित अन्य अमेरिकी नौसेना कमांडों ने आग बुझाने में मदद की। अमेरिकी नौसेना के पूर्व कैप्टन और विश्लेषक कार्ल शूस्टर ने कहा कि युद्धपोतों में आग लगने का हमेशा खतरा बना रहता है, क्योंकि इनमें ज्वलनशील पदार्थों की भरमार होती है। हाल के वर्षों में अमेरिकी नौसेना के जहाज यूएसएस बोनहोम रिचर्ड में सबसे भीषण आग जुलाई, 2020 में लगी थी। वह सैन डिएगो के बंदरगाह पर एफ-35 लड़ाकू विमानों को ले जाने के लिए अपग्रेडेशन के दौर से गुजर रहा था। यह जहाज चार दिन तक आग की लपटों से घिरा रहा था। परिणामस्वरूप नौसेना को अरबों डॉलर के इस युद्धपोत को कबाड़ में डालना पड़ा।

भारत-चीन के बीच हुए समझौते से परेशान हुआ नेपाल, डिप्लोमैटिक नोट भेजने की तैयारी

एजेंसी

काठमांडू। भारत और चीन के विदेश मंत्रियों के बीच हुए समझौते के एक बिंदु को लेकर नेपाल परेशान हो उठा है। भारत के जिस भू-भाग को नेपाल अपना होने का दावा करता है, उस भू-भाग को लेकर भारत और चीन ने समझौता कर लिया। इससे नाराज नेपाल ने अपने दोनों पड़ोसी देशों को अपनी नाराजगी व्यक्त करने के लिए डिप्लोमैटिक नोट भेजने की तैयारी कर रहा है। भारत और चीन के विदेश मंत्रियों के बीच हुए समझौते में रहे 9 नंबर की सहमति से नेपाल सरकार नाराज है और इसका विरोध करते हुए दोनों देशों को डिप्लोमैटिक नोट भेजने की तैयारी कर रही है, इसके लिए विदेश मंत्रालय में आपात बैठक बुलाई गई है। इस बैठक के बाद विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता की तरफ से बयान जारी करते हुए भारत-चीन के बीच हुए समझौते का विरोध किया गया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लोक बहादुर पौडेल ने कहा कि भारत और चीन के बीच हुए समझौते के 9 नंबर में भारत और चीन के बीच व्यापारिक दृष्टि से जिस लिपुलेक पास का जिक्र

किया गया, वह नेपाल का अभिन्न अंग है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता का कहना है कि लिपुलेक को लेकर नेपाल अपनी स्थिति पहले ही स्पष्ट कर चुका है। इस बयान में कहा गया है कि लिपुलेक के आसपास कोई भी निर्माण कार्य नहीं करने के लिए भारत से आग्रह किया जा चुका है। नेपाल ने दावा किया है कि लिपुलेक और लिंपियाधुरा को लेकर उसने चीन को आधिकारिक जानकारी भी साझा की है। नेपाल ने चीन को अपने नए नक्शे को मान्यता देने के लिए कई बार पत्राचार किए जाने की जानकारी दी। एकबार फिर से नेपाल ने चीन से आग्रह किया है कि वह नेपाल के अभिन्न अंग को लेकर किसी तीसरे देश के साथ कोई समझौता न करे। नेपाल भारत के लिपुलेक और लिंपियाधुरा पर अपना दावा करता रहा है। वर्ष 2021 में जब तत्कालीन प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की सरकार ने भारत के लिपुलेक और लिंपियाधुरा पर अपना दावा करते हुए नक्शा जारी कर दिया था। इतना ही नहीं उस समय ओली सरकार ने संसद में इस नक्शे को सरकारी प्रयोजन में लाने के लिए संविधान संशोधन तक किया था। इस बात को लेकर दोनों देशों के बीच कई महीनों तक कूटनीतिक विवाद चलता रहा।

इजराइल गाजा शहर पर हमले को तैयार, सैनिकों का बाहरी इलाके में जमावड़ा

एजेंसी

काठमांडू। तेल अवीव (इजराइल), 21 अगस्त (हि.स.)। इजराइल गाजा शहर पर हमले के लिए तैयार है। इजराइली सुरक्षा बलों (आईडीएफ) के सैनिक बाहरी इलाके में पहंच चुके हैं। इजराइली अधिकारियों ने कल कहा कि सेना गाजा शहर पर कब्जा करने की योजना पर आगे बढ़ रही है। लगभग दो साल के युद्ध के बाद भी शहर और उसके आसपास के इलाके आतंकवादी समूह हमास का गढ़ बने हुए हैं। द न्यूयॉर्क टाइम्स ने इजराइल के एक वरिष्ठ सैन्य अधिकारी के हवाले से कहा कि सैनिक शहर के बाहरी इलाके में पहुंच चुके हैं। सैन्य अभियान शुरू होने के बाद विस्थापित होने वाले लोगों के लिए दक्षिणी गाजा में तंबू लगाए जा रहे हैं। योजना में शहर को घेरने, आबादी को आतंकवादियों से मुक्त कराने, हमास लड़ाकों को पकड़ने के लिए सैनिक चौकियों से होते हुए दक्षिण की ओर बलपूर्वक बढ़ेंगे। गाजा शहर में भेजे गए सैनिकों की मदद के लिए लगभग

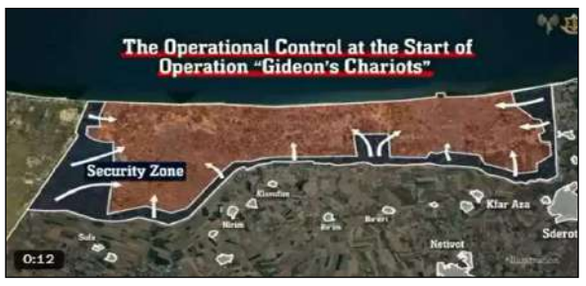

60,000 आरक्षित सैनिकों को तैयार रखा गया है। इस समय 20,000 सैनिकों को आगे बढ़ने का आदेश दिया गया है। यह तैयारी तब शुरू हुई जब प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने हमास के युद्धविराम प्रस्ताव पर सहमत होने पर विचार किया है। इजराइल में बंधकों के परिवार चिंतित हैं। परिवारों का मानना है कि हमास हमले के जवाब में उन्हें मार डालेगा। इस बीच कट्टर दक्षिणपंथी नेताओं ने धमकी दी है कि अगर नेतन्याहू युद्धविराम प्रस्ताव को स्वीकार करते हैं तो वे सरकार छोड़ देंगे। इस बीच आईडीएफ ने एक्स पोस्ट में सैन्य तैयारी की पुष्टि की है। आईडीएफ ने कहा कि सैनिकों ने गाजा के लगभग 75 फीसद से अधिक हिस्से पर परिचालन नियंत्रण कर लिया है। हमास के आतंकवादी बुनियादी ढांचे पर प्रहार कर उसकी कमान शक्ति को कमजोर कर दिया गया है।आईडीएफ अपने अभियान को विस्तार देने के लिए पूरी तरह तैयार है। एनबीसी न्यूज चैनल के अनुसार, इजराइल ने गाजा शहर पर पूर्ण नियंत्रण पाने के लिए हजारों रिजर्व सैनिकों को भेजा है। सैनिकों ने शहर के बाहरी इलाके में रह रहे लगभग दस लाख लोगों को दक्षिण की ओर धकेलना शुरू कर दिया है। यह सब ऐसे समय में हो रहा है जब फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम और कनाडा सहित अमेरिका के कुछ सबसे करीबी सहयोगियों ने कहा है कि वे उन 145 से अधिक देशों में शामिल हो सकते हैं जो फिलिस्तीनी राज्य को मान्यता देते हैं।

दक्षिण कोरिया की पूर्व प्रथम महिला किम की हिरासत अवधि अदालत ने 31 अगस्त तक बढ़ाई

एजेंसी

सियोल (दक्षिण कोरिया)। दक्षिण कोरिया की एक अदालत ने आज देश के पूर्व राष्ट्रपति यून सुक येओल की पत्नी किम कियोन ही की हिरासत अवधि 31 अगस्त तक के लिए बढ़ा दी। विशेष वकीलों की टीम किम से आरोपों के बारे में तीसरी बार गुरुवार को पूछताछ करेगी। देश की पूर्व प्रथम महिला किम को 13 अगस्त को गंभीर आरोपों में गिरफ्तार किया गया था। उनके पति पहले से ही मार्शल लॉ की अल्पकालिक घोषणा के कारण गिरफ्तार किए जा चुके हैं। द कोरिया टाइम्स अखबार की खबर के अनुसार विशेष वकील मिन जोंग-की ने बताया कि पूर्व प्रथम महिला किम कियोन ही की हिरासत अवधि 10 दिन के लिए बढ़ा दी गई है। एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया कि मंगलवार को एक अदालत ने किम की हिरासत अवधि 31 अगस्त तक बढ़ाने का फैसला किया। उनकी हिरासत अवधि गुरुवार को समाप्त होने वाली थी। उन्हें मार्शल लॉ के बाद मचे बवाल के बाद लंबी संवैधानिक और कानूनी प्रक्रिया के बाद गिरफ्तार किया गया था। अदालत के आदेश के बाद उनकी गिरफ्तारी शेयर बाजार में हेराफेरी की योजना में शामिल होने, 2022 के संसदीय उपचुनाव और 2024 के आम चुनाव में उम्मीदवारों के नामांकन में दखलंदाजी करने और व्यावसायिक लाभ के बदले एक ओझा के माध्यम से यूनिफिकेशन चर्च से आलीशान उपहार प्राप्त करने के आरोपों में की गई है। उन्हें पश्चिमी सियोल के गुरो-गु स्थित सियोल दक्षिणी हिरासत केंद्र में रखा गया है। यहां उनके पति पहले से ही हिरासत में हैं। अदालत के आदेश पर गिरफ्तार होने वाली वह देश की पूर्व प्रथम महिला हैं।

ट्रंप को निक्की हेली की नसीहत-भारत के साथ दुश्मन जैसा व्यवहार रणनीतिक गलती होगी

एजेंसी

वॉशिंगटन। संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका की पूर्व राजदूत निक्की हेली ने ट्रंप को नसीहत देते हुए कहा है कि भारत को मूल्यवान और लोकतांत्रिक साझीदार' मानना चाहिए। भारत के साथ रिश्ते को बिगाड़ना एक रणनीतिक आपदा होगी। अगर अमेरिका चीन की बढ़ती महत्वाकांक्षाओं पर लगाम लगाना चाहता है तो उसे भारत के साथ संबंधों को प्राथमिकता देनी होगी। न्यूजवीक में प्रकाशित अपने लेख में हेली ने लिखा कि अमेरिका को इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए कि उसका लक्ष्य चीन है और उसका सामना करने के लिए अमेरिका के पास भारत के रूप में एक दोस्त होना चाहिए। भारत एक लोकतांत्रिक देश है और उसका उदय दुनिया के लिए खतरा नहीं है लेकिन चीन की ताकत बढ़ना दुनिया के लिए चुनौती है क्योंकि वह कम्युनिस्ट शासन के

तहत चलता है। हेली का कहना है कि एशिया में चीन के प्रभुत्व का मुकाबला करने वाला भारत इकलौता देश है। हेली ने लिखा कि भारत में चीन की तरह बड़े पैमाने पर उत्पादन क्षमता है, जो अमेरिका को चीन के बजाए भारत के जरिए अपनी सप्लाई चेन की डिमांड को पूरा करने में मदद पहुंचा सकती है। भारत के साथ दुश्मन जैसा व्यवहार रणनीतिक गलती होगी। भारत की बढ़ती रक्षा क्षमता और मध्य पूर्व में उसकी भूमिका उस क्षेत्र में स्थिरता लाने में अहम साबित हो सकती है। वैश्विक नजरिये से भारत के महत्व को रेखांकित करने वाला हेली का आलेख उस समय आया है जब अमेरिका-भारत के बीच व्यापार विवाद चरम पर है और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 25 प्रतिशत पारस्परिक शुल्क और 25 प्रतिशत अतिरिक्त टैरिफ लगा दिया है, जो 27 अगस्त से लागू होगा। हेली ने कहा कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्था है। भारत का उदय चीन की वैश्विक व्यवस्था पर प्रभुत्व की उसकी महत्वाकांक्षा को रोक देगा। जैसे-जैसे भारत मजबूत होगा, चीन की महत्वाकांक्षाएं कमजोर होंगी। अमेरिका और भारत की साझेदारी से दोनों देशों के हित पूरे होंगे और भारत चीन के खिलाफ ज्यादा मजबूती से खड़ा हो सकेगा। लेकिन अमेरिका-भारत के बीच व्यापार विवाद लंबा खिंचा तो चीन इस स्थिति का फायदा उठा सकता है।

रूस ने यूक्रेनी विध्वंसक समूह के तीन सदस्यों को मार गिराने और तीन को दबोचने का दावा किया

एजेंसी

मॉस्को (रूस)। रूस की संघीय सुरक्षा सेवा (एफएसबी) ने दावा किया कि उसके एजेंटों ने पश्चिमी ब्रांस्क क्षेत्र में यूक्रेनी विध्वंसक समूह के तीन सदस्यों को मार गिराया। साथ ही तीन को गिरफ्तार कर लिया। एफएसबी का दावा है कि यह सभी रूस के अंदर आतंकवादी हमलों में शामिल थे। एफएसबी की वेबसाइट के मुताबिक, एक सुरक्षा अभियान के दौरान यह सफलता मिली है। रूस की सरकारी समाचार एजेंसियों के साझा किए गए एक वीडियो में तीन लोग एक जंगली इलाके में जमीन पर पड़े दिखाई दे रहे हैं। यह लोग खुद को यूक्रेन के विशेष अभियान बलों से जुड़ी एक इकाई का सदस्य बता रहे हैं। एफएसबी एजेंट तीन शवों के पास खड़े हैं। वहां हथियारों का जखीरा बिखरा हुआ है। रूसी खुफिया एजेंसी ने दावा किया कि मौके से अमेरिका निर्मित असॉल्ट राइफलें, चेक गणराज्य के विस्फोटक और बड़ी संख्या में नाटो-मानक ग्रेनेड और गोला-बारूद जब्त किया गया है। गिरफ्तार किए गए लोगों में से एक ने खुद को समूह का कमांडर और नाम ओलेक्सांद्र झुक बताया। एफएसबी का दावा है कि इस व्यक्ति ने स्वीकार किया कि समूह को ब्रिटिश, कनाडाई और अन्य यूरोपीय प्रशिक्षकों ने प्रशिक्षित किया। एफएसबी ने आरोप लगाया कि इस समूह को यूक्रेन के साथ-साथ नाटो देशों लिथुआनिया, एस्टोनिया और नॉर्वे में पश्चिमी खुफिया कर्मियों की मौजूदगी में प्रशिक्षित किया गया। झुक ने यह भी स्वीकार किया कि उन लोगों को यूक्रेन की सैन्य खुफिया एजेंसी एचयूआर ने इस महीने की शुरुआत में ब्रांस्क क्षेत्र में प्रमुख रूसी परिवहन स्थलों पर हमले करने के लिए तैनात किया था। एफएसबी ने दावा किया कि मौके से जब्त किया गया एक रेडियो स्टेशन कीव स्थित एचयूआर मुख्यालय के साथ संचार के लिए था। द मॉस्को टाइम्स अखबार के अनुसार, यह स्पष्ट नहीं है कि उस व्यक्ति (झुक) ने दबाव में बात की या नहीं, लेकिन उसने जिस औपचारिक भाषा का इस्तेमाल किया, उससे पता चलता है कि उसका कबूलनामा कम से कम पहले से तैयार किया गया होगा। एफएसबी के दावों की तुरंत पुष्टि करना भी संभव नहीं है। झुक ने यह भी कहा कि यूक्रेनी विशेष बल समूह मई में ब्रांस्क क्षेत्र के एक पुल पर हुए विस्फोट और पिछले सितंबर में बेलगोरोड क्षेत्र में एक मालगाड़ी के पटरी से उतरने की घटना में शामिल था।

इस्लामाबाद में दर्ज 567 यौन शोषण के मामलों में 93 लड़के और 108 लड़कियां पीड़ित

एजेंसी

इस्लामाबाद (पाकिस्तान)। पाकिस्तान के आंतरिक मंत्रालय ने मंगलवार को खुलासा किया कि जनवरी, 2021 से जून, 2025 के बीच इस्लामाबाद में दर्ज 567 यौन शोषण के मामलों में 201 बच्चों से जुड़े थे। सीनेटर शहादत अवान को लिखित जवाब में मंत्रालय ने बताया कि पीड़ितों में 93 लड़के और 108 लड़कियां थीं।

द इंटरनेशनल न्यूज अखबार की खबर के अनुसार मंत्रालय ने लिखिति जवाब में कहा कि इन मामलों में कुल 222 आरोपितों को गिरफ्तार किया गया। अब तक केवल 12 को ही दोषी ठहराया गया है, जबकि 163 पर अभी भी मुकदमा चल रहा है। 15 को बरी कर दिया गया है और 26 अभी भी फरार हैं। गृहमंत्री मोहसिन नकवी ने सदन को सूचित किया कि जोनल पुलिस अधीक्षक के माध्यम से इस्लामाबाद के सभी पुलिस थानों से प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार, 1 जनवरी 2021 से 20 जून 2025 की अवधि के दौरान दुष्कर्म के कुल 567 मामले दर्ज किए गए और 625 आरोपितों को गिरफ्तार किया गया। उन्होंने बताया कि 567 मामलों में से 485 में चालान पेश किया गया, 80 आरोपितों को दोषी ठहराया गया। 23 को बरी कर दिया गया और 406 मामलों में आरोपित अभी भी सक्षम अदालतों में मुकदमे का सामना कर रहे हैं।

पाकिस्तान ने अफगानिस्तान से टीटीपी और बीएलए के खिलाफ निर्णायक कदम उठाने का आग्रह किया

एजेंसी

काबुल (अफगानिस्तान)। पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ने यहां अफगानिस्तान की तालिबान हुकूमत से प्रतिबंधित तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी) और बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी (बीएलए) के खिलाफ निर्णायक कदम उठाने का आग्रह किया। इस दौरान पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चीन ने आतंकवाद के खिलाफ संयुक्त प्रयासों को मजबूत करने का संकल्प लिया। पाकिस्तान के अखबार द एक्सप्रेस ट्रिब्यून की खबर के अनुसार चीन के विदेश मंत्री वांग यी और पाकिस्तान के विदेश मंत्री त्रिपक्षीय बैठक में भाग लेने के लिए कल काबुल पहुंचे। तालिबान के अफगानिस्तान पर फिर से कब्जा करने के बाद से वांग यी की यह पहली काबुल यात्रा रही। डार और वांग ने त्रिपक्षीय बैठक से इतर अफगान अधिकारियों के साथ अलग-अलग द्विपक्षीय वार्ता की। चीन के विदेश मंत्री ने अफगानिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री मुल्ला अखुंद से कहा कि उन्हें उम्मीद है कि तालिबान सरकार बीजिंग की सुरक्षा चिंताओं पर गौर करेगी। अफगानिस्तान के कार्यवाहक विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी के साथ मुलाकात में पाकिस्तान के विदेश मंत्री डार ने अफगानिस्तान की धरती पर टीटीपी, बीएलए और मजीद ब्रिगेड की मौजूदगी का मुद्दा उठाया। इस्लामाबाद स्थित विदेश कार्यालय

के बयान में कहा गया कि विदेश मंत्री ने अफगानिस्तान में सक्रिय आतंकी समूहों के पाकिस्तान के अंदर हाल ही में किए गए आतंकवादी हमलों में वृद्धि पर चिंता जताई और अफगान अधिकारियों से टीटीपी, बीएलए और मजीद के खिलाफ ठोस कदम उठाने का आग्रह किया। बयान के अनुसार, अफगानिस्तान ने प्रतिबद्धता दोहराई कि उसके क्षेत्र का इस्तेमाल कोई भी आतंकवादी समूह पाकिस्तान या अन्य देशों के खिलाफ नहीं करेगा। विदेश मंत्री ने सुरक्षा समस्या पर चिंता व्यक्त की, लेकिन दोनों मंत्रियों ने अपने देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों की सकारात्मक प्रगति पर संतोष व्यक्त किया। बाद में डार अपने चीनी और अफगान समकक्षों के साथ राजनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा सहयोग पर केंद्रित त्रिपक्षीय बैठक में शामिल हुए। अफगानिस्तान में पाकिस्तान के विशेष प्रतिनिधि ने 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा कि पाकिस्तान, चीन और अफगानिस्तान टीटीपी, बीएलए और सहित अन्य आतंकवादी समूहों के खिलाफ संयुक्त प्रयास करने पर सहमत हुए हैं। अफगान विदेश मंत्री मुत्ताकी ने कहा कि अफगानिस्तान के इस्लामी अमीरात ने अर्थव्यवस्था को अपनी विदेश नीति का केंद्रीय स्तंभ बनाया है और अफगानिस्तान को केवल सुरक्षा चुनौतियों के चश्मे से देखने वाले देश से क्षेत्रीय आर्थिक गतिविधियों के केंद्र में बदलने के प्रयास जारी हैं। चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने कहा कि अफगानिस्तान के साथ चीन के संबंध समय के साथ और मजबूत होते जा रहे हैं। डार ने आशा व्यक्त की कि तीनों देशों के बीच आर्थिक और व्यापारिक सहयोग और गहरा होगा।

सब्जी उत्पादन और आधुनिक बागवानी में पालीहाउस का महत्वपूर्ण योगदान

By : Bhupender

सब्जी उत्पादन और आधुनिक बागवानी में पॉलीहाउस का महत्वपूर्ण योगदान है। यदि किसान कुछ विशेष सावधानियों को ध्यान में रखें तो इसमें बेमौसमी सब्जियों की खेती एक वरदान के रूप में सिद्ध हो सकती है। पॉलीहाउस में आमतौर पर सभी सब्जियों को उगाया जा सकता है, किन्तु सब्जियों का चयन पौधों की ऊंचाई, मौसम, सब्जी तैयार होने का समय, उत्पादन लागत एवं बाजार भाव को ध्यान में रखकर करना चाहिए।

इसके लिए ज्यादातर उन सब्जियों को चुनें जो कम जगह घेरती हों और उनका बाजार भाव ज्यादा मिलता हो। पॉलीहाउस में उगाने के लिये निम्न सब्जियां उपयुक्त रहती हैं, जैसे- शिमला मिर्च, टमाटर, खीरा, खरबूजा, लौकी, गोभी, बैंगन, फ्रेंचबीन, करेला, चप्पनकद्दू और तरबूज आदि प्रमुख है।

पॉलीहाउस बनाने की विधि

ढांचे की बनावट के आधार पर पॉलीहाउस कई प्रकार के होते हैं। पॉलीहाउस बनाने के लिये बांस की खपच्ची, बांस, जी आई पाइप, आयरन एंगल, सुतली आदि का प्रयोग ढांचा बनाने के लिये किया जाता है और इसे 150 से 200 माइक्रोन मोटी पॉलीथीन से ढंका जाता है। पॉलीथीन शीट का पराबैंगनी होना जरूरी होता है। सूर्य का प्रकाश पारदर्शी पॉलीथीन से पॉलीहाउस के अन्दर पहुंचता है, किन्तु विकिरण से पुन: वायुमण्डल में प्रवेश न कर पाने के कारण वह पॉलीहाउस का तापमान बढ़ाने में सहायक होता है। किसानों के लिये कम लागत के पॉलीहाउस उपयुक्त होते हैं और विभिन्न राज्यों की सरकारों द्वारा इन पर बागवानी मिशन के तहत 50 तक प्रतिशत अनुदान दिया जाता है।

कम लागत के पॉलीहाउस- इस प्रकार के ग्रीन हाउस का ढांचा बांस की खपच्चियों तथा सुतली की सहायता से बनाया जाता है। इस प्रकार के पॉलीहाउस में कोई भी यंत्र वातावरण का नियंत्रण करने के लिये नहीं लगाया जाता एवं ऐसे पॉलीहाउस मैदानी क्षेत्रों के लिये सर्दी की ऋतु में प्रयोग किये जा सकते हैं।

मध्यम लागत के पॉलीहाउस- इस प्रकार के ग्रीन हाउस का ढांचा प्राय: लोहे के पाइप या जी आई पाइप द्वारा बनाया जाता है। इसमें कूलर, छाया देने वाले जाल, पानी के फव्वारे तथा गर्म हवा फेंकने वाले ब्लोअर का इस्तेमाल होता है। इस में वातावरण को अर्धनियंत्रित किया जा सकता है।

अधिक लागत के आधुनिक पॉलीहाउस- ये ग्रीन हाउस मध्यम लागत वाले पॉलीहाउस से काफी बड़े आकार के होते हैं। इसमें वातावरण का नियंत्रण आधुनिक यंत्रों द्वारा किया जाता है, जिसको कम्पयूटर प्रणाली द्वारा संचालित किया जाता है और सिंचाई ड्रिप प्रणाली द्वारा की जाती है।

पॉलीहाउस तकनीक के उपयोग

1. विपरीत मौसम यानी बेमौसमी सब्जियों की नर्सरी तैयार की जा सकती है तथा कम समय में नर्सरी तैयार होती है।
2. ये संरचनाएं सब्जियों को ठण्ड, पाला, गर्मी और हवा से बचाती हैं।
3. सब्जियों की अगेती पौध तैयार करने में सहायक जिससे अगेती फसल लेकर ज्यादा भाव में बाजार में बेचा जा सकता है।
4. अधिक मूल्य वाली सब्जियों का उत्पादन करना संभव।
5. बेमौसमी सब्जी उत्पादन- खीरा, शिमला मिर्च, टमाटर का वर्ष भर उत्पादन किया जा सकता है।
6. सब्जियों के उत्पादन और उत्पादकता में बढोतरी संभव।
I. सब्जियों की गुणवत्ता बढ़ती है।
8. कीड़ों और बीमारियों की रोकथाम आसानी से की जा सकती है।
9. सब्जियों की मोनोक्रापिंग को बढ़ाना यानी साल में कई बार फसल उगा सकते है, जिससे क्रापिंग इन्टेंसिटी बढ़ती है।

पॉलीहाउस में सब्जी उत्पादन के लिए सब्जियों की उन्नत किस्में =

टमाटर- पंत टी- 3, डी टी एच- I, अविनाश- 2, डी ए आर एल- 304, एच वाई बी- 99, के-126, एन पी- 5002 और नवीन प्रमुख है।

शिमला मिर्च- केलिफोर्निया वंडर, अलंकार, भारत इन्दिरा, गोल्डन समर, हीरा, बाम्बी, ओरोबेली, तनवी और जैमिनी आदि प्रमुख है।

खीरा- जापानीज लौंग, ग्रीन, पूसा संयोग, प्वाइनसेट, रानी, फूले पराची और कसन आदि प्रमुख है।

खरबूजा- पंजाब संकर- 1और दिप्ती आदि।

फ्रेंचबीन- पंत अनुपमा और पंतबीन- 2, पूसा पार्वती कंटेण्डर आदि प्रमुख है।

करेला- पूसा दौ मौसमी और पूसा विशेष आदि प्रमुख है।

बैंगन- पूसा हाईब्रिड- 5,6 और 9, पंत संकर, हिसार और श्यामल आदि प्रमुख है।

पॉलीहाउस में पौध तैयार करना = ग्रीन हाउस या पॉलीहाउस में सब्जियों की नर्सरी का विकास तेजी से होता है। इसमें सब्जियों की विपरीत मौसम में नर्सरी तैयार करके किसान अधिक लाभ ले सकते हैं। इसमें कम लागत वाले पॉलीहाउस में सब्जियों की नर्सरी जैसे- शिमला मिर्च, टमाटर, बैंगन और बेलवाली सब्जियां जैसे- खीरा, लौकी, करेला, तोरई, चप्पन कद्दू एवं ककड़ी इत्यादि, की बेमौसमी अर्थात सर्दी में नर्सरी पौध तैयार करके एक दो महीने अगेती फसल ली जा सकती है, जिसके बाजार में बहुत अच्छे दाम मिलते हैं। इसके लिये बांस की खपच्ची, पोलीथीन शीट, सुतली से एक झोपड़ीनुमा ग्रीन हाउस बनाया जा सकता है और इसमें सब्जियों की पौध दिसम्बर से जनवरी में तैयार की जा सकती है।

अगेती नर्सरी (पौध) से फायदे

1. अधिक पैदावार
2. बेमौसमी उत्पादन
3. अच्छी गुणवत्ता
4. कम पानी की आवश्यकता
5. कम खरपतवार व आसान नियंत्रण
6. स्वस्थ व समय पर पौध उत्पादन
I. विपरीत परिस्थितियों से बचाव
8. कीट व रोग नियंत्रण आसान।

इन बातों का रखें ध्यान =

1. केवल उन्नत और संकर किस्में ही उगाएँ।
2. सही सब्जी की फसल और सही किस्म का चयन।
3. सब्जी की बिजाई से पहले पॉलीहाउस में गोबर की खाद डालकर अच्छी तरह मिला दें तथा जमीन को पांच प्रतिशत फोरमेलिन से उपचारित करें।
4. शिमला मिर्च, टमाटर, खीरा आदि ज्यादा लाभदायक फसलें होती हैं।

पौध को प्रोपेगेशन ट्रे में तैयार करें

सब्जियों की पौध के लिये प्रोपेगेशन ट्रे जिसे प्रो ट्रे भी कहते हैं, का इस्तेमाल करें जो आमतौर पर 98 छेदों वाली होती है, इसमें कोकोपीट + परलेट + वर्मीकुलेट का 4:1:1 का मिश्रण लेकर ट्रे तैयार कर लें तथा बीज की बिजाई कर दें।

पॉलीहाउस के फायदे

1. प्रत्येक बीज का बिना क्षति के अंकुरण।
2. जड़ों का पूरा विकास एवं निकालने एवं रोपाई में सुविधाजनक।
3. पौधों का विकास एक समान और स्वस्थ पौधों का तैयार होना
4. कम समय में पौध का तैयार होना।
5. पौध की बीमारियां कम।
6. कीट नियंत्रण सरलता से किया जा सकता है।
I. रोपाई उपरान्त कम मृत्युदर और पौधों का विकास जल्दी होना।
8. पॉलीहाउस को बागवानी के व्यावसायीकरण ने किसानों की एक खास जरूरत बना दिया है, जिसमें बेमौसमी सब्जियां उगाकर आमदनी को कई गुणा बढ़ाया जा सकता है।
9. परम्परागत कृषि विधियों की अपेक्षा पॉलीहाउस में सब्जियों को उगाने से खुले वातावरण की तुलना में दो से चार गुणा तक अधिक पैदावार ली जा सकती है।
10. वर्ष भर सब्जी उत्पादन करना, साथ ही उत्पादन की मात्रा, गुणवत्ता तथा उत्पादकता में भी काफी बढ़ोतरी प्राप्त की जा सकती है।
11. पॉलीहाउस में पर-परागण वाली सब्जियों के बीजों को सरलता से तैयार किया जा सकता है, इस प्रकार तैयार किए गए बीजों में वंश शुद्धता बनाये रखी जा सकती है और यह बीज उच्च गुणवत्ता के होते हैं। पॉलीहाउस के अन्दर उगाई जाने वाली सब्जियों में वे सभी सस्य क्रियायें करनी पडती हैं, जिन्हां खुले खेत में करते हैं।

वृक्षों और वनों का संरक्षण

मार्गों पर वृक्ष लगाने की परम्परा भारत में प्राचीन काल से ही चली आ रही है। भारतीय जन-मानस ने वनों व वृक्षों का महत्व हजारों वर्ष पूर्व ही समझ लिया था। सम्पूर्ण विश्व में आज वृक्षों और वनों के संरक्षण की बात हो रही है परंतु हम भारतीय तो प्राचीन काल से ही इनके महत्व को समझते थे। वृक्षों के महत्व को प्रत्यक्ष-परोक्ष रूप से सामान्य जन को समझाने के लिये या तो उन्हें देवी-देवताओं से सम्बंधित बताया गया था फिर उन्हें किन्हीं अन्य कारणों से पूजनीय बताकर उनके काटने व हानि पहुँचाने को प्रतिबंधित कर दिया गया। इस प्रकार वृक्षों का संरक्षण आसान हो गया। यहाँ तक कि भारतीय वासतुशास्त्र भी कौन सा पेड़ कहाँ और किस दिशा में लगाया जाए, इस विषय में विस्तृत विवरण देता है, जो अंधविश्वास पर नहीं, वैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित होता है। मार्गों में कौन से वृक्ष कहाँ और कैसे लगाये जायें, इसका निर्णय भी हमारे प्राचीन ग्रंथ संदर्भों से लेकर आज के वैज्ञानिक शोधों तक वृक्षों के आकार, प्रकार, मजबूती, सघनता, जीवनकाल एवं उपयोगिता को आधार बनाकर ही किया जाता है।

आज बढ़ती हुई जनसंख्या, शहरीकरण, औद्योगिकीकरण के कारण वनों का तीव्रता से क्षय हुआ है। हम जहाँ एक ओर वनों की पुर्नस्थापना के प्रयास कर रहे हैं वहीं दूसरी ओर हम नगरों, महानगरों, राजमार्गों पर हरित-पट्टियां लगाकर प्राकृतिक वन संपदा व जैव विविधता संरक्षण के प्रयास भी कर रहे हैं। भारत तीव्र गति से प्रगति करता हुआ राष्ट्र है जहाँ पुराने राजमार्गों के पुनरुद्धार के साथ-साथ नये बसते हुए क्षेत्रों में हजारों किलोमीटर राजमार्ग बनाये जा रहे हैं। नवीन नगरीय व औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना के साथ संपर्क मार्गों, नगरीय मार्गों व राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण हेतु हजारों वृक्षों और कृषि उपयोगी भूमि को नष्ट करके कंक्रीट के जंगलों में बदला जा रहा है। ऐसे में यह आवश्यक हो जाता है कि योजनाबद्ध विधि से कम से कम राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे वृक्ष लगाकर कुछ सीमा तक प्राकृतिक वृक्ष/ वन असंतुलन को कम किया जा सके। वृहद सड़क जाल में, भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। वनस्पति विविधता के दृष्टिकोण से भी भारत बहुत संपन्न देश है। सड़कों के किनारे लगे वृक्षों का भी वनस्पति विविधता संरक्षण में महत्त्वपूर्ण योगदान है। राजगामार्गों के किनारे के ये वृक्ष जहाँ एक ओर राजमार्गों को सुरक्षा प्रदान करते हैं वही दूसरी ओर ये वृक्ष मार्गों पर चलने वालों को छाया व सुखद अनुभूति देते हैं एवं वाहनों से निकले प्रदूषण को भी नष्ट करता है।

राजमार्गों पर वृक्ष लगाने की परम्परा अति प्राचीन है। वेदों में भी वृक्षों के महत्व का विस्तृत विवरण है। सम्राट अशोक भी उन सम्राटों में एक थे, जिन्होंने राजमार्गों पर वृक्ष लगाये व आश्रय बनवाये थे। मुगलकाल में अकबर ने राजमार्गों पर वृक्ष लगवाये, आज भी दिल्ली और आस-पास के क्षेत्रों में मार्गों पर प्राचीन वृक्ष बहुतायत में मिल जाते हैं। प्राचीन भारत के लोग मार्गों पर वृक्ष लगाने के महत्व को अच्छी तरह समझते थे और योजनाबद्ध तरीके से मार्गों पर वृक्षों को लगाते थे। कश्मीर, हिमालयी क्षेत्र, उपहिमायली क्षेत्र आसाम, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, दक्षिण भारतीय प्रदेशों में राज मार्गों पर बहुत ही सुनियोजित ढंग से लगे वृक्षों की कतारें अभी भी देखने को मिल जाती हैं। झेलम नदी के किनारे चिनार के वृक्षों की कतारें बहुत सुंदर रूप से लगी हैं। दिल्ली से आगरा जाने वाले राजमार्ग, लाहौर से कलकत्ता तक जाने वाली ग्रैण्ड ट्रंक रोड, दक्षिण भारत के अधिकांश राजमार्गों पर कहीं-कहीं क्रमबद्ध तरीके से लगी समान वृक्षों की सुंदर पंक्तियां दिखाई पड़ जाती हैं। अवध के नवाबों ने लखनऊ और आस-पास के क्षेत्रों में बहुत ही नियोजित ढंग से वृक्षारोपण कराया था। लखनऊ से कानपुर, शाहजहाँपुर, सीतापुर, अयोध्या, सुल्तानपुर और इलाहाबद जाने वाले आठों दिशाओं में फैले राजमार्गों पर इमली, पीपल, आम, जामुन, बरगद, गूलर आदि वृक्षों की समान सुंदर कतारें लगी हुई थीं। अभी हाल के कुछ वर्षों के सुंदरीकरण और सड़कें चौड़ी करने हेतु हजारों सुंदर सघन सैकड़ों साल पुराने वृक्षों की बलि दे दी गई।

राष्ट्रीय राजमार्गों पर सुनियोजित रूप से लगे वृक्ष जहाँ एक ओर लंबी यात्रा को सुखद बनाते हैं वहीं दूसरी ओर यह वृक्ष वन-संपदा, जैव विविधता एवं पर्यावरण का संरक्षण करते हैं तथा वातावरण को भी शुद्ध करते हैं। इसके अतिरिक्त वृक्ष का प्रत्येक भाग उपयोगी होने के कारण आर्थिक दृष्टि से भी लाभदायक होते हैं। आज के परिदृश्य में जहाँ चारों ओर मानव आधुनिकीकरण की ओर अग्रसर हो रहा है और वन, वृक्षों, पेड़-पौधों व कृषि योग्य भूमि को उजाड़ कर उद्योगों, आवासीय क्षेत्रों व मार्गों का निर्माण किया जा रहा है। इस कारण यह तत्काल और प्राथमिक स्तर की आवश्यकता है कि एक योजनाबद्ध विधि से पुन: वृक्षारोपण किया जाए और नये बसते नगरीय क्षेत्रों में यह केवल मार्गों पर ही संभव है। हम नये बने राजमार्गों के किनारे पर तेजी से वृद्धि करने वाले घने छायादार वृक्षों का सुनियोजित रोपण कर सकते हैं। इस योजना को कार्यरूप देने के लिये जलवायु, तापमान, वर्षा आदि के आधार पर उचित वृक्षों का चुनाव कर उनका रोपण करें। भारत एक

अत्यधिक भौगोलिक विविधता वाला देश है अतएव वृक्षारोपण करते समय हमें स्थानीय वातावरण के अनुरूप ही वृक्षों का चयन करना पड़ेगा, क्योंकि हर क्षेत्र में अलग-अलग प्रकार के वृक्ष लगाये जाते हैं।

सन 1937 में श्री मनोहर लाल चतुर्वेदी ने सड़कों पर छायादार वृक्ष लगाने का सुझाव दिया था।

राष्ट्रीय राजमार्गों और नगरीय मार्गों पर अलग-अलग प्रकार के वृक्ष लगाये जाते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग अपेक्षाकृत चौड़े होते हैं अत यहाँ पर ऐसे वृक्ष लगाये जाएं जो आकार में बड़े हों और सघन तथा छायादार हों, साथ ही साथ आर्थिक दृष्टिकोण से भी उपयोगी हों। राज मार्गों पर वृक्ष लगाते समय कुछ बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। जैसे एक कतार में लगे पेड़ एक ही प्रकार के हों जो सड़क के किनारे एक ही आकार व सघनता से वृद्धि करें, उनमें लम्बे और नाटे, सघन या विरल, वृक्ष एक साथ न लगे हों। जबकि नगरीय मार्गों पर लगाये जाने वाले वृक्ष को आकार में छोटा होना चाहिए जिससे कि वृक्ष बढ़ने पर बिजली के तारों से न टकराये और अगर ये पौधे एक ही प्रजाति के फूल वाले वृक्ष हों तो पुष्पन के मौसम में रंगीन फूलों से लदी वृक्षों की कतारें अत्यंत सुंदर प्रतीत होंगी।

नगर के जिन चौड़े मार्गों पर वृक्षों की दो कतारें लगाना संभव हो वहाँ अंदर वाली कतार में छोटे वृक्ष, जैसे गुलमोहर, अमलताश तथा बाहरी कतार में मझोले पौधे, जैसे- जामुन, नीम, महुआ, पाकर, नीम, चमेली इत्यादि लगाये जा सकते हैं।

राष्ट्रीय राजमार्गों पर जहाँ तिराहे चौराहे हो या मार्ग विभाजक कटाव हो, वहाँ छोटे रंगीन फूलों वाले वृक्ष लगाये जा सकते हैं। इससे इन मार्गों पर चलने वाले वाहन चालकों को बड़े वृक्षों की क्रम-बद्धता को विखण्डित करते आकस्मिक रूप से छोटे वृक्ष दिखाई पड़ने से सहज ही तिराहे, चौराहे या मार्ग विभाजक के खुले होने का अनुमान हो जायेगा। इससे दुर्घटनाओं से भी बचा जा सकेगा।

नये बने राष्ट्रीय राजमार्गों और नगरीय मार्गों के मध्य के मार्ग विभाजकों पर छोटे आकार के वृक्ष/ पौधे लगाये जा सकते हैं। सड़क के दोनों ओर लगाये गये वृक्षों का मुख्य उद्देश्य छाया प्रदान करना होता है। इसलिये वृक्षारोपण करते समय ऐसे वृक्षों का चुनाव करना चाहिए जो शीघ्रता से वृद्धि करने वाले हो तथा लम्बे, चौड़े, छत्र आकार वाले वृक्ष हों, जिनकी छाया सड़कों पर भी पड़ती हो।

इस दृष्टि से नीम, महुआ, आम, इमली जैसे- वृक्ष अधिक उपयोगी होते हैं। इन वृक्षों को 12-15 मीटर की दूरी के अंतर पर लगाना चाहिए जिससे उनका छत्र भली-भांति फैल सके।

कुछ वृक्ष, जैसे- यूकेलिप्टस, नीमचमेली, जामुन आदि के वृक्षों की लकड़ी कमजोर होती है अत: इन्हें राजमार्गों के किनारे नहीं लगाना चाहिए, साथ ही साथ कंटीले वृक्ष, जैसे बेर, बबूल को भी मार्गों के निकट नहीं लगाना चाहिए क्योंकि कमजोर पौधे आंधी-पानी में टूट कर मार्ग पर गिर जाते हैं जिससे राजमार्ग अवरुद्ध होंगे, साथ ही साथ वाहन व यात्रियों को भी गंभीर हानि पहुँच सकती है जबकि कटीले पौधें में छाया का भी अभाव होगा और इनसे यात्रियों को भी नुकसान पहुँच सकता है।

मार्ग पर लगाये जा सकने योग्य कुछ महत्त्वपूर्ण पौधों का विवरण व आर्थिक महत्व निम्नवत है

इमली (टमरिन्डस इंडिका)

यह एक सुंदर तथा बड़ा छायादार वृक्ष है जो शुष्क जलवायु में भी आसानी से उग आता है। यह सड़क की धूल, मिट्टी को भी आसानी से सहन कर लेता है। इसकी लकड़ी और फल दोनों ही उपयोगी हैं। लकड़ी का प्रयोग फर्नीचर बनाने में तथा फलों का प्रयोग, मसाले, अचार, चटनी तथा कई प्रकार की भोज्य सामग्री बनाने में होता है।

आम (मैगीफेरा इंडिका)

यह बहुउपयोगी वृक्ष है। इसका प्रत्येक भाग किसी न किसी रूप में उपयोग किया जाता है। इसका फल खाने योग्य है जो पौष्टिक तत्त्वों से भरपूर होता है और आर्थिक दृष्टि से भी लाभदायक है।